



भारत का राजपत्र The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 26] नई दिल्ली, शनिवार, जून 29, 1974/आषाढ़ 8, 1896

No. 26] NEW DELHI, SATURDAY, JUNE 29, 1974/ASADHA 8, 1896

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर)
केंद्रीय प्राधिकारियों द्वारा जारी किये गए सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं

Statutory orders and notifications issued by the Ministries of the Government of India
(other than the Ministry of Defence) by Central Authorities
(other than the Administrations of Union Territories)

मंत्रिमण्डल सचिवालय

(कामिक और प्रशासनिक सुधार विभाग)

नई दिल्ली, 18 जून, 1974

CABINET SECRETARIAT

(Department of Personnel & Administrative Reforms)

New Delhi, the 18th June, 1974

का० प्रा० 1592.—जांच आयोग अधिनियम, 1952 (1952 का 60) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने हुए केन्द्रीय सरकार, भारत के राजपत्र—प्रकाशरण—भाग 2—खण्ड 3—उपखण्ड (ii), दिनांक 16 अक्टूबर, 1971, में प्रकाशित, भारत सरकार, मंत्रिमण्डल सचिवालय (कामिक विभाग) की अधिसूचना संख्या 375/31/71-ए० सी० डी० 3(का० प्रा० 3863), दिनांक 16 अक्टूबर, 1971 में एतद्वारा निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात्:—

उक्त अधिसूचना के पैरा 2 में, '30 जून, 1974 तक' शब्दों, अंकों और अक्षरों के स्थान पर '30 सितम्बर, 1974 तक' शब्द, अंक और अक्षर प्रतिस्थापित किए जायेंगे।

[सं० 381/21/71-ए० सी० डी० 3]

यू० सी० अग्रवाल, संयुक्त सचिव

S.O. 1592.—In exercise of the powers conferred by section 3 of the Commissions of Inquiry Act, 1952 (60 of 1952), the Central Government hereby makes the following further amendment in the notification of the Government of India in the Cabinet Secretariat (Department of Personnel) No. 375/31/71-AVD. III (S.O. 3863), dated the 16th October 1971, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), dated the 16th October, 1971, namely:—

In paragraph 2 of the said notification, for the words, figures and letters "by the 30th June, 1974" the words, figures and letters "by the 30th September 1974" shall be substituted.

[No. 381/21/71-AVD. III]

U. C. AGARWAL, Jt. Secy.

बिधि, न्याय तथा कम्पनी कार्य मंत्रालय

(न्याय विभाग)

नई दिल्ली, 15 जून, 1974

नोटिस

क्रा० प्रा० 1593.—इसके द्वारा, लेख्य प्रमाणक नियम (नोटरीज रूल), 1956 के नियम 6 के अनुसार, सक्षम प्राधिकारी द्वारा सूचना दी जाती है उक्त प्राधिकारी को श्री प्रकाश चन्द जैन, एडवोकेट, 82, खुरबारा, देहरादून ने उक्त नियमों के नियम 4 के अधीन देहरादून में अपने कार्यालय के साथ पश्चिम उत्तराखण्ड (उ० प्र०) की जजशिप में लेख्य प्रमाणक (नोटरीज) का काम करने की नियुक्ति के लिए आवेदन-पत्र भेजा है।

उक्त व्यक्ति की लेख्य प्रमाणक के रूप में नियुक्ति के बारे में यदि कोई आपत्तियाँ हों तो वे इस नोटिस के प्रकाशित होने के चौदह दिन के अन्दर नीचे हस्ताक्षर करने वाले को लिख कर भेज दिये जायें।

[सं० 22/78/73-जस्]

के० त्यागराजन

सक्षम प्राधिकारी तथा उप सचिव

MINISTRY OF LAW, JUSTICE & COMPANY AFFAIRS

(Department of Justice)

New Delhi, the 15th June, 1974

NOTICE

S.O. 1593.—Notice is hereby given by the Competent Authority in pursuance of rule 6 of the Notaries Rules, 1956, that application has been made to the said Authority, under rule 4 of the said Rules, by Shri Prakash Chand Jain, Advocate, 82, Khurbara, Dehra Dun for appointment as a Notary to practice in the Judgeship West Uttar Pradesh (U.P.) with his office at Dehra Dun.

2. Any objection to the appointment of the said person as a Notary may be submitted in writing to the undersigned within fourteen days of the publication of this Notice.

[No. F. 22/78/73-JUS.]

K. THYAGARAJAN, Competent Authority and Dy. Secy.

(बिल मंत्रालय)

राजस्व और बीमा विभाग

आवेश

नई दिल्ली, 13 मार्च, 1974

क्रा० प्रा० 1894.—केन्द्रीय सरकार, धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) की धारा 12क की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित व्यक्तियों को मूल्यांकन अधिकारी के रूप में नियुक्त करती है, अर्थात्:—

क्रम सं०	व्यक्तियों के नाम
1	2
	सर्वे श्री
1.	आर० वेन्काटरामा अय्यर
2.	बी० एस० सेनाद्री
3.	जी० रामेगोवा
4.	ए० बीरुना
5.	सी० गोविन्दन
6.	बी० एन० गुणधन्वा
7.	एम० वेन्काटरामण

1 2

8. आर० ए० एम० गौतम
9. पी० मक्सेना
10. ए० एन० प्रसाद
11. सुरेश कपूर
12. के० एस० यादव ।

[सं० 13/74/का० सं० 328/63/73—धनकर (कृषि भूमि)]

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue & Insurance)

ORDER

New Delhi, the 13th March, 1974

S.O.—1594 : In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 12A of the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957), the Central Government hereby appoints the following persons as Valuation Officers, namely :—

S. Name of the Person
No.

- S/Shri
1. R. Venkatarama Iyer
 2. B.S. Seshadri
 3. G. Ramegowda
 4. A. Veeranna
 5. C. Govindan
 6. B.N. Gundappa
 7. S. Venkataraman
 8. R.A.S. Gautam
 9. P. Saxena
 10. A.N. Prasad
 11. Suresh Kapoor
 12. K.S. Yadava.

[No- 13/74/F. No. 328/63/73/W.T.(Agricultural Lands)]

आवेश

क्रा० प्रा० 1595.—केन्द्रीय सरकार, धन कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) की धारा 12क की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित व्यक्तियों को मूल्यांकन अधिकारियों के रूप में नियुक्त करती है, अर्थात्:—

क्रम सं०	व्यक्ति का नाम
1	2
	सर्वे श्री
1.	के० मधुबालामुक्कमण्यम
2.	बी० गोपाला अय्यर
3.	आर० थोपाधी
4.	आर० वेन्काटरामा अय्यर
5.	के० बी० मुक्जी
6.	वी० एन० साधन
7.	एम० सी० शर्मा ।

[सं० 15/74/का० सं० 328/63/73—ध०क० (शेयर)]

ORDER

S.O. 1595.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 12A of the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957) the Central Government hereby appoints the following persons as Valuation Officers, namely :—

S. Name of the person
No.

S/Shri

1. K. Muthubalasubramanian
2. B. Gopala Iyer
3. R. Thothathri
4. R. Venkatarama Iyer
5. K.B. Mukerji
6. B.L. Sachan
7. M.C. Sharma.

[No. 15/74/F. No. 328/63/73-W.T. (Shares)]

आदेश

का० प्रा० 1596.—केन्द्रीय सरकार, धन-कर, अधिनियम, 1957 (1957 का 27) की धारा 12क की उपधारा (i) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, नीचे की सारणी के स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट व्यक्तियों को मूल्यांकन अधिकारी नियुक्त करती है, जिनके पदनाम उक्त सारणी के स्तम्भ (3) में की तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट किए गए हैं :—

सारणी

क्रम सं०	व्यक्तियों के नाम	पदनाम
1	2	3
1.	श्री सुरेन्द्र नारायण	सहायक मूल्यांकन अधिकारी
2.	श्री आर० एल० ग्रोवर	मूल्यांकन अधिकारी

[सं० 18/74/फा० सं० 328/54/74-धन-कर]

ORDER

S.O. 1596.—In exercise of the powers conferred by sub-section (i) of section 12A of the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957), the Central Government hereby appoints the person specified in column (2) of the Table below as Valuation Officers with the designation specified in the corresponding entry in column (3) of the said Table :—

TABLE

S. No.	Name of the person	Designation
1	2	3
1.	Shri Surendra Narain	Assistant Valuation Officer
2.	Shri R.L. Grover	Valuation Officer

[No. 18/74/F. No. 328/54/74-W.T.]

आदेश

नई दिल्ली, 28 मार्च, 1974

का० प्रा० 1597.—केन्द्रीय सरकार, धन कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) की धारा 12क की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट व्यक्ति का, उक्त सारणी के स्तम्भ (3) में की तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट पदाभिधान सहित मूल्यांकन अधिकारी नियुक्त करती है :—

क्रम सं०	व्यक्ति का नाम	पदाभिधान
1	2	3
1.	श्री आर० डी० गुप्ता	मूल्यांकन अधिकारी

[सं० 19/74/फा० सं० 328/84/74—ध० क०—]

ORDER

New Delhi, the 28th March, 1974

S.O. 1597.—In exercise of the powers conferred by sub-section (i) of section 12A of the Wealth Tax Act, 1957 (27 of 1957), the Central Government hereby appoints the person specified in column (2) of the Table below as Valuation Officer with the designation specified in the corresponding entry in column (3) of the said Table :—

TABLE

S. No.	Name of the person	Designation
1	2	3
1.	Shri R.D. Gupta	Valuation Officer

[No. 19/74/F. No. 328/84/74-W.T.]

आदेश

नई दिल्ली, 19 मार्च, 1974

का० प्रा० 1598.—केन्द्रीय सरकार, धन-कर, अधिनियम, 1957 (1957 का 27) की धारा 12क की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित व्यक्तियों को मूल्यांकन अधिकारी के रूप में नियुक्त करती है, अर्थात् :—

क्रम सं०	व्यक्ति का नाम
1	2
	सर्वश्री
1.	एम० के० दत्ता
2.	आर० के० सेन
3.	एम० सी० नामपाल
4.	एम० के० जैन
5.	एम० एल० अग्रवाल
6.	वी० एम० वाही
7.	के० के० सूद
8.	जगदीश प्रसाद
9.	आर० डी० गुप्ता
10.	एम० एन० सोनी
11.	रघुबीर सिंह जैन

[सं० 20/74/फा० सं० 328/63/73-ध० क० (रोयसः)]

ORDER

New Delhi, the 29th March, 1974

S.O. 1598.—In exercise of the powers conferred by Sub-section (1) of Section 12A of the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957), the Central Government hereby appoints the following persons as Valuation Officers, namely :—

S. No.	Name of the person
--------	--------------------

	S/Shri
1.	S.K. Dutta
2.	R.K. Sen
3.	M.C. Nagpal
4.	M.K. Jain
5.	S.I. Aggarwal
6.	V.S. Wahi
7.	K.K. Sud
8.	Jagdish Parshad
9.	R.D. Gupta
10.	S.N. Soni
11.	Raghubir Singh Jain

[No. 20/74/F. No. 328/63/73-WT. Shares]

आदेश

का० प्रा० 1599.—केन्द्रीय सरकार, धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) की धारा 12क की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित व्यक्तियों को मूल्यांकन अधिकारियों के रूप में नियुक्त करती है, यर्थात् :—

क्रम सं०	व्यक्ति का नाम
----------	----------------

1	2
1.	श्री आर० एल० बहल
2.	श्री एस० पी० सिंह
3.	श्री राम प्रसाद

[सं० 22/74/का० सं० 328/63/73-ध० क० (कृषि भूमि)]

ORDER

S.O. 1599.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 12A of the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957), the Central Government hereby appoints the following persons as Valuation Officers, namely :—

S. No.	Name of the person
--------	--------------------

1.	Shri R.L. Bahl
2.	Shri S.P. Singh
3.	Shri Ram Prasad

[No. 22/74/F. No. 328/63/73-W.T. (Agricultural Lands)]

आदेश

नई दिल्ली, 15 मई, 1974

धन-कर

का० प्रा० 1600.—केन्द्रीय सरकार, धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) की धारा 12क की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्न सारणी के स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट व्यक्तियों को उक्त सारणी के स्तम्भ (3) की तत्संबन्धी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट अभिधानों सहित मूल्यांकन अधिकारियों के रूप में नियुक्त करती है :—

सारणी

क्रम सं०	व्यक्तियों के नाम	पदाभिधान
1	2	3
	सर्वश्री	
1.	एम० के० लहरी	मूल्यांकन अधिकारी
2.	एम० एन० शर्मा	यर्थात्
3.	के० रामाचन्द्रन	यर्थात्

[सं० 37/74/का० सं० 328/107/74-ध० क०]

वी० डी० वाखार्कार, अधर सचिव

ORDER

New Delhi, the 15th May, 1974

WEALTH-TAX

S.O. 1600.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 12A of the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957), the Central Government hereby appoints the persons specified in column (2) of the Table below as Valuation Officers with the designations specified in the corresponding entry in column (3) of the said Table.

TABLE

S. No.	Name of the persons	Designation
1	2	3
	S/Shri	
1.	S.K. Lahri	Valuation Officer
2.	M.N. Sharma	Valuation Officer
3.	K. Ramachandran	Valuation Officer

[No. 37/74/F. No. 328/107/74-W. T.]
V. D. WAKHARKAR, Under Secy.

आदेश (रद्दकरण)

नई दिल्ली, तारीख 8 अप्रैल, 1974

का० प्रा० 1601.—श्री के० बी० नरसिम्हन् को, जिन्हें का० सं० 328/63/73-ध० क०, तारीख 6 मितम्बर, 1973 में के आदेश सं० 43 द्वारा, धनकर अधिनियम, 1957 की धारा 12क के अधीन, गेयरो के लिए मूल्यांकन अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया था, नियुक्ति रद्द की जाती है।

[सं० 27/74/का० सं० 328/63/73-ध० क०]

ORDER CANCELLATION

New Delhi, the 8th April, 1974

S.O. 1601.—The appointment of Shri K. B. Narasimhan who was appointed as Valuation Officer for Shares u/s. 12A of the Wealth Tax Act, 1957 by Order No. 43 in F. No. 328/63/73-WT dated the 6th September, 1973 is hereby cancelled.

[No. 27/74/F. No. 328/63/73-WT]

आदेश

नई दिल्ली, 17 अप्रैल, 1974

का० प्रा० 1602.—केन्द्रीय सरकार, धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) की धारा 12क की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, नीचे की सारणी के स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट व्यक्ति को, उक्त सारणी के स्तम्भ (3) में

को तत्संबन्धी प्रविष्टि में अनिवार्य पदाभिधान सहित, मूल्यांकन अधिकारी के रूप में नियुक्त करती है :—

सारणी

क्रम सं०	व्यक्ति का नाम	पदाभिधान
1.	श्री बी० एम० घोष	मूल्यांकन अधिकारी

[सं० 29/74/का० सं० 328/96/74-ध० क०]
एम० बापू, अवर सचिव

ORDER

New Delhi, the 17th April, 1974

S.O. 1602.—In exercise of the powers conferred by sub-section (i) of section 12A of the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957), the Central Government hereby appoints the person specified in column (2) of the Table below as Valuation Officer with the designation specified in the corresponding entry in column (3) of the said Table :—

TABLE

S. No.	Name of the person	Designation
1	2	3
1.	Shri B. M. Ghosh	Valuation Officer

[No. 29/74/F. No. 328/96/74 W.T.]

S. BAPU, Under Secy.

नई दिल्ली 10 मई, 1974

आय-कर

का० प्रा० 1603.—सर्वसाधारण की जानकारी के लिए यह अधिसूचित किया जाता है कि निम्न वर्णित संस्था को भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद्, विहित प्राधिकारी, द्वारा आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35 की उपधारा (1) के खण्ड (ii) के प्रयोजनों के लिए अनुमोदित किया गया है :—

संस्था

वकील इन्स्टिट्यूट आफ कार्डिओलॉजी एण्ड रिसर्च सेंटर, मुम्बई।
यह अधिसूचना 1-4-1973 से प्रभावी होगी।

[सं० 611 (का० सं० 203/28/74-आई टी ए० II)]

New Delhi, the 10th May, 1974

INCOME-TAX

S.O. 1603.—It is hereby notified for general information that the institution mentioned below has been approved by Indian Council of Medical Research, the prescribed authority for the purpose of clause (ii) of sub-section (1) of Section 35 of the Income-tax Act, 1961 :—

INSTITUTION

VAKIL INSTITUTE OF CARDIOLOGY AND RESEARCH CENTRE, BOMBAY

This notification will take effect from 1-4-1973.

[No. 611 (F. No. 203 28/74-IT(III))]

नई दिल्ली, 22 मई 1974

आय-कर

का० प्रा० 1604.—सर्वसाधारण की सूचना के लिए यह अधिसूचित किया जाता है कि केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड द्वारा आय-कर 1961 (1961 का 43) की धारा 35 घ की उपधारा (2) के प्रयोजनों के लिए निम्न उल्लिखित संस्था अनुमोदित की गई है।

संस्था

मेल्बोर्नीसिक्स कनगलटेन्स (इण्डिया) प्राइवेट लिमिटेड, नई दिल्ली।

[सं० 619 (का० सं० 202/48/71-आई टी ए० II)]

New Delhi, the 22nd May, 1974

INCOME-TAX

S.O. 1604.—It is hereby notified for general information that the institution mentioned below has been approved by the Central Board of Direct Taxes for the purposes of sub-section (2) of Section 35D of Income-tax Act, 1961 (43 of 1961).

INSTITUTION

Cellulosics Consultants (India) Private Ltd., New Delhi.

[No. 619 (F. No. 202/48/71-ITA. II)]

नई दिल्ली, 24 मई, 1974

आयकर

का० प्रा० 1605.—सर्वसाधारण की जानकारी के लिए यह अधिसूचित किया जाता है कि निम्न-वर्णित संस्था को विहित प्राधिकारी, भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद् ने आय-कर अधिनियम, 1959 की धारा 35 की उपधारा (1) के खण्ड (iii) के प्रयोजनों के लिए, प्रथमतया तीन वर्ष की अवधि के लिए अनुमोदित किया है। स्वामी, संस्था द्वारा इस छूट के अधीन प्राप्त दानों और जिस रीति से उनका उपयोग किया जाय उसकी बाबत एक रिपोर्ट प्रतिवर्ष भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद् को भेजेंगे।

संस्था

बलराज-दमयन्ती साहनी मेमोरियल ट्रस्ट, अलमोड़ा।

यह अधिसूचना 1 अप्रैल, 1973 से प्रभावी है।

[सं० 627 (का० सं० 203/20/74-आई टी ए० II)]

New Delhi, the 24th May, 1974

INCOME-TAX

S.O. 1605.—It is hereby notified for general information that the institution mentioned below has been approved by Indian Council of Social Science Research, the prescribed authority for the purposes of clause (iii) of sub-section (1) of Section 35 of the Income-tax Act, 1961 for a period of three years in the first instance. The trustees will send to Indian Council of Social Science Research annually a report on the donation received by the Institution under this exemption and the manner in which they are utilised.

INSTITUTION

Balraj-Damyanti Sahni Memorial Trust, Almora.

The notification takes effect from 1-4-1973.

[No. 627 (F. No. 203/20/74-ITA. II)]

नई दिल्ली, 28 मई, 1974

आय-कर

का० प्रा० 1606.—संयंसाधारण की जानकारी के लिए यह अधिसूचित किया जाता है कि निम्न वर्णित संस्था को इंजन वाल्वों के निर्माण सम्बन्धी तकनीकी ज्ञान प्रदान करने के प्रयोजनों के लिए, विहित प्राधिकारी, द्वारा आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35 की उपधारा (2) के प्रयोजनों के लिए अनुमोदित किया गया है।

संस्था

इंजन वाल्व्स लिमिटेड, मद्रास

यह अधिसूचना 1 अप्रैल, 1973 में प्रभावी होगी।

[सं० 632 (का० सं० 202/55/73-प्रा० टी० पी० II)]

टी० पी० जूनजुनवाला, उर सचिव

New Delhi, the 28th May, 1974

INCOME-TAX

S.O. 1606.—It is hereby notified for general information that the institution mentioned below has been approved by the Central Board of Direct Taxes for the purposes of sub-section (2) of Section 35D of Income-tax Act, 1961 for purpose of imparting of technical know-how in respect of manufacture of engine valves :—

INSTITUTION

ENGINE VALVES LIMITED, MADRAS.

The notification takes effect from 1-4-1973.

[No. 632 (F. No. 202/55/73-ITA.II)]

T. P. JHUNJHUNWALA, Dy. Secy.

नई दिल्ली, 27 मई, 1974

बीमा

का० प्रा० 1607.—यह केन्द्रीय सरकार की राय है कि विविध बीमा कारबार अधिक दक्षता से चलाने के लिए ऐसा करना आवश्यक है;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार विविध, बीमा कारबार (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1972 (1972 का 57) की धारा 16 की उपधारा (1) के खण्ड (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बीमाकर्ताओं के अधीन पर्यवेक्षी, लिपिकीय और अधीनस्थ पदों पर काम करने वाले कर्मचारियों के वेतनमानों और सेवा के अन्य निबंधनों तथा शर्तों के सुव्यवस्थीकरण और पुनरीक्षण के लिए उपबन्ध करने हेतु निम्नलिखित स्कीम धनती है, अर्थात् :—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ :—**(1) इस स्कीम का नाम विविध बीमा (पर्यवेक्षी), लिपिकीय और अधीनस्थ कर्मचारी वृन्द के वेतनमानों और सेवा की अन्य शर्तों का सुव्यवस्थीकरण और पुनरीक्षण स्कीम, 1974 है।

(2) यह राजपत्र में प्रकाशन की तारीख की प्रवृत्त होगी।

2. **लागू होना :—**इसमें अन्तर्निष्ठ उपबन्ध, (अधिकारियों और विकास कर्मचारिवृन्द से भिन्न) भारत में पर्यवेक्षी, लिपिकीय और अधीनस्थ पदों पर कार्य करने वाले ऐसे व्यक्तियों को लागू होंगे—

(i) जो भारतीय बीमा कंपनियों में से किसी में 31 दिसम्बर, 1972 को पूर्णकालिक कर्मचारियों के रूप में पुष्ट हो गए थे;

(ii) जो किसी भारतीय बीमा कंपनी से भिन्न किसी विद्यमान बीमाकर्ता के 31 दिसम्बर, 1972 को पूर्णकालिक कर्मचारियों के रूप में पुष्ट हो गए थे और जो धारा 7 की उपधारा (1) के अनुसार किसी भारतीय बीमा कंपनी के कर्मचारों हो गए थे;

(iii) जो भारतीय बीमा कंपनियों में से किसी कंपनी या किसी भारतीय बीमा कंपनी से भिन्न किसी विद्यमान बीमाकर्ता के अधीन अस्थायी पूर्णकालिक कर्मचारों के जो इस स्कीम के प्रारम्भ होने के पूर्व पुष्ट हो गए थे;

(iv) जो इस स्कीम के प्रारम्भ होने के पश्चात् निगम या उपाके किसी समनुपंगी द्वारा भर्ती किए गए थे, किन्तु ऐसे व्यक्तियों को लागू नहीं होंगे :—

(क) जो नियोजन की विनिर्दिष्ट भविदाओं के अधीन नियोजित किए गए हैं;

(ख) जो अग्रकालिक नियोजन के अधीन हैं; और

(ग) जो इस स्कीम के प्रारम्भ होने के पूर्व पदत्याग कर चुके हैं या श्रमिकी सेवाएं समाप्त कर दी गई हैं।

परन्तु खण्ड (iii) में निर्दिष्ट व्यक्तियों की बाबत, इस स्कीम के उपबन्ध केवल उस तारीख से प्रभावी होंगे जिसको संबद्ध व्यक्ति अपने अपने पद पर पुष्ट हो गए थे।

3. **परिभाषाएं :—**इस स्कीम में, जब तक कि सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो :—

(क) “अधिनियम” से विविध बीमा कारबार (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1972 (1972 का 57) अभिप्रेत है;

(ख) “अभिरक्षक” से, जब तक कि पद अध्यक्ष-एवम-प्रबन्धक निदेशक के रूप में पुनः पदाभिहित न किया गया हो, धारा 16 की उपधारा (2) में निर्दिष्ट चार कंपनियों में से किसी का अभिरक्षक अभिप्रेत है, और पद के पुनः पदाभिधान की तारीख से अभिरक्षक के प्रति इस स्कीम में किसी निर्देश से यह अर्थ लगाया जाएगा कि वह अध्यक्ष-एवम-प्रबन्धक निदेशक के प्रति निर्देश है;

(ग) “कर्मचारी” से वह कर्मचारी अभिप्रेत है, जिसे इस स्कीम के उपबन्ध लागू होते हैं;

(घ) “बीमा परीक्षा” से प्रथम अनुसूची के पैरा 4 में विनिर्दिष्ट कोई बीमा परीक्षा अभिप्रेत है।

(ङ) “प्रबन्ध निदेशक” से धारा 9 के अधीन बने भारतीय विधि बीमा निगम का प्रबन्ध निदेशक अभिप्रेत है;

(च) “नया वेतनमान” से प्रथम अनुसूची में यथा उपवर्णित नया वेतनमान और संज्ञाई भत्ता तथा अन्य भत्ते अभिप्रेत है;

(छ) “धारा” से अधिनियम की कोई धारा अभिप्रेत है;

(ज) “अनुसूची” से इस स्कीम में संलग्न अनुसूची अभिप्रेत है;

(झ) “अधीनस्थ कर्मचारिवृन्द” से दफ्तरी, मशीन ऑपरेटर, जमादार, प्रधान चपरासी, चपरासी, लिफ्टमैन, माफो, ननसाज, प्रहरी, और आहुकश के पद पर कार्य करने वाला कोई कर्मचारी अभिप्रेत है।

4 **कर्मचारियों के वेतन और भत्ते :—**(1) प्रत्येक कर्मचारी को अपने कार्यालय के प्रधान की मार्फत अभिरक्षक को संबंधित लिखित सूचना द्वारा इस स्कीम के प्रारम्भ होने की तारीख से तब्ये दिन के भीतर या

तो नए वेतनमान द्वारा या इस स्कीम के प्रारम्भ होने के ठीक पूर्व उसे लागू वेतनमान और भत्तों द्वारा शामिल होने के लिए चुनने का विकल्प होगा और एक बार प्रयोग किया विकल्प अन्तिम होगा।

स्पष्टीकरण 1:—इस पैरा और पैरे 5 और 6 के प्रयोजनों के लिए, "कर्मचारी" से पैरा 2 के खण्ड (i) या खण्ड (ii) या खण्ड (iii) में निर्दिष्ट कोई कर्मचारी अभिप्रेत है।

स्पष्टीकरण 2:—इस पैरा के प्रयोजनों के लिए, "नया वेतनमान" से वेतन, मंहगाई भत्ता और अन्य भत्ता अभिप्रेत है, किन्तु इसमें किट भत्ता और यर्दी तथा गुप्ताई भत्ता सम्मिलित नहीं है।

(2) (क) यदि कोई कर्मचारी नए वेतनमान द्वारा शामिल होने के लिए चुनाव करता है तो उसे उस तारीख से जिसको वह उप-पैरा (1) के अधीन विकल्प का प्रयोग करता है, नए वेतनमान के अनुसार वेतन, मंहगाई भत्ता और अन्य भत्ते दिए जाएंगे और ऐसे कर्मचारी को 1 जनवरी, 1973 से प्रारम्भ होने वाली अवधि के लिए, नए वेतनमान और उस वेतनमान, जो विकल्प की तारीख के ठीक पूर्व उसे लागू था मानों नया वेतनमान उक्त अवधि के दौरान प्रवृत्त था, के बीच वेतन, मंहगाई भत्ता और अन्य भत्तों का अन्तर दिया जाएगा।

परन्तु यह कि जहां पूर्वोक्त अवधि के लिए ऐसा कर्मचारी, नए वेतनमान के अधीन अवधारित रकम से अधिक रकम पुराने वेतनमान के अधीन वेतन, मंहगाई भत्ता और अन्य भत्ते के रूप में ले चुका हो वहां, उससे इस प्रकार की गई अधिक रकम लौटाने की अपेक्षा नहीं की जाएगी।

(ख) यदि खण्ड (क) में निर्दिष्ट अवधि के दौरान ऐसे कर्मचारी द्वारा छुट्टी का कोई भाग भुनाया गया था तो, ऐसे कर्मचारी से ऐसे भुनाए जाने के रूप में उसके द्वारा वसूल की गई रकम लौटाने की अपेक्षा नहीं की जाएगी और यदि इस स्कीम के उपबन्धों को लागू करने के परिणाम-स्वरूप ऐसा कर्मचारी ऐसी छुट्टी की बाबत संदाय के किन्हीं बकाए का हकदार हो तो ऐसे बकाए उसे दिए जाएंगे।

(3) (क) यदि कोई कर्मचारी, इस स्कीम के प्रारम्भ होने के ठीक पूर्व उसे लागू वेतनमान और भत्तों का चुनाव करता है तो, कर्मचारी ऐसे प्रारम्भ से, उक्त वेतनमान के अनुसार मासिक वेतन और भत्ते प्राप्त करता रहेगा।

(ख) यदि सुसंगत अवधि के दौरान ऐसा कर्मचारी उस पद से भिन्न, जिस पर वह प्रसामान्यतः नियोजित था, पद धारण कर रहा था या अस्थायी प्रकृति का कोई भत्ता पा रहा था तो, केवल उस वेतन और भत्तों को, जो उसने प्रसामान्य पद पर लिया होगा, हिसाब में लिया जाएगा।

(ग) नए वेतनमान से भिन्न सभी बातों की बाबत ऐसे कर्मचारी, ऐसी बातों की बाबत इसमें अन्तर्निहित उपबन्धों द्वारा शामिल होगा।

परन्तु यदि ऐसे कर्मचारी की उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति हो जाती है तो, ऐसे कर्मचारी से संबंधित उस श्रेणी में वेतनमान और भत्ते वे होंगे जो ऐसी उच्चतर श्रेणी के लिए इसमें विनिर्दिष्ट हैं।

5 कर्मचारियों का वर्गीकरण:—(1) कर्मचारियों का वर्गीकरण 1 जनवरी, 1973 को उनके अधिष्ठायी पदों और काम की प्रकृति के आधार पर उपयुक्त प्रवर्गों में किया जाएगा, जो उप-पैरा (2) से (4) में विनिर्दिष्ट है।

(2) (क) **अधीक्षक:—**उप-पैरा (1) के अधीन रहते हुए, निम्नलिखित व्यक्ति अधीक्षकों के रूप में समझे जाने के पात्र होंगे, अर्थात्:—

(i) वे सभी व्यक्ति, जो अधीक्षकों, प्रमुख प्रमुखों, सहायक अधीक्षकों, कर्मचारिवृन्द सहायकों, प्रधान निपिकों और पर्यवेक्षी हेमियन में काम करने वाले पर्यवेक्षकों के रूप में पदाभिहित हैं;

(ii) वे सभी व्यक्ति जो यूनाइटेड इण्डिया फायर और जनरल इंडोरेम कंपनी लिमिटेड, यूनिट "यूनियन कोऑपरेटिव" में फिनिश अधिकारियों के रूप में पदाभिहित हैं;

(iii) वे सभी कर्मचारी, जिनके विनिर्दिष्ट वेतनमान या अर्हताएं हैं और जिनमें उपखण्ड (i) या उपखण्ड (ii) में उल्लिखित पदों में से किसी समतुल्य पद पर विशेषणवादी भर्ती किया गया है।

(ख) **ज्येष्ठ सहायक:**

(i) उप-पैरा (4) के अधीन रहते हुए, जहां खण्ड (क) के अधीन वर्गीकृत अधीक्षकों की श्रेणी से भिन्न दो लिपिकीय श्रेणियां हों, वहां वे, जो दोनों श्रेणियों में से उच्चतर श्रेणी में हों, उनके द्वारा किये गए कर्तव्य के आधार पर ज्येष्ठ सहायकों के रूप में वर्गीकृत किए जाने के पात्र होंगे। जहां ऐसी दो श्रेणियों से अधिक श्रेणियां हो वहां, वे, जो ऐसी श्रेणियों में से उच्चतम श्रेणी में हों, ज्येष्ठ सहायकों के रूप में वर्गीकृत किए जाने के पात्र होंगे।

(ii) उप-पैरा (4) के अधीन रहते हुए, जहां केवल एक लिपिकीय श्रेणी हो वहां, वे जो 1 जनवरी, 1973 को निम्नलिखित शर्तों में से किसी को पूरा करते हैं, ज्येष्ठ सहायकों के रूप में वर्गीकृत किए जाने के पात्र होंगे, अर्थात्:—

(क) जिन्होंने लिपिकों या सहायकों के रूप में 10 वर्ष की सेवा की हो; या

(ख) जिन्होंने लिपिकों या सहायकों के रूप में 8 वर्ष की सेवा की हो और बीमा संस्थान परिसंघ की अनुश्रुति परीक्षा उत्तीर्ण की हो; या

(ग) जिन्होंने लिपिकों या सहायकों के रूप में 7 वर्ष की सेवा की हो और बीमा संस्थान परिसंघ या चाटर्ड बीमा संस्थान की एसोसिएटशिप परीक्षा उत्तीर्ण की हो; या

(घ) जिन्होंने लिपिकों या सहायकों के रूप में 5 वर्ष की सेवा की हो और बीमा संस्थान परिसंघ या चाटर्ड बीमा संस्थान की फेलोशिप परीक्षा उत्तीर्ण की हो।

(3) (क) **प्राशुलिपिक:** वे सभी व्यक्ति जो प्राशुलिपिकों के रूप में या समतुल्य पदों पर कार्य कर रहे हैं और वे सभी व्यक्ति जो प्राशु-टंककों या प्राशुलिपि टंककों के रूप में या समतुल्य पदों पर कार्य कर रहे हैं और जो सरकार द्वारा गठित किसी परीक्षण निकाय द्वारा जारी किया गया श्रुतलेख में प्रति मिनट कम से कम 100 शब्दों और टंकण में प्रति मिनट कम से कम 40 शब्दों का प्रमाणपत्र धारण करते हैं या जो होने वाला परीक्षण श्रुतलेख में प्रति मिनट कम से कम 100 शब्दों और टंकण में प्रति मिनट कम से कम 40 शब्दों की गति के साथ उत्तीर्ण करने हों प्राशुलिपिकों के रूप में वर्गीकृत किए जाने के पात्र होंगे।

(ख) **सहायक:** निम्नलिखित प्रवर्गों में से किसी एक में या अधिक में आने वाले सभी कर्मचारी सहायकों के रूप में वर्गीकृत किए जाएंगे अर्थात्:—

- (i) ऐसे सभी कर्मचारी जो नियमित आधार पर नैतिक लिपिकीय कार्य कर रहे हों;
- (ii) ऐसे सभी कर्मचारी जो लिपिकों कनिष्ठ लिपिकों, सहायकों, टेलीफोन अपरेटरों, टेलीग्राम अपरेटरों, पंच वाई अपरेटरों, यूनिट रेकर्ड मशीन अपरेटरों और पत्रिकान-यंत्र प्रकाशकों के रूप में पदाभिज्ञित हैं;
- (iii) ऐसे सभी कर्मचारी जो कनिष्ठ लिपिकीय श्रेणी या समतुल्य टंकक श्रेणी में टंककों के रूप में कार्य कर रहे हैं;
- (iv) वे सभी, जो आशुलिपिकों, आशु-टंककों, आशुलिपि टंककों के रूप में या समतुल्य पदों पर कार्य कर रहे हैं और जिन्हें आशुलिपिकों के रूप में वर्गीकृत नहीं किया गया है;
- (v) ऐसे सभी अन्य लिपिकीय कर्मचारिवृन्द, जिन्हें ज्येष्ठ सहायकों या अधीनस्थों के रूप में वर्गीकृत नहीं किया गया है।

(ग) अभिलेख लिपिक :

ऐसे सभी कर्मचारी जो अभिलेख लिपिकों या फाइलिंग सहायकों के रूप में पदाभिज्ञित हैं और वे सभी कर्मचारी जो अधीनस्थ कर्मचारी-वृन्द से संबंधित विनिश्चित वेतन श्रेणी में नहीं हैं और जिनके कार्य मुख्य रूप से निम्नलिखित में से कोई एक या अधिक हैं अभिलेख लिपिकों के रूप में वर्गीकृत किए जाएंगे, अर्थात् :—

- (i) कागजपत्रों को फाइल करना और खोजना;
 - (ii) आवक डाक को खोलना, छांटना और उसका विवरण करना;
 - (iii) लिफाफों पर पता लिखना;
 - (iv) बांडा और अनुलिपिकरण मशीनों का प्रचालन;
 - (v) हस्त-प्रचालित पना-लेखन मशीनों का प्रचालन;
 - (vi) वर्णक्रम-विषयक या सांख्यिक अनुक्रमणिका को बनाए रखना;
 - (vii) बरिष्ठों द्वारा नष्ट करने के लिए चिह्नित पुराने अभिलेखों का नष्ट किया जाना।
- (घ) (i) चालक.—ऐसे सभी कर्मचारी जो एकमात्र रूप से यंत्र नोत्रित यात्रों के वाहकों के रूप में कार्य कर रहे हों; चालकों के रूप में वर्गीकृत किए जाएंगे।
- (ii) सभी अन्य अधीनस्थ कर्मचारिवृन्द :—ऐसे सभी कर्मचारी जो विभिन्न अधीनस्थ पदों पर कार्य कर रहे हों, अधीनस्थ कर्मचारिवृन्द के रूप में वर्गीकृत किए जाएंगे।

(4) पैरा (2) और उप-पैरा (3) के खण्ड (क) में विनिश्चित पदों के लिए काउन्-संख्या का अधिधारण विभिन्न स्तरों पर और विभिन्न प्रकारों के कामिक की आवश्यकता के आधार पर अभिरक्षक द्वारा किया जाएगा। यदि इस प्रकार वर्गीकृत किए जाने के लिए पात्र कर्मचारियों की संख्या अपेक्षित काउन्-संख्या से अधिक हो जाती हो तो इस प्रकार वर्गीकृत किए जाने के लिए कर्मचारियों का चयन अहंताओं, सेवा-काल, और कार्य की दक्षता के आधार पर किया जाएगा।

(5) उस प्रवर्ग के जिसमें किसी कर्मचारी को नए वेतनमान में रखे जाने के प्रयोजन के लिए समनुदिष्ट किया जाएगा बारे में अभिरक्षक का विनिश्चय कर्मचारी पर आबद्धकर होगा।

6. नियतन की पद्धति :—उन कर्मचारियों से जो नए वेतनमान द्वारा शासित नहीं होने का चुनाव करते हैं, भिन्न प्रत्येक कर्मचारी को उस प्रवर्ग से संबंधित नए वेतनमान में रखा जाएगा जिसमें वह नए

वेतनमान में मूल वेतन पर रखा जाता है जो निम्नलिखित अनुकल्पों के आधार पर अभिनिश्चित तीनों रकमों में से सबसे अधिक रकम होगी :—

(क) उस प्रवर्ग में 1 जनवरी, 1973 को सेवा के प्रत्येक दो संपूर्ण वर्षों के लिए प्रारम्भिक वेतनमान पर एक वृद्धि देकर।

पैरा 4 के उप-पैरा (2) के खण्ड (ख) के उपखण्ड (ii) के अनुसार ज्येष्ठ सहायकों के रूप में वर्गीकृत व्यक्तियों की बावत, कनिष्ठ सहायकों की श्रेणी में मूल वेतन इस अनुकल्प द्वारा अभिनिश्चित किया जायेगा और ऐसे ज्येष्ठ सहायकों की श्रेणी में मूल वेतन को जो कनिष्ठ सहायक की श्रेणी में मूल वेतन के समतुल्य या उससे उच्चतर है, उपयुक्त मूल वेतन माना जाएगा।

यदि इस प्रकार अवधारित मूल वेतन 270 रु० या अधिक हो किन्तु 500 रु० से अधिक न हो और श्रेणी की अधिकतम सीमा पर न हो तो, उस श्रेणी में मूल वेतन में एक और वेतन वृद्धि इस अनुकल्प के अधीन मूल वेतन की रकम अवधारित करने के लिए की जाएगी, या

(ख) यह अवधारित करके कि 1 जनवरी, 1973 को नए वेतनमान में मूल वेतन और मंहगाई भत्ते का योग उस तारीख को मूल वेतन और तत्संबंधी तदर्थ भत्ता या ह्रास के तदर्थ समझौते के परिणामस्वरूप अनुवर्त तदर्थ वैयक्तिक वेतन और उस तारीख को तत्संबंधी मंहगाई भत्ते के योग के समतुल्य या उसके ठीक अगले वेतनस्तर से अधिक है।

यदि इस प्रकार अवधारित मूल वेतन 245 रु० या अधिक हो किन्तु 315 रु० से अधिक न हो, और श्रेणी की अधिकतम सीमा पर न हो तो, उस श्रेणी में मूल वेतन पर एक और वेतन वृद्धि इस अनुकल्प के अधीन मूल वेतन की रकम अवधारित करने के लिए दी जाएगी; या

(ग) यह अवधारण करके कि क्या नए वेतनमान में मूल वेतन वर्तमान कुल मूल वेतन और 10 रु० की रकम के योग के समतुल्य या उसके ठीक अगले वेतनस्तर से अधिक है,

यदि इस प्रकार अवधारित मूल वेतन 270 रु० या अधिक हो किन्तु 500 रु० से अधिक न हो और श्रेणी की अधिकतम सीमा पर न हो तो, उस श्रेणी में मूल वेतन पर एक और वेतन-वृद्धि इस अनुकल्प के अधीन मूल वेतन की रकम अवधारित करने के लिए दी जाएगी।

टिप्पण :—(1) अनुकल्प (ग) के प्रयोजन के लिए, “वर्तमान मूल वेतन” पद से वह मूल वेतन अभिप्रेत है, जो कर्मचारी, यदि यह स्कीम प्रवृत्त नहीं होती तो, 1 जनवरी, 1973 (उस तारीख को शीघ्र वेतन-वृद्धि यदि कोई हो, के पश्चात्) को लेता और इसमें कोई अन्य रकम जैसे वैयक्तिक वेतन या कृत्यिक भत्ता या तदर्थ भत्ता या कोई अन्य भत्ता, चाहे जिस नाम से भी जाना जाये, ऐसी रकमों के संदाय से संबंधित निबंधनों और शर्तों में कोई उपबन्ध होते हुए भी सम्मिलित नहीं है।

टिप्पण :—(2) इस उप-पैरा के प्रयोजनों के लिए यदि कोई कर्मचारी 1 जनवरी, 1973 के ठीक पूर्व किसी ऐसी कम्पनी में, जिसमें मंहगाई भत्ते का कोई निश्चित मान नहीं है, सम्मिलित वेतन या भत्ता प्राप्त करता है, तो सम्मिलित वेतन मूल वेतन के रूप में नहीं माना जाएगा, किन्तु अभिरक्षक कर्मचारी के मामले में वर्तमान मूल वेतन के रूप में मानी जाने वाली उपयुक्त रकम अवधारित करेगा।

(2) यदि उप-पैरा (1) के अधीन यथा अवधारित मूल वेतन नए वेतनमान की अधिकतम सीमा से अधिक हो जाता है तो, उसे नए वेतनमान की अधिकतम सीमा पर नियत किया जाएगा।

(3) जहाँ किसी कर्मचारी को उप-पैरा (1) के अनुकूल (क) या (ग) के आधार पर 270 रु० से कम मूल वेतन पर रखा जाता है और तबहा कर्मचारी का मूल वेतन, 1 जनवरी, 1974 को या के पूर्व वापिक वेतन-वृद्धि अनुदान किए जाने पर 270 रु० पर पहुँच जाता है या उससे अधिक हो जाता है वहाँ, कर्मचारी को उस श्रेणी में एक अनिर्दिष्ट वेतन-वृद्धि दी जाएगी, जो उसकी वापिक वेतन-वृद्धि की तारीख से प्रभावी होगी।

(4) जहाँ किसी कर्मचारी को उप-पैरा (1) के अनुकूल (ख) के आधार पर 215 रु० से कम मूल वेतन पर रखा जाता है और जहाँ कर्मचारी का मूल वेतन, 1 जनवरी, 1974 को या के पूर्व वापिक वेतन-वृद्धि अनुदान किए जाने पर 215 रु० पर पहुँच जाता है या उससे अधिक हो जाता है वहाँ, कर्मचारी को उस श्रेणी में एक अनिर्दिष्ट वेतन-वृद्धि दी जाएगी, जो उसकी वापिक वेतन-वृद्धि की तारीख से प्रभावी होगी।

(5) जहाँ किसी कर्मचारी की बाबत इस पैरा के अधीन 1 जनवरी 1973 को (नया मूल वेतन, मंहाई भत्ता, अर्हता वेतन, कुलिक भत्ता, गृह भाटक भत्ता, नगर प्रतिकारात्मक भत्ता और पहाड़ी स्थान भत्ता को समाविष्ट करते हुए) अवधारित कुल वेतन, उक्त तारीख के (केवल वर्तमान मूल वेतन, मंहाई भत्ता, तदर्थ भत्ता या तदर्थ वैयक्तिक वेतन, कुलिक भत्ता, अर्हता वेतन, गृह भाटक भत्ता, नगर प्रतिकारात्मक भत्ता पहाड़ी स्थान भत्ता और तबख में संलग्न लंच भत्ता को समाविष्ट करने हुए) ठीक पूर्व के उसके कुल वेतन से कम हो वहाँ, वेतन नियत किए जाने के पश्चात् नए कुल वेतन से अधिक कुल वेतन की रकम कर्मचारी को न्यक्तिक वेतन के रूप में दिया जाएगा।

7. वेतन वृद्धियाँ :—(1) नए वेतनमान में वेतन वृद्धियाँ प्रतिवर्ष उस मास के प्रथम दिन को जिसमें, 1 जनवरी, 1973 के पूर्व अन्तिम वेतन वृद्धि अनुदान की गई थी या अगले मास के प्रथम दिन को जिस दिन को वह निरंतर सेवा के बारह मास पूरा कर लेता है, शोध्य होगी। जहाँ वेतन-वृद्धि 1 जनवरी 1973 को शोध्य होती है वहाँ, कर्मचारी को उसके वर्तमान वेतनमान में एक वृद्धि देने के पश्चात् नया वेतनमान लागू किया जाएगा।

(2) ऐसे कर्मचारियों की बाबत जिनका मूल वेतन पैरा (5) के अधीन, 1 जनवरी, 1973 को नए वेतनमान के अधिकतम पर नियत किया जाता है और उनके संबंध में जो अपनी सेवा की अवधि के दौरान उसके पश्चात् किसी भी समय अधिकतम पर पहुँच जाएगा, यथास्थिति अभिरक्षक या प्रबन्ध निदेशक कर्मचारियों के कार्य का रेकार्ड सतोपजनक पाने पर ही, उनके द्वारा 1 जनवरी, 1973 के पश्चात् या उनके अपने-अपने वेतनमान के अधिकतम पर उनके पहुँचने की तारीख के पश्चात् की गई प्रत्येक दो वर्ष की सेवा के लिए एक अनिर्दिष्ट वेतन वृद्धि और पश्चात्-वर्ती स्थिति में वेतनमान में की गई अन्तिम वृद्धि के हिसाब से देने के लिए, विचार करेगा और इस उपबन्ध के अधीन अधिक से अधिक तीन ऐसी वृद्धियाँ अनुदान की जाएंगी।

8. काम के घंटे :—(1) (क) काम के घंटे जो, सभी कार्यालयों में पर्यवेक्षी और लिपिकीय श्रेणियों के सभी कर्मचारियों के लिए सामान्य कार्यकरण दिन होंगे, सप्ताह दिनों में 45 मिनट के लंच के समय सहित, 10.00 बजे से 5.00 बजे होंगे और शनिवारों को 10.00 बजे से 2.00 बजे होंगे।

(ख) कार्यालयों में संलग्न अधीनस्थ कर्मचारिवृन्द के लिए काम के सामान्य घंटे सप्ताह दिनों में 45 मिनट के लंच के समय सहित 9.30 36 GI/74--2

बजे से 5.00 बजे होंगे और शनिवारों को 9.30 बजे से 2.00 बजे होंगे।

परन्तु टेसीफोन अपरेटरों, डाक विभाग कर्मचारिवृन्द और अभिरक्षक या प्रबन्ध निदेशक द्वारा विनिर्दिष्ट किसी विनिर्दिष्ट विभाग के अधीनस्थ कर्मचारिवृन्द के लिए, काम के घंटे संबंध कार्यालय के सामान्य काम के घंटों से भिन्न हो सकेंगे।

(2) चालकों और कर्मचारिवृन्द जैसे, निरस्तमेत, क्लीनर प्रहरी, बिजली-सिस्त्री नलमाज और माली, के लिए काम के सामान्य घंटे, शनिवार सहित सभी छह सप्ताह दिनों को 8 घंटे होंगे, और प्राठ घंटे की इस अधिकतम समय सीमा के अधीन रहते हुए, प्रत्येक कार्यालय के लिए काम के वास्तविक घंटे इस प्रकार होंगे जो अभिरक्षक या प्रबन्ध निदेशक द्वारा नियत किए जाएंगे।

9. अवकाशदिन :—सभी कार्यालय, परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 (1881 का 26) के अधीन अवकाश दिनों के रूप में संबंधित राज्य सरकारों द्वारा घोषित सभी अवकाशदिन मनाएंगे, किन्तु उन अवकाशदिनों को छोड़ देंगे जिन्हें वेतन की अपने लेखाओं को बंद करने में समर्थ बनाने के प्रयोजन के लिए स्पष्टतः घोषित किया गया है। जहाँ ऐसे अवकाशदिनों की संख्या किसी वर्ष में 22 दिन से कम हो वहाँ, ऐसे अनिर्दिष्ट अवकाशदिन और अर्द्ध-अवकाशदिन, स्थानीय उत्सवों के अवसर पर मनाए जा सकेंगे, जो कम्पनी के अभिरक्षक या प्रबन्ध निदेशक विनिश्चय करें, परन्तु एक वर्ष में अवकाशदिनों की कुल संख्या 22 पूर्ण अवकाशदिन और 3 अर्द्ध-अवकाशदिन से अधिक नहीं होगी।

टिप्पण :—अर्द्ध अवकाशदिनों की दशा में, कार्यालय या तो सामान्य कार्य-करण अवधि की लंच-पूर्व अवधि या लंच-पश्चात् अवधि के लिए बंद रहेगा। शनिवार को पड़ने वाले अवकाशदिन पूर्ण अवकाशदिनों के रूप में माने जाएंगे।

10. छुट्टी :—(1) इस स्कीम के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, किसी कर्मचारी को निम्नलिखित प्रकारों की छुट्टी अनुदान की जा सकेगी :—

- (क) आकस्मिक छुट्टी;
- (ख) उपाजित छुट्टी;
- (ग) बीमारी छुट्टी;
- (घ) प्रसूती छुट्टी;
- (ङ) परीक्षा छुट्टी;
- (च) वारन्तीन छुट्टी;
- (छ) व्यवसाय गप छुट्टी।

(2) किसी कर्मचारी को छुट्टी निम्नलिखित साधारण विधानों के अनुकूल दी जाएगी :—

- (क) छुट्टी कर्मचारी या सेवा द्वारा उपाजित की जानी है;
- (ख) छुट्टी का दावा अधिकारस्वरूप नहीं किया जा सकता है;
- (ग) यदि निगम या उसके किसी समतुल्य की सेवा की अभ्या-वश्यकताओं से ऐसी अपेक्षा हो तो, किसी प्रकार की छुट्टी को ठकार करने या प्रतिमंडित करने का विवेकाधिकार उसे भुजूर करने के लिए, मशकत प्राधिकारों के पास आरक्षित है।

टिप्पण :—छुट्टी की मंजूरी की उपधारा नहीं की जा सकेगी और मांगी गई छुट्टी का उपयोग तब तक नहीं किया जा सकेगा जब तक कि उसे विनिर्दिष्टतः मंजूर नहीं किया गया हो;

- (घ) यह अनुज्ञेय होगा कि किसी प्रकार की छुट्टी से अवकाशदिनों या शनिवारों को पड़ने या बाद में जोड़ लिया जाए;

(४) आकस्मिक छुट्टी का उपयोग किसी अन्य प्रकार की छुट्टी के साथ नहीं किया जाएगा। इस मामले के अधीन रहते हुए, इस स्कीम के अधीन किसी प्रकार की छुट्टी की मंजूरी किसी अन्य प्रकार की छुट्टी के साथ, या क्रम में दी जा सकती है।

(3) **उपाजित छुट्टी** :—(क) प्रत्येक कर्मचारी, निरंतर सेवा के प्रत्येक वर्ष के लिए 30 दिन की उपाजित छुट्टी का हकदार होगा।

(ख) अधिकतम 120 दिन तक की छुट्टी किसी एक समय मंजूर की जा सकती है।

(ग) उपाजित छुट्टी की यह अवधि, जो किसी कर्मचारी द्वारा संचित की जा सकती है, 180 दिन की होगी।

(4) **आकस्मिक छुट्टी** :—(क) किसी कर्मचारी को किसी कलेंडर वर्ष में अधिकतम 15 दिन की आकस्मिक छुट्टी अनुदान की जा सकती है, किन्तु किसी समय 6 दिन से अधिक नहीं होगी। आकस्मिक छुट्टी का उपयोग सामान्यतः सक्षम प्राधिकारी द्वारा मंजूर किए जाने के पश्चात् ही किया जा सकता है; किन्तु एक दिन की आकस्मिक छुट्टी का उपयोग अनवस्थित आवात की दशा में पूर्व मंजूरी के बिना किया जा सकता है, परन्तु यह तब जब कि कार्यालय के प्रधान को उन परिस्थितियों के बारे में जिनमें पूर्व मंजूरी नहीं ली जा सकती, पीछे सूचित किया जाना है।

(ख) किसी सप्ताह दिन को या नौ केवल पूर्वार्द्ध या अपराह्न के लिए आकस्मिक छुट्टी का उपयोग करना अनुमति है, उस दशा में छुट्टी की वह अवधि आधा दिन मानी जाएगी, किन्तु शनिवार को या किसी ऐसे दिन को, जब कि आधे दिन के अवकाश की घोषणा की गई है, तो यह छुट्टी पूर्ण दिन के रूप में मानी जाएगी।

(5) **बीमारी छुट्टी** :—कोई कर्मचारी ऐसे, चिकित्सीय प्राधिकारी द्वारा, जो अभिरक्षक या प्रबन्ध निदेशक द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए, दिए गए चिकित्सीय प्रमाणपत्र पर बीमारी छुट्टी का हकदार होगा। कर्मचारी प्रति वर्ष 30 दिन के हिसाब से बीमारी छुट्टी का हकदार होगा और बीमारी की छुट्टी वह अवधि, जो किसी कर्मचारी द्वारा संचित की जा सकती है, अधिकतम 240 दिन की होगी।

(6) **प्रसूति छुट्टी** :—कोई महिला कर्मचारी 90 दिन से अधिक प्रसूति छुट्टी का हकदार होगी। प्रसव-पूर्व और प्रसव-पश्चात् की अवधियों के बीच छुट्टी विस्तार कर्मचारी की सुविधा पर छोड़ दिया जाएगा।

परन्तु यदि कोई ऐसी महिला कर्मचारी, जिसके तीन जीवन बच्चे हों, प्रसव के लिए छुट्टी लेती है, तो ऐसी छुट्टी उपाजित छुट्टी के रूप में मानी जाएगी और यदि उपाजित छुट्टी अनुमति न हो तो उस दशा में बीमारी छुट्टी के रूप में मानी जाएगी, जबकि ऐसी बीमारी छुट्टी अनुमति होगी।

(7) **परीक्षा छुट्टी** :—बीमा परीक्षा में बैठने वाले कर्मचारी को परीक्षा की वास्तविक कालावधि के लिए परीक्षा छुट्टी का उपयोग करने की अनुमति दी जा सकती है और यदि काम के स्थान से विश्रुत स्थान को परीक्षा में बैठने के लिए यात्रा करना आवश्यक हो तो, निकटतम केंद्र को जाने और वहां से लौटने के लिए निम्नतम यात्रा-समय को भी परीक्षा छुट्टी के रूप में माना जाएगा।

(8) **करन्तीन छुट्टी** :—अभिरक्षक या प्रबन्ध निदेशक या अभिरक्षक या प्रबन्ध निदेशक द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत कोई अन्य अधिकारी गुण-गुण के आधार पर करन्तीन छुट्टी की प्रार्थना पर विचार कर सकेगा, किन्तु कोई भी कर्मचारी ऐसी छुट्टी का दावा अधिकाररूप नहीं करेगा।

(9) **व्यवसाय संघ छुट्टी** :—(क) किसी मान्यताप्राप्त संघ के और ऐसे संघ द्वारा नामनिर्दिष्ट कम से कम 15 व्यक्तियों में से प्रत्येक व्यक्ति को

सद्व्यवसायिक व्यवसाय संघ के कार्य के लिए विशेष छुट्टी प्रति वर्ष अधिक से अधिक 15 दिन तक, वास्तविक यात्रा समय घटा कर, मंजूर की जा सकती है।

(ख) खण्ड (क) में निर्दिष्ट मान्यताप्राप्त संघ के और ऐसे संघ द्वारा नामनिर्दिष्ट कम से कम 20 अन्य व्यक्तियों में से प्रत्येक व्यक्ति को समरूप प्रयोजनार्थ विशेष छुट्टी प्रति वर्ष अधिक से अधिक 10 दिन तक, वास्तविक यात्रा समय घटाकर, मंजूर की जा सकती है।

11 **भविष्य निधि** :—प्रत्येक कर्मचारी अपने मूल वेतन और महंगाई भत्ते के 8 प्रतिशत के हिसाब से भविष्य निधि में अभिदाय करेगा और निगम या उसके किसी समतुल्यी द्वारा समान अभिदाय किया जाएगा।

12 **सेवानिवृत्ति** :—सेवानिवृत्ति की सामान्य आयु 60 वर्ष की होगी

परन्तु कोई ऐसा कर्मचारी, जो किसी मामले के दौरान 60 वर्ष की आयु का हो जाता है, ठीक अपने मामले के प्रथम दिन को ही सेवानिवृत्त होगा।

13. **उपदान** :—उपदान संदाय अधिनियम, 1972 (1972 का 19) के उपबन्धों के अनुसार किसी कर्मचारी को उपदान संदाय किया जाएगा :

परन्तु निम्नलिखित शर्तों के अधीन रहते हुए, इस स्कीम के अधीन संदाय उपदान किसी भी दशा में 20 मास की मजदूरी या 20,000 रु० से जो भी कम हो, अधिक नहीं होगा :—

(i) जहां किसी कर्मचारी द्वारा अन्तिम की गई मजदूरी 1,000 रु० से अधिक है तो इसे उपदान की मात्रा अवधारित करने के प्रयोजन के लिए 1,000 रु० समझा जाएगा; और

[(ii) वह दर, जिस पर उपदान संदाय किया जाएगा निम्न अनुसार वह जाएगी :—

सेवा के पूरे किए गए वर्षों की संख्या	मास की मजदूरी की संख्या में सेवा के प्रत्येक वर्ष के लिए उपदान की दर
--------------------------------------	--

12	0.6
13	0.7
14	0.8
15 या अधिक	1.0

स्पष्टीकरण :—इस पैरा में, "मजदूरी" का वही अर्थ होगा जो उसे उपदान संदाय अधिनियम, 1972 (1972 का 39) की धारा 2 के खण्ड (घ) में दिया गया है।

14 **अतिरिक्तिक भत्ता** :—जब कभी भी कार्यालय के काम के हिस्से में यह आवश्यक पाया जाए, तो कर्मचारी से प्रसामान्य काम के घंटों से परे काम करने की अपेक्षा की जा सकती है। जब किसी कर्मचारी से किसी दिन उसके प्रसामान्य काम के घंटों के पश्चात् आधे घंटे से अधिक काम करने के लिए अपेक्षा की जाती है तो उसे निम्नानुसार परिकल्पित अतिरिक्तिक भत्ता संदाय किया जाएगा :—

(क) **पर्यवेक्षी और लिपिकीय कर्मचारियों** :—जब अतिरिक्तिक घंटों की संख्या 42 काम-घंटे से अधिक न हो, जिसके अन्तर्गत रविवार से शनिवार एक सप्ताह के दौरान प्रसामान्य काम काज के घंटे भी सम्मिलित हैं :—

(i) मास के लिए मजदूरी की दर प्रति घंटा डेढ़ गुणा होगी,

(ii) 12 घंटों में अधिक काम के अतिरिक्त घंटों के लिए, जिसमें सप्ताह के दौरान प्रसामान्य काम घंटे भी सम्मिलित है—मास के लिए मजदूरी की दर प्रति घंटा दूगुणी होगी,

(ख) अधिसूचक कर्मचारियों—जब अतिरिक्त घंटों की सख्या सप्ताह के दौरान प्रसामान्य काम के घंटों को मिलाकर 45 घंटों में अधिक न हो तब—

(i) मास के लिए मजदूरी की दर प्रति घंटा डेढ़ गुणा होगी,

(ii) 45 घंटों में अधिक काम के अतिरिक्त घंटों के लिए, जिसमें सप्ताह के दौरान प्रसामान्य काम-घंटे भी सम्मिलित है—मास के लिए मजदूरी की दर प्रति घंटा दूगुणी होगी।

(ग) चालक और निर्माण कर्मचारियों—जब सप्ताह के दौरान काम के अतिरिक्त घंटों की सख्या 7 घंटे से अधिक न हो तो—

(i) मास के लिए मजदूरी की दर प्रति घंटा डेढ़ गुणा होगी,

(ii) सप्ताह के दौरान 7 घंटे से अधिक काम के अतिरिक्त घंटों के लिए—मास के लिए मजदूरी की दर प्रति घंटा दूगुणी होगी।

(घ) साधारण—अवकाश दिनों और रविवारों को किए गए अतिरिक्त काम के लिए संघाय उसी आधार पर किया जाएगा जैसे अन्य दिनों के लिए है। किन्तु, रविवार को किए गए काम के लिए प्रतिश्रुत्यात्मक अवकाश दिन, अतिरिक्त भत्ता के सदाय के अतिरिक्त अगले सप्ताह के दौरान दिया जाएगा।

टिप्पणः—अतिरिक्त की अवधि की निकटतम आधे घंटे पर पूर्णांकित किया जाएगा।

टिप्पणः—किसी भी कर्मचारी को, किसी कर्मचारी वर्ष में 90 घंटे से अधिक अतिरिक्त में काम करने के लिए नहीं कहा जाएगा।

15 स्थानापन्न भत्ता :—किसी कर्मचारी से किसी उच्चतर प्रवर्ग में किसी पद का स्थानांतरण रूप में भारसाधन धारण करने या समतुल्य पद का अतिरिक्त भारसाधन धारण करने की, जब कभी भी आवश्यक समझा जाए, अपेक्षा की जा सकेगी और जहां ऐसा स्थानापन्न रूप में भारसाधन या अतिरिक्त भारसाधन 15 दिन या अधिक की निरंतर अवधि के लिए किया जाता है वहां कर्मचारी को निम्नलिखित रूप में अनुपातिक भत्ता दिया जाएगा, अर्थात् :—

(i) उच्चतर प्रवर्ग पद पर स्थानापन्न किया जाता : प्रतिमास 100 रु० की अधिकतम रकम सीमा में रहते हुए अपने मूल वेतन का 20 प्रतिशत।

(ii) किसी समतुल्य पद का अतिरिक्त भारसाधन : प्रतिमास 50 रु० की अधिकतम रकम सीमा में रहते हुए अपने मूल वेतन का 10 प्रतिशत।

टिप्पणः—यदि कर्मचारी ऐसे पद पर स्थानापन्न रूप में कार्य कर रहा है या वह ऐसे पद का अतिरिक्त भारसाधन धारण करता है जिस पर कुनियक भत्ता दिया जाता है तो कर्मचारी उस अवधि के लिए जिसके लिए वह स्थानापन्न रूप में कार्य

करता है या भारसाधन करता है, अनुपातिक कुनियक भत्ता प्राप्त करेगा।

16. यात्रा भत्ता :—किसी कर्मचारी से शासकीय कार्य के लिए दूरी पर जाने की अपेक्षा की जा सकेगी। यात्रा भत्ता और बिराम भत्ता की दरें तथा वे शर्तें जिनके अधीन वे संदेय होंगी, द्वितीय अनुसूची में यथा विनिर्दिष्ट होंगी।

17. छुट्टी यात्रा सहायकी :—छुट्टी यात्रा सहायकी की दरें और वे शर्तें जिनके अधीन ऐसी सहायकी संदेय होंगी, तृतीय अनुसूची में यथा विनिर्दिष्ट होंगी।

17. स्थानांतरण और कार्य-स्थान का परिवर्तन :—अभिरक्षक या प्रबन्ध निदेशक या अभिरक्षक या प्रबन्ध निदेशक द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत कोई अधिकारी, किसी कर्मचारी का एक विभाग से दूसरे में या किसी कंपनी या निगम के एक कार्यालय से उस कंपनी या किसी अन्य कंपनी या निगम के दूसरे कार्यालय में स्थानांतरण कर सकेगा।

19 कार्य-भार, मासिक और पंजीकरण :—(1) कार्य-भार का ढांचा और कार्य-माप की पद्धति ऐसी होंगी, जो प्रबन्ध निदेशक द्वारा संघों से परामर्श करने पश्चात् विनिर्दिष्ट की जाए।

(2) प्रबन्ध निदेशक, संघों से परामर्श करने के पश्चात् छंटनी किए बिना ठीक-ठीक कार्यकरण के लिए आवश्यक विस्तार तक यंत्रीकरण पुर-स्थापित कर सकेगा।

20. उत्सव-अग्रिम—किसी कर्मचारी का निम्नलिखित शर्तों के अधीन रहते हुए उत्सव-अग्रिम अनुवर्त किया जा सकेगा, अर्थात् :—

(क) उत्सव-अग्रिम प्रत्येक कलेंडर वर्ष के दौरान केवल एक बार अनुवर्त किया जाएगा;

(ख) कोई अग्रिम तब तक अनुवर्त नहीं किया जाएगा जब तक कि पहले लिया गया अग्रिम पूर्ण रूप से न चुका दिया गया हो;

(ग) अग्रिम की रकम एक मास के कुल वेतन या 400 रु०, से जो भी कम हो, अधिक नहीं होगी;

(घ) अग्रिम को व्याज के बिना अधिक से अधिक दस मासिक किस्तों में चुका दिया जाएगा, जो उस मास से, जिसमें अग्रिम लिया गया है, प्रारम्भ होगा।

21. निर्बंधन :—यदि इस स्कीम के उपबन्धों में से किसी के निर्धारण के बारे में कोई शंका या कठिनाई उद्भूत हो तो, हमें केन्द्रीय सरकार को विनिश्चय के लिए निर्दिष्ट किया जाएगा और वह सरकार उसका विनिश्चय करेगी।

22 शिथिल करने की शक्ति :—जहां प्रबन्ध निदेशक का समाधान हो जाए कि इस स्कीम के उपबन्धों में से किसी उपबन्ध के प्रवर्तन से किसी विशिष्ट मामले में कठिनाई होगी, तो वह प्रादेश द्वारा और लेखबद्ध कारणों के आधार पर उस उपबन्ध की अपेक्षाओं को ऐसी सीमा तक और ऐसे अपवाद और शर्तों के अधीन रहते हुए जिन्हें वह मामले का न्यायसंगत और साम्यिक रीति से विचार करने के लिए आवश्यक समझे, छूट दे सकेगा यदि शिथिल कर सकेगा।

23. नये वेतनमान की अवधि :—नया वेतनमान प्रारम्भिक रूप से 31 दिसम्बर, 1976 तक जिसमें यह दिन भी सम्मिलित है, प्रवृत्त रहेगा और तत्पश्चात् तब तक प्रवृत्त रहेगा जब तक केन्द्रीय सरकार द्वारा उगमें परिवर्तन नहीं किया जाता।

24. **अन्य सुविधाएं** :—कोई कर्मचारी ऐसी किसी सुविधा को पाने का हकदार नहीं होगा जो इस स्कीम से उद्भूत नहीं होती है।

25. **मध्यारोही प्रभाव** :—तत्समय प्रवृत्त किसी करार, पंचाट या अन्य लिखत में अन्तर्विष्ट कोई बात विरोध में होने हुए भी इस स्कीम के उपबन्धों प्रभावी होंगे।

प्रथम अनुसूची

I. बेतनमान (मूल बेतन)

क. पर्यवेक्षीय और लिपिकीय कर्मचारिवृत्त :—
(पैरा 3 देखिये)

1. अधीक्षक

330-25-405-30-525-35-665-40-865 रु०

2. उपेक्ष सहायक

230-15-275-20-335-25-485-द०रो०-30-665-35-735 रु०

3. आशुलिपिक

230-15-275-20-335-25-485-द०रो०-30-665-35-735 रु०

4. सहायक, टंकक, टेलीफोन ऑपरेटर, टेलिक्स ऑपरेटर, स्वागती, पंच कार्ड ऑपरेटर, यूनिट अभिलेख मशीन ऑपरेटर, परिकल्पन-यंत्र-प्रचालक, और अन्य समतुल्य पद : 175-10-235-15-295-20-395-द०रो०-25-495-30-585 रु०

5. अभिलेख लिपिक

165-6-177-7-191-8-215-9-260-10-300-15-390 रु०

ख. अधिनस्थ कर्मचारिवृत्त :—

(1). चासक

166-5-181-6-199-7-234-8-274-9-310 रु०

(2) अन्य अधिनस्थ कर्मचारिवृत्त

125-5-165-6-201-7-229-8-245 रु०

II. कृत्यिक भत्ता

अपने नियमित और मुख्य कृत्य के रूप में निम्नलिखित कृत्यों में से किसी में नियुक्ति कर्मचारियों को नीचे उपर्युक्त रूप में कृत्यिक भत्ता दिया जाएगा :—

- (1) लिफ्टमैन, मशीन ऑपरेटर, प्रधान जपरामियों, जमादार या वानरियों के रूप में कार्य करने वाले अधीनस्थ कर्मचारिवृत्त 20 रु० प्रतिमास
- (2) बैंक में रोकड़ ले जाने या ले जाने वाले अधीनस्थ कर्मचारिवृत्त, जब किसी क्लैण्डर मास के दौरान ले जाए गए रोकड़ की रकम सामान्यतः 25,000 रु० या अधिक हो 10 रु० प्रतिमास
- (3) किसी कार्यालय में रोकड़ संभालने वाला रोकड़-डिया जब किसी क्लैण्डर मास के दौरान रोकड़-संव्यवहार की कुल रकम सामान्यतः 25,000 रु० या अधिक हो 25 रु० प्रतिमास
- (4) टेलिक्स ऑपरेटर, पंच कार्ड ऑपरेटर और यूनिट अभिलेख मशीन ऑपरेटर 25 रु० प्रतिमास
- (5) परिकल्पन-यंत्र प्रचालक 25 रु० प्रतिमास
- (6) नियम के अध्यक्ष, प्रबन्ध निदेशक, अभिरक्षक, महाप्रबन्धक, सहायक महाप्रबन्धक और समतुल्य पदों के आशुलिपिक 40 रु० प्रतिमास

टिप्पण 1:—कृत्यिक भत्ता लेने के लिए पात्र व्यक्तियों की संख्या और नाम का अध्याकरण, अभिरक्षक या प्रबन्ध निदेशक द्वारा किया जाएगा, जो कार्य की मात्रा और प्रशासनिक आवश्यकताओं पर आधारित होगा।

टिप्पण 2:—कोई कर्मचारी, किसी एक समय केवल एक कृत्यिक भत्ता लेगा।

टिप्पण 3:—छुट्टी पर जाने वाला कोई कर्मचारी अपनी छुट्टी अवधि के दौरान कृत्यिक भत्ता लेता रहेगा, परन्तु यह तब जब कि वह अपनी छुट्टी की समाप्ति पर उसी पद पर कार्य करें।

टिप्पण 4:—कोई भी कर्मचारी, अधिकार स्वस्थ, उस पद से संलग्न कृत्यिक भत्ते का उपयोग करने के लिए कोई विशिष्ट कार्यभाग का आवंटन किए जाने का दावा नहीं करेगा।

टिप्पण 5:—कोई भी कर्मचारी, कृत्यिक भत्ता वाले पद पर कार्य करने से इस्तीफा नहीं करेगा या यह नहीं रखेगा कि उसे वहां ऐसा भत्ता दिया जाए, जहां पदधारी की अनुपस्थिति या अस्थायी कार्यभार के कारण कर्मचारी को उसके कार्यालय के प्रधान द्वारा ऐसा कार्य सम-नुविष्ट किया गया है।

III. मंहगाई भत्ता

कर्मचारियों को लागू मंहगाई भत्ते के मान का अध्याकरण निम्नानुसार होगा :

सूचकांक :—भारतीय थ्रम पत्रिका में यथा प्रकाशित औद्योगिक कर्मचारियों के लिए अखिल भारतीय औद्योगिक उपभोक्ता कीमत सूचकांक आधारित वर्ष : 1960-100

(2) मंहगाई भत्ते की दर :—प्रत्येक क्लैण्डर तिमाही, अर्थात् जनवरी से मार्च, अप्रैल से जून, जुलाई से सितम्बर और अक्टूबर से दिसम्बर के दौरान कर्मचारियों को संवेय मंहगाई भत्ता ठीक पूर्ववर्ती क्लैण्डर तिमाही के सूचकांक के औसत पर आधारित होगा। इस प्रकार अप्रैल, मई और जून के लिए मंहगाई भत्ता पूर्ववर्ती जनवरी, फरवरी और मार्च के औसत पर आधारित होगा और इस प्रकार यह क्रम चलता रहेगा। तिमाही औसत सूचकांक और 100 पर आधारित सूचकांक के बीच के अन्तर को चार द्वारा विभाजित किया जाएगा और इस प्रकार अभिप्राप्त पूर्ण भजनफल को निम्नवर्णित प्रतिशत के लिए गुणक के रूप में प्रयुक्त किया जाएगा :—

मूल बेतन रेंज	मंहगाई भत्ते की दर
(i) जहां कर्मचारी का मूल बेतन 245 रु० या कम है	मूल बेतन का 4 प्रतिशत
(ii) जहां कर्मचारी का मूल बेतन 245 रु० से अधिक है किन्तु 700 रु० कम से कम है	मूल बेतन का तीन प्रतिशत, जिसकी न्यूनतम राशि 9.80 रु० होगी (अर्थात् जो 245 रु० का चार प्रतिशत है)
(iii) जहां कर्मचारी का मूल बेतन 700 रु० से अधिक है।	700 रु० का 3 प्रतिशत और अनिशेष का 2 प्रतिशत।

(3) मंहगाई भत्ते का पुनरीक्षण :—मंहगाई भत्ते का पुनरीक्षण प्रत्येक चार अरब बड़ों या घटने पर विमर्श आधार पर किया जा सकेगा।

IV. अर्हता बेतन

कर्मचारी को मासिक भत्ता, जिसे अर्हता बेतन कहा जाएगा, अनुदान किया जाएगा या निम्नलिखित आधार पर बेतन-वर्तियां अनुदान की जाएगी :

(1) इस स्कीम के प्रारम्भ होने पर विद्यमान अस्नातक मशायको को, जो 1 जनवरी, 1973 से पांच वर्ष के भीतर स्नातकों के रूप में अर्हित हो जाते हैं, परीक्षा के परिणाम के प्रकाशन की तारीख से उनके वेतनमान में दो वेतन वृद्धियाँ अनुदान की जाएगी।

(2) परिणाम के प्रकाशन की तारीख से निम्नलिखित बीमा परीक्षा में अर्हित करने वाले किसी कर्मचारी को निम्न यथा-उपदर्शित अर्हता वेतन की रकम संदेय की जाएगी :

परन्तु एक अर्हता वेतन से अधिक उसे अनुभेय नहीं किया जाएगा।

परीक्षा	प्रति माह अर्हता वेतन
बीमा संस्थान परिसर या चार्टर्ड बीमा संस्थान	
(i) अनुज्ञतिधारी	केवल मशायको या समतुल्य या निम्नतर पदों को संदेय 15 रु०
(ii) एसोसिएटशिप के पूरा करने पर	केवल ज्येष्ठ सहायकों या समतुल्य या निम्नतर पदों को संदेय 25 रुपये
(iii) फेलोशिप के पूरा करने पर	50 रु०
बीमांकक संस्थान	
(iv) कोई तीन विषय	25 रु०
(v) कोई सात विषय	40 रु०
(vi) फेलोशिप के पूरा करने पर	60 रु०
चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थान या लागत और संकर्म सेवा संस्थान	
(vii) इण्टरमीडिएट पूरा करने पर	25 रु०
(viii) एसोसिएटशिप या फेलोशिप के पूरा करने पर	50 रु०

(3) इस स्कीम के प्रारम्भ होने पर या के पश्चात् सहायकों को प्रवर्ग में या समतुल्य पदों पर नियुक्ति व्यक्तियों को —

(क) सेवा में उनके पुष्टिकरण की तारीख से, यदि वे पुष्टिकरण के पूर्व स्नातकों के रूप में सेवा ग्रहण करते हो या अर्हित होते हों ;

(ख) परिणामों के प्रकाशन की तारीख से, यदि वे सेवा ग्रहण करने की तारीख से पांच वर्ष की अवधि के भीतर स्नातकों के रूप में अर्हित होते हों,

उस श्रेणी में दो वेतन-वृद्धियाँ दी जाएगी।

(4) अर्हता वेतन के अनुदान या स्नातक होने पर वेतन-वृद्धियों से सम्बन्ध व्यक्तियों की उपेक्षा प्रभावित नहीं होगी।

(5) यदि किसी कर्मचारी को अधिक वेतन-वृद्धि या किसी बीमा परीक्षा में अर्हित हो जाने पर कोई अन्य आवश्यक फायदा पहले ही दिया गया हो तो अर्हता वेतन की रकम उपयुक्त रूप से कम कर दी जाएगी या अनुभेय नहीं होगी, यह पहले ही प्राप्त फायदे की मात्रा पर निर्भर होगा।

उदाहरण: यदि किसी सहायक ने बीमा संस्थान परिसर की अनुज्ञति और एसोसिएटशिप परीक्षाओं के पूरा करने के लिए दो वेतन-वृद्धियाँ ले

नी है, जिनका धनीय मूल्य (क) 20 रु० है तो—वह अर्हता वेतन प्रतिमास 5 रु० प्राप्त करेगा,

(ख) 30 रु० है तो—वह कोई अर्हता वेतन प्राप्त नहीं करेगा।

V. गृह भाटक भत्ता

कर्मचारियों को बावत गृह भाटक भत्ता, प्रति मास 10 रु० की अधिकतम रकम के अधीन रहते हुए, मूल वेतन के 10 प्रतिशत पर संदेय होगा। अधीनस्थ कर्मचारिवृन्द के लिए निम्नतम गृह भाटक भत्ता 22 रु० और पर्यवेक्षी तथा निपिकीय कर्मचारिवृन्द के लिए 28 रु० होगा।

VI. नगर प्रतिकरात्मक भत्ता :

केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर इस प्रकार घोषित सभी वर्ग 'क' और वर्ग 'ख' के नगरों में तैनात सभी कर्मचारियों को नगर प्रतिकरात्मक भत्ता प्रति मास 20 रु० की दर से संदेय होगा।

VII. पहाड़ी स्थान भत्ता :

धीनगर, धर्मशाला, बारामुल्ला, अन्नन्ताम, पालनपुर, शिमला, भस्मोड़ा, तैनाल, शिलांग, दांग्रिलिंग, काठमांडू, आठकामंडू और सरकारा में तैनात कर्मचारियों को, प्रतिमास निम्नतम 20 रु० और प्रतिमास 75 रु० की अधिकतम सीमा में रहते हुए, उनके मूल वेतन के 15 प्रतिशत की दर से प्रत्येक मास पहाड़ी स्थान भत्ता दिया जाएगा।

VIII. किट भत्ता :

पैरा vii में सूचीबद्ध पहाड़ी स्थानों में से किसी स्थान को स्थानान्तरित कर्मचारियों को 200 रु० का किट भत्ता दिया जाएगा।

किट भत्ता एक पहाड़ी स्थान से दूसरे पहाड़ी स्थान को स्थानान्तरण पर या यदि ऐसा भत्ता पूर्वगामी 3 वर्ष के दौरान किसी समय लिया गया था तो, संदेय नह होगा।

IX. बर्दी और धुलाई भत्ता :

अधीनस्थ कर्मचारिवृन्द जिसमें चालक भी सम्मिलित है को बर्दियों का दिया जाना और धुलाई करने या धुलाई भत्ता के सहाय की व्यवस्था निम्नानुसार विनियमित होगी :

(i) कार्यालय बर्दिया अधीनस्थ कर्मचारिवृन्द जिसमें चालक भी सम्मिलित है, को दी जा सकेगी।

(ii) सूती बर्दी के 3 सेट प्रत्येक वर्ष एक बार अधीनस्थ कर्मचारिवृन्द जिसमें चालक भी सम्मिलित है, को दिए जा सकेंगे। उन स्थानों में जो प्रबन्ध निदेशक द्वारा ऐसे स्थान विनिश्चित किए गए हैं जहाँ सर्दी अधिक पड़ती है, एक सूती बर्दी के बदले एक ऊनी बर्दी दी जा सकेगी और प्रत्येक दो वर्षों में नवीकृत की जा सकेगी।

(iii) उस कर्मचारी को, जिसे बर्दी दी गई है, वर्ष में एक बार एक जोड़ी जूतन दी जा सकेगी। जहाँ ऊनी बर्दी दी गई है, वहाँ जूतने के अनिवार्य दो वर्षों में एक बार एक जोड़े जूते दिए जा सकेंगे। जहाँ जूते दिए गए हैं वहाँ, दो जोड़े मोजे भी प्रत्येक वर्ष दिए जा सकेंगे। प्रत्येक अनुकूल्य वर्ष में एक बार एक छाता भी दिया जा सकेगा।

(iv) जहाँ निगम या उसका कोई समनुषंगी, बर्दियों की धुलाई या सफाई करने की व्यवस्था नहीं करता वहाँ कर्मचारी को सुखई, कालकत्ता, बिल्ली और मस्राग में प्रतिमास 7 रु० और अन्य स्थानों में प्रतिमास 5 रु० की दर से धुलाई भत्ता अनुवत किया जा सकेगा। जहाँ ऊनी बर्दियाँ दी जाती हैं वहाँ उसके अनिवार्य वर्ष में एक बार वास्तविक ड्राईक्लीनिंग-प्रकार की प्रतिपूर्ति की जा सकेगी।

द्वितीय अनुसूची

(पैरा 6 देखिये)

1. कर्त्तव्याङ्क होने के दौरान यात्रा और विराम भत्ता के लिए हकदारी का विनियमन नीचे यथा उपदर्शित रूप में किया जाएगा।

क. यात्रा भत्ता

(1) रेल द्वारा यात्रा

प्रवर्ग	यात्रा का ऋग और श्रेणी
(i) 340 रु० और अधिक मूल वेतन वाले कर्मचारी	प्रथम श्रेणी
(ii) 340 रु० से कम मूल वेतन वाले कर्मचारी, जिनमें अधीनस्थ कर्मचारिवृन्द नहीं है	श्रेणी 2 या ए सी श्रेणी 3*
(iii) अधीनस्थ कर्मचारिवृन्द	तृतीय श्रेणी

*जहाँ श्रेणी 2 या ए सी श्रेणी 3 की व्यवस्था रेलवे द्वारा नहीं की गई है वहाँ, श्रेणी 1 द्वारा यात्रा अनुज्ञात की जा सकेगी। और, जहाँ यात्रा में रात की यात्रा भी सम्मिलित है वहाँ समस्त यात्रा श्रेणी 1 द्वारा करनी अनुज्ञेय होगी।

2. स्टीमर द्वारा यात्रा

(i) 600 रु० से अधिक मूल वेतन वाले कर्मचारी	उच्चतम श्रेणी
(ii) 340 रु० और अधिक मूल वेतन वाले किन्तु 600 रु० से कम मूल वेतन वाले कर्मचारी	दोनों श्रेणियों में से जो उच्चतर हो, और जहाँ दो श्रेणियों से अधिक की व्यवस्था हो वहाँ मध्यवर्ती या द्वितीय श्रेणी
(iii) 340 रु० से कम मूल वेतन वाले सभी कर्मचारी (अधीनस्थ कर्मचारिवृन्द से भिन्न)	दोनों श्रेणी में से जो निम्नतर हो, और जहाँ तीन श्रेणियाँ हो वहाँ मध्यवर्ती या द्वितीय श्रेणी यदि चार श्रेणियाँ हो तो तृतीय श्रेणी।
(iv) अधीनस्थ कर्मचारिवृन्द	निम्नतम श्रेणी

(3) सड़क द्वारा यात्रा

एकल स्थान लेकर वाक परिवहन द्वारा *वास्तविक भाड़ा

*अधीनस्थ कर्मचारिवृन्द के सिवाय सभी कर्मचारियों के लिए उच्चतर श्रेणी द्वारा, यदि उनकी व्यवस्था हो।

ख. विराम भत्ता

(क) विराम भत्ते की दर निम्नलिखित रूप में होगी, अर्थात्—

प्रवर्ग	रकम
(1) अधीनस्थ कर्मचारिवृन्द	प्रतिदिन 10 रु०
(2) अधीनस्थ कर्मचारिवृन्द से भिन्न कर्मचारी	
(i) 151-340 रु० के बीच मूल वेतन	प्रतिदिन 15 रु०
(ii) 341-600 रु० के बीच मूल वेतन	प्रतिदिन 25 रु०
(iii) 600 रु० से अधिक मूल वेतन	प्रतिदिन 30 रु०

(ख) उपर्युक्त विराम भत्ता में 25 प्रतिशत की वृद्धि मुम्बई, कलकत्ता, दिल्ली और मद्रास में अनुज्ञात की जाएगी।

(ग) मुख्यालयों से प्रत्येक 24 घंटे की अनुपस्थिति के लिए पूर्ण विराम भत्ता दिया जाएगा, अनुपस्थिति की अवधि, यात्रा प्रारम्भ करने के समय से और मुख्यालय लौटने के समय तक संगणित की जाएगी।

(घ) 24 घंटे से कम के लिए विराम भत्ता निम्नलिखित मान पर होगा :

(i) 12 घंटे के अधिक की अनुपस्थिति	पूर्ण
(ii) 6 घंटे से अधिक किन्तु 12 घंटे से अधिक की अनुपस्थिति	विराम भत्ते का 50 प्रतिशत
(iii) 6 घंटे से कम	विराम भत्ते का 30 प्रतिशत

(ङ) कर्मचारी पर मुख्यालयों से प्रथम 30 दिन की अनुपस्थिति के लिए विराम भत्ता पूरी दरों पर और तत्पश्चात् 90 दिन की अधिकतम अवधि तक प्रमामान्य दरों की आधी दर पर अनुज्ञात किया जाएगा।

(च) ऐसे कर्मचारियों की दशा में, जो निगम या उसके किसी समनुषंगी द्वारा घोषित अतिथि गृहों में ठहरते हैं, यदि खाने या ठहरने की व्यवस्था मुफ्त हो तो विराम भत्ता प्रमामान्य दर की आधी दर पर और यदि खाने और ठहरने, दोनों की व्यवस्था मुफ्त हो तो प्रमामान्य दर की एक-चौथाई दर पर होगा।

11. स्थानान्तरण पर यात्रा भत्ता

भत्ता की दर और अन्य सुगम शर्तें निम्नानुसार होंगी :

(क) कर्मचारी और उसके कुटुम्ब को उस यात्रा श्रेणी द्वारा, जिसके लिए कर्मचारी बीरे पर यात्रा करने के लिए हकदार है, यात्रा भत्ता अनुज्ञात किया जाएगा।

(ख) यात्रा के लिए अनुपयोगिक हेतु, यात्रा पर बिताए गए समय के लिए कर्मचारी और उसके कुटुम्ब के सदस्यों को विराम भत्ता अनुज्ञात किया जाएगा। 12 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए विराम भत्ता की हकदारी आधी दर पर होगी।

(ग) स्थानान्तरण पर कार्य ग्रहण करने का समय निम्नलिखित रूप में अनुज्ञात किया जाएगा :

(i) यदि कोई निवास-स्थान में परिवर्तन न हो तो एक दिन, इस प्रयोजन के लिए रविवार या अवकाश दिन को एक दिन के रूप में गिना जाएगा।

(ii) यदि एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन को जाने के कारण निवास-स्थान में परिवर्तन होना हो तो तैयारी के लिए 6 दिन और यात्रा भग किये बिना विभिन्न प्रकार के परिवहन द्वारा की गई यात्रा का वास्तविक समय।

(घ) निजी सामान के परिवहन पर व्ययों की प्रतिपूर्ति निम्नलिखित आधार पर होगी—

मूल वेतन लेने वाले कर्मचारियों के लिए कुटुम्ब सहित	कुटुम्ब के बिना
600 रु० से अधिक	20 क्वीटल
151 रु०—600 रु० के बीच	15 क्वीटल
150 रु० तक	6 क्वीटल
	10 क्वीटल
	7.5 क्वीटल
	2.5 क्वीटल

सामान मासगाड़ी द्वारा या यात्री गाड़ी द्वारा या यदि रेल परिवहन उपलब्ध न हो तो, परिवहन के अन्य प्रकार द्वारा इन शर्तों के अधीन ले जाया जा सकेगा कि परिवहन का खर्च, मासगाड़ी द्वारा अनुज्ञेय अधिपत राशि से अधिक न हो।

(इ) मनुक द्वारा परिवहन की दर, प्रत्येक 3.5 कि० ग्रा० या उसके भाग के लिए प्रति कि० मी० 3 पैसे होगी।

नियाम-स्थान में रेलवे स्टेशन तक और रेलवे स्टेशन में निवास स्थान तक सामान की हवाई के लिए वही दर लागू होगी।

(च) पैकिंग प्रसारों के लिए प्रतिपूर्ति निम्नानुसार होगी :

(i) 340 रु० से कम मूल वजन लेने वाले कर्म- प्रति कि० ग्राम एक पैसे चार्जों के लिए

(ii) 340 रु० और अधिक मूल वजन लेने वाले प्रति कि० ग्राम 2 पैसे कर्मचारियों के लिए

(छ) पैकिंग और दुलाई की प्रतिपूर्ति के अलावा कर्मचारियों को निम्नलिखित मान दर स्थानान्तरण अनुदान दिया जाएगा :

मूल वजन	स्थानान्तरण अनुदान
150 रु० तक	100 रु०
151—600 रु० के बीच	200 रु०
600 रु० से अधिक	300 रु०

टिप्पणः—इस अनुसूची में, किसी कर्मचारी के संबंध में, “कुटुम्ब” के अन्तर्गत पति या पत्नी, धर्मज आश्रित बच्चे और कर्मचारी के साथ रहने वाले और पूर्णतः आश्रित माता-पिता हैं।

तृतीय अनुसूची

(पैरा 17 देखिये)

छुटी यात्रा सहायकी

(क) किसी कर्मचारी और उसके कुटुम्ब के सदस्यों को प्रत्येक दो कलेण्डर वर्षों के अन्तर में एक बार यह रियायत उपलब्ध होगी परन्तु यह तब जब कि कम-से-कम 15 दिन की उपाजित छुट्टी पर जाता हो। प्रथम अन्तःक कलेण्डर वर्ष 1974-75 का होगा।

(ख) कर्मचारी दोनों तरफ के पहले 200 कि०मी० के लिए यात्रा की लागत स्वयं वहन करेगा और दोनों तरफ के अगले 1000 कि०मी० तक यात्रा की लागत नियम या उसकी किसी समनुषंगी द्वारा वहन की जाएगी। अधीनस्थ कर्मचारिकृत्त की बाबत दोनों तरफ के 1000 कि०मी० तक की यात्रा की पूरी लागत की प्रतिपूर्ति कर्मचारियों को की जाएगी।

(ग) प्रतिपूर्ति, उस श्रेणी के रेल भाड़ा या स्टीमर भाड़े के आधार पर, जिसके द्वारा कर्मचारी दोरे पर कर्तव्यारूढ यात्रा का हकदार है, या उस श्रेणी द्वारा जिसके द्वारा वह या उसका कुटुम्ब वस्तुतः यात्रा करता है, जो भी कम हो, की जाएगी। मनुक द्वारा यात्रा की वंश में दोरे पर यात्राओं को लागू दर लागू होगी। यदि कर्मचारी अपनी गवारी में यात्रा करता है या कोई सवारी भाड़े पर लेता है तो, शेष केवल कर्मचारी तक सीमित होगा।

(घ) रियायत या तो कर्मचारी के गृह की यात्रा के लिए या उसके चुनाव के किसी अन्य स्थान के लिए उपलब्ध होगी।

(ङ) कर्मचारी 1000 कि०मी० से अधिक यात्रा के लिए अपने हकदारी की श्रेणी में धिन्न श्रेणी द्वारा यात्रा कर सकेगा किन्तु उसकी

जो प्रतिपूर्ति की जाएगी वह उसके द्वारा दिए गए वास्तविक भाड़े तक सीमित होगी जो उप-पैरा (ख) और (ग) के अधीन देय राशि तक सीमित होगी।

(च) रियायत को अपनीज नहीं किया जाएगा और यह उस यात्रा में उपलब्ध नहीं होगी जवनि कर्मचारी स्वयं 15 दिन में अधिक छुट्टी पर नहीं जाता है।

(छ) रियायत कर्मचारी के कुटुम्ब के उन सदस्यों को, जो कर्मचारी के साथ या पूर्व या पीछे जाते हैं, छह मास से अधिक अवधि के लिए उस परिणाम तक जिस तक कर्मचारी को है, ग्राह्य होगी, परन्तु यह तब जबकि छुट्टी की अवधि के दौरान कर्मचारी और उसका कुटुम्ब उसी आस्थान पर हो।

टिप्पणः इस अनुसूची में, कर्मचारी के संबंध में, “कुटुम्ब” के अन्तर्गत कर्मचारी के साथ रहने वाले और उस पर पूर्णतः आश्रित पति या पत्नी, धर्मज आश्रित संतान और माता-पिता आते हैं।

[फा० सं० 65(19) आई०एन० एम० 111/21/73]

आर० डी० थापर, अवर सचिव

केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड

नई दिल्ली, 13 मार्च, 1974

प्रादेश

फा० आ० 1608— केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, धन कर नियम, 1957 के नियम 3 के उपनियम (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निदेश देता है कि इसमें संवलन सारणी के स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट प्रत्येक मूल्यांकन अधिकारी सारणी के स्तम्भ (3) में तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट आयकर-आयुक्तों की प्रादेशिक अधिकारिता के भीतर के क्षेत्रों में कृषि भूमि की बाबत मूल्यांकन अधिकारी के कर्तव्यों का पालन करेगा :

सारणी

क्र० सं०	मूल्यांकन अधिकारी	आयकर-आयुक्त
1	2	3
सर्व श्री		
1.	आर० बेकटारायन अय्यर, आयकर अधिकारी मैसूर [और II] कम्पनी मकिल, बंगलौर।	
2.	बी० एम० सेशाद्री, आयकर अधिकारी, मेर-कारा।	--यथोक्त--
3.	जी० रामगोबड्डा, आयकर अधिकारी (मंग-रण) बंगलौर।	--यथोक्त--
4.	ए० बृगन्ना, आयकर अधिकारी, गुलबर्गा	--यथोक्त--
5.	सी० गोविन्दा, आयकर अधिकारी, मंगलौर	--यथोक्त--
6.	वी० एन० गुन्डप्पा, आयकर अधिकारी, निर्धारण-3, मकिल-1, मंगलौर।	--यथोक्त--

1	2	3
7. एम० वेंकटरामन, आयकर अधिकारी, सर्किल-1	—यथोक्त—	बंगलौर।
8. आर० ए० ए० गौतम, आयकर अधिकारी	कानपुर-I और II	
9. पी० सक्सेना, आयकर अधिकारी	—यथोक्त—	
10. ए० ए० प्रसाद, आयकर अधिकारी	—यथोक्त—	
11. सुरेश कपूर, आयकर अधिकारी	—यथोक्त—	
12. के० एम० यादव, आयकर अधिकारी	—यथोक्त—	

[सं० 14/74/फा० सं० 328/63/73—डक्यू. टो० (कृषि भूमि)]

CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES

ORDER

New Delhi, the 13th March, 1974

S.O.1608:—In exercise of the powers conferred by sub-rule (2) of Rule 3A of the Wealth-tax Rules, 1957, the Central Board of Direct Taxes hereby directs that every Valuation Officer specified in Column (2) of the Table appended hereto shall perform the functions of a Valuation Officer in respect of agricultural lands in the areas within the territorial jurisdiction of the Commissioners of Income-tax specified in the corresponding entry in column (3) of the Table :

TABLE

S. Valuation Officer No.	Commissioner of Income-tax
1	2
1	2
S/Shri	
1. R. Venkatarama Iyer, Income-tax Officer, Company Circle, Bangalore	Mysore I & II
2. B. S. Seshadri, Income-tax Officer, Mercara	Do.
3. G. Ramegowda, Income-tax Officer, (Collection), Bangalore	Do.
4. A. Vecranna, Income-tax Officer, Gulbarga	Do.
5. C. Govindan, Income-tax Officer, Mangalore.	Do.
6. B. N. Gundappa, Income-tax Officer, Assessment-3, Circle-I, Bangalore.	Do.
7. S. Venkataraman, Income-tax Officer, Circle-I, Bangalore.	Do.
8. R. A. S. Gautam, Income-tax Officer.	Kanpur-I & II
9. P. Saxena, Income-tax Officer	Do.
10. A. N. Prasad, Income-tax Officer	Do.
11. Suresh Kapoor, Income-tax Officer.	Do.
12. K. S. Yadava, Income-tax Officer.	Do.

[No. 14/74/F. No. 328/63/73-W.T. (Agricultural Lands)]

फा० सं० 1609.—केन्द्रीय प्रत्यक्ष-कर बोर्ड, धन-कर नियम, 1957 के नियम 3A के उपनियम (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निर्देश देता है कि इसमें उपाख्य सारणी के स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट प्रत्येक मूल्यांकन अधिकारी—

- कंपनियों के, जिनमें उनके रजिस्ट्रीकृत कार्यालय भी सम्मिलित है, स्टॉक शेअर्स, डिबेंचरों और प्रतिभूतियों;
- भागीदारी फर्मों के जिनमें उनके मुख्य कार्यालय भी सम्मिलित है, शेअर्स;
- प्रतिभूतियों, सिवाय उनके जो खंड (i) में उल्लिखित और स्थित हों और;
- बालू कारबार की कारखाना आस्तियों, की बाबत सारणी के स्तम्भ (3) में की तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट आयकर आयुक्तों की प्रादेशिक अधिकारिता के भीतर के क्षेत्रों में मूल्यांकन अधिकारी के कर्तव्यों का पालन करेगा।

स्पष्टीकरण : आदेश में “कारखाना आस्तियों” में शुद्धिल भी सम्मिलित है किन्तु इसके अन्तर्गत स्थावर संपत्ति, कृषि-भूमि, बागान, वन, खान तथा खदान, मशीनरी तथा संयंत्र, आभूषण, कलाकृतियाँ और आजीवन हित, प्रतिवर्तन तथा प्रत्याशा हित नहीं हैं।

सारणी

क्रम सं०	मूल्यांकन अधिकारी	आय-कर आयुक्त
1	2	3
सर्वश्री		
1. के० सुशुशानासुब्रमणियन, II आय-कर अधिकारी, कंपनी सर्किल, बंगलौर।	मैसूर-I और II	
2. श्री० गोपाला अय्यर, III आय-कर अधिकारी, कंपनी सर्किल, बंगलौर।	—यथोक्त—	
3. आर० टोटाटरी, आय-कर अधिकारी, निर्धारण-7, सर्किल-1, बंगलौर।	—यथोक्त—	
4. आर० वेंकटरामय्या अय्यर, आय-कर अधिकारी, कंपनी सर्किल, बंगलौर।	—यथोक्त—	
5. के० श्री० मुकर्जी, आय-कर अधिकारी	कानपुर-I और II	
6. श्री० एल० सच्छन, आय-कर अधिकारी	—यथोक्त—	
7. एम० सी० शर्मा, आय-कर अधिकारी	—यथोक्त—	

[सं० 16/74/फा सं० 328/63/73-धन-कर(शेअर्स)]

S.O. 1609.—In exercise of the powers conferred by sub-rule (2) of rule 3A of the Wealth tax Rules, 1957, the Central Board of Direct Taxes hereby directs that every Valuation Officer specified in column (2) of the Table appended hereto shall perform the functions of a valuation officer in respect of :—

- Stock shares, debentures and Securities of companies with their registered offices;
- Shares in partnership firms with their head offices;

- (iii) Securities, other than those mentioned in clause (i) and situated and
- (iv) Business assets of business carried on; in the areas within the territorial jurisdiction of the Commissioners of Income-tax specified in the corresponding entry to column (3) of the Table.

Explanation : In the order "business assets" includes goodwill but does not include immovable property, agricultural lands, plantations, forests, mines and quarries, machinery & plant, jewellery, works of art and life interest, reversions and interest in expectancy.

TABLE

S. No.	Valuation Officer	Commissioners of Income-tax
1	2	3
S/Shri		
1.	K. Muthubalasubramanian, II Income-tax Officer, Company Circle, Bangalore	Mysore-I & II
2.	B. Gopala Iyer, III Income-tax Officer, Company Circle, Bangalore.	-do-
3.	R. Thothathri, Income-tax Officer, Asst-7, Circle-I, Bangalore.	-do-
4.	R. Venkatarama Iyer, I Income-tax Officer, Company Circle, Bangalore.	-do-
5.	K.B. Mukerji, Income-tax Officer	Kanpur-I & II
6.	B.L. Sachan, Income-tax Officer	-do-
7.	M.C. Sharma, Income-tax Officer	-do-

[No. 16/74/F. No. 328/68/73-W.T. (Shares)]

आदेश

नई दिल्ली, 29 मार्च, 1974

का. आ. 1610 :—केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, धन-कर नियम, 1957 के नियम 3क के उपनियम (2) द्वारा प्रवृत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मूल्यांकन निवेश देता है कि इससे उपाबद्ध सारणी के स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट प्रत्येक मूल्यांकन अधिकारी, सारणी के स्तम्भ (3) में की सम्बंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट आय-कर आयुक्त की अधिकारिता के भीतर के क्षेत्रों में, कृषि भूमि (धन-कर नियम, 1957 के नियम 3क के उपनियम (4) में निर्दिष्ट बागानों से भिन्न) की बाबत, मूल्यांकन अधिकारी के कृत्यों का पालन करेगा।

सारणी

क्रम सं०	मूल्यांकन अधिकारी	आय-कर आयुक्त
1	2	3
सर्वश्री		
1.	आर० एल० बहल आय-कर अधिकारी, कलकत्ता	पश्चिमी बंगाल-I से VI

1	2	3
2.	एम० पी० सिंह आय-कर अधिकारी	—यथोक्त—
3.	राम प्रसाद, आय-कर अधिकारी	राजस्थान

[सं० 23/74 का० सं० 328/63/73-ध० क० (कृषि भूमि)]

ORDER

New Delhi, the 29th March, 1974

S.O.1610.—In exercise of the powers conferred by sub-rule 2) of Rule 3A of the Wealth-tax Rules, 1957, the Central Board of Direct Taxes hereby directs that every Valuation Officer specified in Column (2) of the Table appended hereto shall perform the functions of a Valuation Officer in respect of agricultural lands (other than plantations referred to in sub-rule (4) of rule 8 A of the Wealth-tax Rules, 1957) in the areas within the territorial jurisdiction of the Commissioners of Income-tax specified in the corresponding entry in Column (3) of the Table.

TABLE

S. No.	Valuation Officer	Commissioner of Income-tax
1	2	3
S/Shri		
1.	R.L. Bahl, Income-tax Officer, Calcutta.	West Bengal-I to VI
2.	S.P. Singh, Income-tax Officer.	-do-
3.	Ram Prasad, Income-tax Officer.	Rajasthan

[No. 23/74/F. No. 328/62/72-W.T. (Agricultural lands)]

आदेश

का. आ. 1611.—केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, धन-कर नियम, 1957 के नियम 3क के उपनियम (2) द्वारा प्रवृत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निवेश देता है कि इससे उपाबद्ध सारणी के स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट प्रत्येक मूल्यांकन अधिकारी, सारणी के स्तम्भ (3) में की सम्बंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट आय-कर आयुक्त की अधिकारिता के भीतर के क्षेत्रों में,—

- कम्पनियों के, उनके रजिस्ट्रीकृत कार्यालयों सहित, स्टॉक शेयरों निबन्धनों और प्रतिभूतियों,
- भागीदारी फर्मों में, उनके मुख्य कार्यालयों सहित, शेयरों;
- खण्ड (i) में वर्णित और अवस्थित प्रतिभूतियों से भिन्न प्रतिभूतियों, और
- खलाये गये कारबार की कारबार भास्त्रियों की बाबत मूल्यांकन अधिकारी के कृत्यों का पालन करेगा।

स्पष्टीकरण: इस आदेश में "कारबार भास्त्रियों" में सूनाम भी सम्मिलित है, किन्तु हममें स्थावर सम्पत्ति, कृषि भूमि, बागान, वन, खानें और खदानें मशीनरी और संयंत्र, आभूषण, कलाकृति और आजीवन हित, प्रतिवर्तन और प्रत्याशा हित नहीं है।

सारणी		
सं०	मूल्यांकन अधिकारी	आय-कर आयुक्त
1	2	3
नवश्री		
1.	एस० के० दत्ता, आय-कर आयुक्त, कलकत्ता पश्चिमी बंगाल-I से VI	
2.	आर० के० सेन, आय-कर आयुक्त, कलकत्ता	—यथोक्त—
3.	एस० सी० नागपाल, आय-कर आयुक्त	दिल्ली-I से III
4.	एम के० जैन, आय-कर आयुक्त	—यथोक्त—
5.	एस० एल० भद्रवाल, आय-कर आयुक्त	—यथोक्त—
6.	बी० एम० बाही, आय-कर आयुक्त	—यथोक्त—
7.	के०के० सूद, आय-कर आयुक्त	—यथोक्त—
8.	जगदीश प्रसाद, आय-कर आयुक्त	—यथोक्त—
9.	आर० डी० गुप्ता, आय-कर आयुक्त	—यथोक्त—
10.	एस० एन० सोनी, आय-कर आयुक्त, जयपुर	राजस्थान
11.	रघुबीर सिंह, आय-कर आयुक्त, जयपुर	—यथोक्त—

[सं० 21/74/फा० सं० 328/6373 ध० क० (शेयर)]

ORDER

S.O.1611.—In exercise of the powers conferred by sub-rule (2) of rule 3A of the Wealth-tax Rules, 1957, the Central Board of Direct Taxes hereby directs that every valuation officer specified in column (2) of the Table appended hereto shall perform the functions of a Valuation Officer in respect of :—

- Stock shares, debentures and securities of companies with their registered offices;
- Shares in partnership firms with their head offices;
- Securities, other than those mentioned in clause (i), and situated; and
- Business assets of business carried on, in the area within the territorial jurisdiction of the Commissioners of Income-tax specified in the corresponding entry in column (3) of the Table.

Explanation : In the order "business assets" includes goodwill but does not include immovable property, agricultural lands, plantations, forests, mines and quarries, machinery and plant, jewellery, works of art and life interest, reversions and interest in expectancy.

TABLE

S. No.	Valuation Officer	Commissioner of Income-tax
1	2	3
S/Shri		
1.	S.K. Dutta, Income-tax Officer, Calcutta.	West Bengal-I to VI
2.	R.K. Sen, Income-tax Officer, Calcutta.	-do-
3.	M.C. Nagpal, Income-tax Officer.	Delhi-I to III

1	2	3
4.	M.K. Jain, Income-tax Officer	Delhi-I to III
5.	S.L. Agarwal, Income-tax Officer	-do-
6.	V.S. Wahi, Income-tax Officer	-do-
7.	K.K. Sud, Income-tax Officer	-do-
8.	Jagdish Parshad, Income-tax Officer	-do-
9.	R.D. Gupta, Income-tax Officer	-do-
10.	S.N. Soni, Income-tax Officer, Jaipur	Rajasthan
11.	Raghubir Singh, Income-tax Officer, Jaipur	-do-

[No. 21/74/F. No. 328/63/73-W.T. (Shares)]

शुद्धि-पत्र

का० प्रा० 1612.—(क) बोर्ड का आदेश सं० 7/74/फा० सं० 328/63/73-इन्स्यु०टी० (शेयर), तारीख 2 फरवरी, 1974 से संलग्न सारणी के स्तम्भ (3) में क्रम सं० 21, 22, 23 और 24 के सामने विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर 'पटियाला' पढ़ें और क्रम सं० 25, 26, और 27 के सामने विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर 'अमृतसर' पढ़ें।

(ख) बोर्ड का आदेश सं० 9/74/फा० सं० 328/63/73-इन्स्यु०टी० (कृषि भूमि), तारीख 2 फरवरी, 1974 से संलग्न सारणी के स्तम्भ (1) में '32' के पश्चात् '53' के स्थान पर '33' रखा जाएगा और उक्त आदेश सं० 9, तारीख 2 फरवरी, 1974 के स्तम्भ (3) में क्रम सं० 18, 19, 23, 24, 32 और 33 के सामने विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर 'पटियाला' पढ़ें और क्रम सं० 20, 21, 22, 26, 28, 30 और 31 के सामने विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर 'अमृतसर' पढ़ें।

[सं० 25/74/फा० सं० 328/63/73-इन्स्यु०टी०]

वी० डी० बखारकर, अवर सचिव

CORRIGENDUM

S.O. 1612.—(a) In column (3) of the Table appended to the Board's Order No. 7/74-F. No. 328/63/73-W.T. (Shares) dated the 2nd February, 1974, read 'Patiala' for the existing entries against S. Nos. 21, 22, 23 and 24, and read 'Amritsar' for the existing entries against S. Nos. 25, 26 and 27.

(b) In column (1) of the Table appended to the Board's Order No. 9/74/F. No. 328/63/73-W.T. (Agricultural lands) dated the 2nd February, 1974, '33' be substituted for '53' after '32' and in column (3) of the said Order No. 9 dated the 2nd February, 1974, read 'Patiala' for the existing entries against S. Nos. 18, 19, 23, 24, 32 and 33 and read 'Amritsar' for the existing entries against S. Nos. 21, 22, 26, 28, 29, 30, 31.

[No. 25/74/F. No. 328/63/73-W.T.]

V. D. WAKHARKAR, Under Secy.

नई दिल्ली, 8 अप्रैल, 1974

शुद्धि-पत्र

का०आ० 1613.—केन्द्रीय प्रत्यक्ष-कर बोर्ड के आदेश सं० 7/74/का० सं० 328/63/73-ध०क० (शेयर), तारीख 2 फरवरी, 1974 में स्तम्भ (3) के नीचे क्रम सं० 3 के सामने, विद्यमान प्रविष्टि के स्थान पर "मद्रास-I और II तथा आन्ध्र प्रदेश-I और II" रखा जाएगा और क्रम सं० 4 से 8 के सामने की प्रविष्टि के स्थान पर "मद्रास-I और II" रखा जाएगा।

[सं० 26/74/का० सं० 328/63/73-ध०क० (शेयर)]

एस० बापू, अवर सचिव

New Delhi, the 8th April, 1974

CORRIGENDUM

S.O. 1613.—In the Central Board of Direct Taxes Order No. 7/74/F. No. 328/63/73-W.T. (Shares), dated 2nd February, 1974 the existing entry under column (3) against S. No. 3 shall be substituted by "Madras-I & II and Andhra Pradesh-I & II" and against S. Nos. 4 to 8 by "Madras (Shares) I & II".

[No. 26/74/F. No. 328/63/73-W.T. (Shares)]

S. BAPU, Under Secy.

वित्त मंत्रालय

(बैंकिंग विभाग)

नई दिल्ली, 13 जून, 1974

का०आ० 1614.—बैंककारी विनियम अधिनियम, 1949 (1949 का 10) की धारा 53 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार, रिजर्व बैंक आफ इण्डिया की सिफारिश पर, एतद्वारा घोषित करती है कि उक्त अधिनियम की धारा 10ख के उपबन्ध 30 मितम्बर, 1974 तक बड़ी दोआब बैंक लि०, होशियारपुर पर लागू नहीं होंगे।

[सं० 15 (6)-बी० आ० III/73]

म० बा० उमगांवकर, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Banking)

New Delhi, the 13th June, 1974

S.O. 1614.—In exercise of the powers conferred by section 53 of the Banking Regulation Act, 1949 (10 of 1949), the Central Government, on the recommendation of the Reserve Bank of India, hereby declares that the provisions of section 10B of the said Act shall not apply to the Bari Doab Bank Ltd., Hoshiarpur, till the 30th September, 1974.

[No. 15(6)-B. O. III/73]

M. B. USGAONKAR, Under Secy.

रिजर्व बैंक आफ इंडिया

नई दिल्ली, 15 जून, 1974

का० आ० 1615.—रिजर्व बैंक आफ इंडिया अधिनियम, 1934 के अनुमरण में मई, 1974 की 31 तारीख को समाप्त हुए सप्ताह के लिये लेखा दशू विभाग

देयताएं	रुपये	रुपए	प्रास्तियां	रुपए	रुपए
बैंकिंग विभाग में रखे हुए नोट	22,87,02,000		सोने का सिक्का और मुद्रि-		
			यन:-		
			(क) भारत में रखा हुआ	182,53,05,000	
संचलन में नोट	64,61,06,65,000		(ख) भारत के बाहर रखा		
			हुआ विदेशी प्रतिभूतियां	166,73,97,000	
जारी किये गये कुल नोट		64,83,93,67,000	जोड़		349,27,02,000
			रुपये का सिक्का		6,04,16,000
			भारत सरकार की रुपया		
			प्रतिभूतियां		1,28,62,49,000
			बेसी विनियम बिल और		
			दूसरे वाणिज्य-पत्र		
कुल देयताएं,		64,83,93,67,000	कुल प्रास्तियां		64,83,93,67,000

तारीख 5 जून, 1974

बी०बी० बाहो, उप गवर्नर

31 मई, 1974 को रिजर्व बैंक आफ इंडिया के बैंकिंग विभाग के कार्यकलाप का विवरण

वेयताएं	रुपए	आस्तियां	रुपए
चुकता पूंजी	5,00,00,000	नोट	22,87,02,000
भारक्षित निधि	150,00,00,000	रुपयें का सिक्का	6,83,000
राष्ट्रीय कृषि ऋण (दीर्घकालीन क्रियाएँ) निधि	239,00,00,000	छोटा सिक्का	3,57,000
राष्ट्रीय कृषि ऋण (स्थिरीकरण) निधि	85,00,00,000	खरीदे और भुनाये गये बिल	
राष्ट्रीय औद्योगिक ऋण (दीर्घकालीन क्रियाएँ) निधि	205,00,00,000	(क) देशी	267,98,62,000
जमा राशियाँ:—		(ख) विदेशी
(क) सरकारी		(ग) सरकारी खजाना बिल	130,93,52,000
(i) केन्द्रीय सरकार	50,91,12,000	विदेशों में खरा हुआ बकाया*	602,74,51,000
(ii) राज्य सरकारें	13,84,32,000	निवेश**	222,75,97,000
(ख) बैंक]		ऋण और अग्रिम:—	
(i) अनुसूचित वाणिज्य बैंक	581,83,99,000	(i) केन्द्रीय सरकार को
(ii) अनुसूचित राज्य सहकारी बैंक	15,83,59,000	(ii) राज्य सरकारों को	146,34,07,000
(iii) गैर अनुसूचित राज्य सहकारी बैंक	1,36,43,000	ऋण और अग्रिम:—	
(iv) अन्य बैंक	69,18,000	(i) अनुसूचित वाणिज्य बैंकों को †	407,38,31,000
		(ii) राज्य सहकारी बैंकों को ‡	182,36,31,000
		(iii) दूसरों को	10,45,23,000
		राष्ट्रीय कृषि ऋण (दीर्घकालीन क्रियाएँ) निधि से	
		ऋण, अग्रिम और निवेश	
		(क) ऋण और अग्रिम:—	
		(i) राज्य सरकारों को	67,94,37,000
		(ii) राज्य सहकारी बैंकों को	16,67,31,000
		(iii) केन्द्रीय भूमिबंधक बैंकों को
		(iv) कृषि पुनर्वित्त निगम को	36,70,00,000
(ग) अन्य	372,66,24,000	(ख) केन्द्रीय भूमिबंधक बैंकों के डिबेंचरों में निवेश	
		राष्ट्रीय कृषि ऋण (स्थिरीकरण) निधि से	
		ऋण और अग्रिम	11,31,64,000
देय बिल	104,99,21,000	राज्य सहकारी बैंक को ऋण और अग्रिम राष्ट्रीय	
		औद्योगिक ऋण (दीर्घकालीन क्रियाएँ) निधि से	44,16,19,000
अन्य वेयताएँ	683,82,09,000	ऋण, अग्रिम और निवेश	
		(क) विकास बैंक को ऋण और अग्रिम	173,56,86,000
		(ख) विकास बैंक द्वारा जारी किये गये बांडों/डिबेंचरों	
		में निवेश
		अन्य आस्तियां	165,65,84,000
रुपए	25,09,96,17,000	रुपए	25,09,96,17,000

*खरादी, प्राबधिक जमा और अल्पकालीन प्रतिभूतियां शामिल हैं।

**राष्ट्रीय कृषि ऋण (दीर्घकालीन क्रियाएँ) निधि और राष्ट्रीय औद्योगिक ऋण (दीर्घकालीन क्रियाएँ) निधि में से किए गये निवेश शामिल नहीं हैं।

†राष्ट्रीय कृषि ऋण (दीर्घकालीन क्रियाएँ) निधि से प्रदत्त ऋण और अग्रिम शामिल नहीं हैं, परन्तु राज्य सरकारों को दिये गये अस्थायी ओवरड्राफ्ट शामिल हैं।

‡रिजर्व बैंक आफ इंडिया अधिनियम की धारा 17(4)(ग) के अधीन अनुसूचित वाणिज्य बैंकों को मीयादी बिलों पर अग्रिम दिये गये 103,65,98,000 रुपए शामिल हैं।

(iv) राष्ट्रीय कृषि ऋण (दीर्घकालीन क्रियाएँ) निधि और राष्ट्रीय कृषि ऋण (स्थिरीकरण) निधि से प्रदत्त ऋण और अग्रिम शामिल नहीं हैं।

[सं० फा० 10/1/74—बी०ओ० I]

Reserve Bank of India
New Delhi the 15 June, 1974

S.O. 1615 AN ACCOUNT PURSUANT TO THE RESERVE BANK OF INDIA ACT, 1934, FOR THE WEEK ENDED THE 31st DAY OF MAY, 1974 ISSUE DEPARTMENT

Liabilities	Day	Rs.	Rs.	Assets	Rs.	Rs.
Notes held in the Banking Department		22,87,02,000		Gold Coin and Bullion —		
Notes in circulation		6461,06,65,000		(a) Held in India	182,53,05,000	
				(b) Held outside India		
Total Notes issued			6483,93,67,000	Foreign Securities	166,73,97,000	
				Total		349,27,02,000
				Rupee Coin		6,04,16,000
				Government of India Rupee Securities		6128,62,49,000
				Internal Bills of Exchange and Other Commercial paper		..
Total liabilities			6483,93,67,000	Total Assets		6483,93,67,000

Dated, 5th June 1974

V.V. CHARI, Dy. Governor

Statement of the Affairs of the Reserve Bank of India, Banking Department as on the 31st May, 1974

Liabilities	Rs.	Assets	Rs.
Capital Paid Up	5,00,00,000	Notes	22,87,02,000
Reserve Fund	150,00,00,000	Rupee Coin	6,83,000
		Small Coin	3,57,000
		Bills Purchased and Discounted:—	
National Agricultural Credit (Long Term Operations) Fund	239,00,00,000	(a) Internal	267,98,62,000
		(b) External	..
National Agricultural Credit (Stabilisation) Fund	85,00,00,000	(c) Government Treasury Bills	130,93,52,000
National Industrial Credit (Long Term Operations) Fund	205,00,00,000	Balances Held Abroad*	602,74,51,000
		Investments**	222,75,97,000
Deposits :—		Loans and Advances to :—	
(a) Government		(i) Central Government	..
(i) Central Government	50,91,12,000	(ii) State Governments @.	146,34,07,000
(ii) State Governments	13,84,32,000	Loans and Advances to :—	
		(i) Scheduled Commercial Banks +	407,38,31,000
(b) Banks		(ii) State Co-operative Banks ++	182,36,31,000
(i) Scheduled Commercial Banks	581,83,99,000	(iii) Others	10,45,23,000
(ii) Scheduled State Co-operative Banks	15,83,59,000	Loans, Advances and Investments from National Agricultural Credit (Long Term Operations) Fund	
(iii) Non-Scheduled State Co-operative Banks	1,36,43,000	(a) Loans and Advances to :—	
(iv) Other Banks	69,18,000	(i) State Governments	67,94,37,000
(c) Others	372,66,24,000	(ii) State Co-operative Banks	16,67,31,000
Bills Payable	104,99,21,000	(iii) Central Land Mortgage Banks	..
Other Liabilities	683,82,09,000	(iv) Agricultural Refinance Corporation	36,70,00,000
		(b) Investment in Central Land Mortgage Bank	11,31,64,000
		Loans and Advances from National Agricultural Credit (Stabilisation) Fund	
		Loans and Advances to State Co-operative Banks	44,16,19,000
		Loans, Advances and Investment from National Industrial Credit (Long Term Operations) Fund	
		(a) Loans and Advances to the Development Bank	173,56,86,000
		(b) Investment in bonds/debentures issued by the Development Bank	..
		Other Assets	163,65,84,000
	Rupees		Rupees
	2509,96,17,000		2509,96,17,000

*Includes Cash, Fixed Deposits, and Short-term Securities.

**Excluding Investments from the National Agricultural Credit (Long Term Operations) Fund and the National Industrial Credit (Long Term Operations) Fund.

@Excluding Loans and Advances from the National Agricultural Credit (Long Term Operations) Fund, but including temporary overdrafts to State Governments.

+-Includes Rs. 103,65,98,000 advances to scheduled commercial banks against usance bills under Section 17(4)(c) of the Reserve Bank of India Act.

---Excluding Loans and Advances from the National Agricultural Credit (Long Term Operations) Fund and the National Agricultural Credit (Stabilisation) Fund.

Dated the 5th day of June 1974.

V.V. CHARI, Dy. Governor.

[No. F.10(1)/74—BO.1]

C.W. MIRCHANDANI, Under Secy.

नई दिल्ली, 15 जून, 1974

का० प्रा० 1616:—रिजर्व बैंक आफ इंडिया अधिनियम, 1934 के अनुसरण में जून 1974 की 7 तारीख को समाप्त हुए सप्ताह के लिये लेखा दशू विभाग

देयताएँ	रुपये	रुपये	आस्तियाँ	रुपये	रुपये
बैंकिंग विभाग में रखे हुए नोट	10,50,99,000		सोने का सिक्का और बुलियन		
			(क) भारत में रखा हुआ	182,53,05,000	
संचलन में नोट	6561,04,46,000		(ख) भारत के बाहर रखा हुआ		
			विदेशी प्रतिभूतियाँ	166,73,97,000	
जारी किये गये कुल नोट		6571,55,45,000	जोड़		349,27,02,000
			रुपये का सिक्का		4,02,84,000
			भारत सरकार की रुपया प्रतिभूतियाँ		6218,25,59,000
			देशी विनियम जिल और दूसरे वाणिज्य-यत्न		
कुल देयताएँ		6571,55,45,000	कुल आस्तियाँ		6571,55,45,000

तारीख: 12 जून 1974

आर० के० हजारी, उप गवर्नर

7 जून 1974 को रिजर्व बैंक आफ इंडिया के बैंकिंग विभाग से कार्यकलाप का विवरण

देयताएँ	रुपये	आस्तियाँ	रुपये
चुक्ता पूंजी	5,00,00,000	नोट	10,50,99,000
प्रारंभित निधि	150,00,00,000	रुपये का सिक्का	4,71,000
राष्ट्रीय कृषि ऋण (दीर्घकालीन क्रियाएँ) निधि	239,00,00,000	छोटा सिक्का	3,48,000
राष्ट्रीय कृषि ऋण (स्थिरीकरण) निधि	85,00,00,000	खरीदे और भुनाय गये बिल	
राष्ट्रीय औद्योगिक ऋण (दीर्घकालीन क्रियाएँ) निधि	205,00,00,000	(क) देशी	270,09,59,000
जमा राशियाँ:—		(ख) विदेशी	
(क) सरकारी		(ग) सरकारी खजाना बिल	145,96,78,000
(1) केन्द्रीय सरकार	75,45,41,000	विदेशों में रखा हुआ बकाया*	589,04,93,000
(2) राज्य सरकारें	9,06,32,000	निवेश**	238,51,13,000
(ख) बैंक		ऋण और अग्रिम:—	
(1) अनुसूचित वाणिज्य बैंक	573,66,18,000	(1) केन्द्रीय सरकार को	
(2) अनुसूचित राज्य सहकारी बैंक	14,41,34,000	(2) राज्य सरकारों को (ए)	147,07,96,000
(3) गैर अनुसूचित सहकारी बैंक	1,25,43,000	ऋण और अग्रिम:—	
(4) अन्य बैंक	67,08,000	(1) अनुसूचित वाणिज्य बैंकों को	413,99,56,000
		(2) राज्य सहकारी बैंकों को	180,53,56,000
		(3) दूसरों को	12,67,01,000
		राष्ट्रीय कृषि ऋण (दीर्घकालीन क्रियाएँ) निधि से ऋण और अग्रिम निवेश	
		(क) ऋण और अग्रिम:—	
		(1) राज्य सरकारों को	67,94,37,000
		(2) राज्य सहकारी बैंकों को	12,87,93,000
		(3) केन्द्रीय भूमिबंधक बैंकों को	
		(4) कृषि पुनर्वित्त निगम को	36,70,00,000

देयताएँ	रुपये	आस्तियां	रुपये
(ग) अन्य	361,04,41,000	(घ) केन्द्रीय भूमिबंधक बैंकों के डिबेंचरों में निवेश राष्ट्रीय कृषि ऋण (स्थिरीकरण) निधि से ऋण और अग्रिम	11,31,64,000
देय बिल	121,99,49,000	राज्य सहकारी बैंकों को ऋण और अग्रिम राष्ट्रीय औद्योगिक ऋण (दीर्घकालीन क्रियाएँ) निधि से	43,89,26,000
अन्य देयताएँ	679,33,39,000	ऋण, अग्रिम और निवेश	
		(क) विकास बैंक को ऋण और अग्रिम	173,56,85,000
		(ख) विकास बैंक द्वारा जारी किये गये बांडों/ डिबेंचरों में निवेश अन्य आस्तिया
		अन्य आस्तियां	166,09,30,000
रुपये	2520,89,05,000	रुपये	2520,89,05,000

*नकदी, आवधिक जमा और अल्पकालीन प्रतिभूतियां शामिल हैं।

**राष्ट्रीय कृषि ऋण (दीर्घकालीन क्रियाएँ) निधि और राष्ट्रीय औद्योगिक ऋण (दीर्घकालीन क्रियाएँ) निधि में से किये गये निवेश शामिल नहीं हैं।

@राष्ट्रीय कृषि ऋण (दीर्घकालीन क्रियाएँ) निधि से प्रदत्त ऋण और अग्रिम शामिल नहीं हैं, परन्तु राज्य सरकारों को दिये गये अस्थायी ओवरड्राफ्ट शामिल हैं।

†रिजर्व बैंक आफ इंडिया अधिनियम की धारा 17(4)(ग) के अधीन अनुसूचित वाणिज्य बैंकों को सीमावी बिलों पर अग्रिम दिये गये 123,79,73,000/- रुपए शामिल हैं।

‡राष्ट्रीय कृषि ऋण (दीर्घकालीन क्रियाएँ) निधि और राष्ट्रीय कृषि ऋण (स्थिरीकरण) निधि से प्रदत्त ऋण और अग्रिम शामिल नहीं हैं।

तारीख : 12 जून, 1974

[सं० एफ 10/1/74 बीपी I]

भार० के हज़ारी, उप गवर्नर।

New Delhi, the 15th June, 1974

S.O. 1616.—An Account pursuant to the RESERVE BANK OF INDIA ACT, 1934, for the week ended the 7th day of June 1974.

ISSUE DEPARTMENT

Liabilities	Rs.	Rs.	Assets	Rs.	Rs.
Notes held in the Banking Department	10,50,99,000		Gold Coin and Bullion :—		
Notes in circulation	6561,04,46,000		(a) Held in India	182,53,05,000	
Total Notes issued		6571,55,45,000	(b) Held outside India	
			Foreign Securities	166,73,97,000	
			Total		349,27,02,000
			Rupee Coin		4,02,84,000
			Government of India Rupee Securities		6218,25,59,000
			Internal Bills of Exchange and other Commercial paper		
Total liabilities		6571,55,45,000	Total Assets		6571,55,45,000

R.K. HAZARI, Dy. Governor.

Dated the 12th day of June, 1974.

Statement of the Affairs of the Reserve Bank of India Banking Department as on the 7th June, 1974

Liabilities	Rs.	Assets	Rs.
Capital Paid Up	5,00,00,000	Notes	10,50,99,000
Reserve Fund	150,00,00,000	Rupee Coin	4,71,000
National Agricultural Credit (Long Term Operations) Fund	239,00,00,000	Small Coin	3,48,000
National Agricultural Credit (Stabilisation) Fund	85,00,00,000	Bills Purchased and Discounted —	
National Industrial Credit (Long Term Operations) Fund	205,00,00,000	(a) Internal	270,09,59,000
Deposits :—		(b) External
(a) Government		(c) Government Treasury Bills	145,96,78,000
(i) Central Government	75,45,41,000	Balances Held Abroad*	589,04,93,000
(ii) State Governments	9,05,32,000	Investments**	238,51,13,000
(b) Banks		Loans and Advances to —	
(i) Scheduled Commercial Banks	573,66,18,000	(i) Central Government
(ii) Scheduled State Co-operative Banks	14,410,34,000	(ii) State Governments(a)@	147,07,96,000
(iii) Non-Scheduled State Co-operative Banks	1,25,43,000	Loans and Advances to —	
(iv) Other Banks	67,08,000	(i) Scheduled Commercial Banks+	413,99,56,000
(c) Others	361,04,41,000	(ii) State Co-operative Banks + +	180,53,56,000
Bills Payable	121,99,49,000	(iii) Others	12,67,01,000
Other Liabilities	679,33,39,000	Loans, Advances and Investments from National Agricultural Credit (Long Term Operations) Fund	
		(a) Loans and Advances to —	
		(i) State Governments	67,94,37,000
		(ii) State Co-operative Banks	12,87,92,000
		(iii) Central Land Mortgage Banks
		(iv) Agricultural Refinance Corporation	36,70,00,000
		(b) Investment in Central Land Mortgage Bank Debentures	11,31,64,000
		Loans and Advances from National Agricultural Credit (Stabilisation) Fund	
		Loans and Advances to State Co-operative Banks	43,89,26,000
		Loans, Advances and Investments from National Industrial Credit (Long Term Operations) Fund	
		(a) Loans and Advances to the Development Bank	173,56,85,000
		(b) Investment in bonds/debentures issued by the Development Bank
		Other Assets	166,09,30,000
	Rupees 2520,89,05,000		Rupees 2520,89,05,000

*Includes Cash, Fixed Deposits and Short-term Securities.

**Excluding Investments from the National Agricultural Credit (Long Term Operations) Fund and the National Industrial Credit (Long Term Operations) Fund.

@Excluding Loans and Advances from the National Agricultural Credit (Long Term Operations) Fund, but including temporary overdrafts to State Governments.

+Includes Rs. 123,79,73,000 advanced to scheduled commercial banks against usance bills under Section 17(4)(c) of the Reserve Bank of India Act.

+ +Excluding Loans and Advances from the National Agricultural Credit (Long Term Operations) Fund and the National Agricultural Credit (Stabilisation) Fund.

R.K. HAZARI, Dy. Governor.

No. F. 10/1/74 B.O.I.

C.W. Mirchandani, Under Secy.

Dated the 12th day of June 1974.

वारिष्ठ्य संचालन

संयुक्त-मुख्य नियंत्रक आयात निर्यात का कार्यालय

आदेश

बम्बई, 15 मार्च, 1973

कां० प्रा० 1617.—महेश्वरी जनरल स्पेयर्स इण्डस्ट्रीज प्रा० लि० बम्बई को (1) एम०एस०पी कटिंग ब्लैक बार्स (सीमा किम्म के) (2) अप्रैल-मार्च, 1973 की रेट बुक के परिशिष्ट 14 के अनुसार निषेध तथा प्रतिबंधित से भिन्न अनुमेय आकारों वाले बाल बेयरिंग, (3) अप्रैल-मार्च, 1973 की रेट बुक के परिशिष्ट 16/6(ए) तथा 16(6)(बी) में विशिष्टीकृत से भिन्न लेपर्ड रोलर बेयरिंग (4) संलग्न सूची के अनुसार का आयात करने के लिए 6640/- का एक आयात लाइसेंस संख्या: 2663813, दिनांक 24-1-73 स्वीकृत किया गया था। उन्होंने उपर्युक्त लाइसेंस की अनुलिपि सीमाशुल्क तथा मुद्रा विनियम नियंत्रण प्रति दोनों के लिए इस आधार पर आवेदन किया है कि मूल प्रति किसी भी सीमा शुल्क प्राधिकारी के पास पंजीकृत कराए बिना और उसका बिल्कुल उपयोग किए बिना ही खो गई है। अब अनुलिपि प्रतियों की जबरन लाइसेंस के पूरे मूल्य अर्थात् 6640 रुपये के लिए है। अपने दावे के समर्थन में आवेदक ने प्रेजीडेन्सी मैजिस्ट्रेट, एस्सेलेन्ड कोर्ट, बम्बई के सम्मुख विधिवत शपथ लेते हुए एक शपथ पत्र दाखिल किया है और इसके साथ बिले-मार्च पुलिस स्टेशन द्वारा एक प्रमाण पत्र भी भेजा है जिसमें इसकी पुष्टि की गई है कि वह छोटा बैग जिसमें अन्य वस्तुओं के साथ साथ लाइसेंस भी थे, आवेदक द्वारा हवाई अड्डे पर खो गया था।

2. मैं संतुष्ट हूँ कि लाइसेंस संख्या पी/ए/2663813, दिनांक 24-1-73 की मूल सीमाशुल्क तथा मुद्रा विनियम नियंत्रण प्रयोजन प्रति खो गई है और निदेश देता हूँ कि आवेदक को अनुलिपि प्रति जारी की जाए।

3. लाइसेंस की मूल सीमाशुल्क मुद्रा विनियम नियंत्रण प्रयोजन प्रति रद्द की जाती है।

[मिसिल संख्या : 236/13033/बी सी, 71/एस/ई पी एस सी-2-सी]

सी० डिपूजा, उप-मुख्य नियंत्रक,
संयुक्त मुख्य नियंत्रक,

MINISTRY OF COMMERCE

OFFICE OF THE JOINT CHIEF CONTROLLER OF
IMPORTS & EXPORTS

ORDER

Bombay, the 15th March, 1973

S.O. 1617.—M/s. General Spares Industries, P. Ltd., Bombay have been granted Licence No. 2663813 of 24-1-73 for Rs. 6640/- for import of "(1) M.S. Free Cutting Black Bars (loaded quality). (2) Permissible sizes of Ball Bearings other than those banned and restricted as per App. 14 of AM. 73 R.B. (3) Tapered Roller Bearings other than those specified in app. 16/6(A) and 16(6)(B) of AM. 73 R.B. (4) As per list attached." They have applied for duplicate copy of both Customs and Exchange Control copy of the 36 GI/74—4

said licence on the ground that the original has been lost without having been registered with any Customs authority and without having been utilised at all. The duplicate copies now required is for the full value of the licence i.e. Rs. 6640/-. In support of their claim. The applicants have filed an affidavit duly sworn in before the Presidency Magistrate, Esplanade Court, Bombay alongwith a Photostat of a certificate from the Vile-Parle Police Station confirming that a brief case containing licences alongwith other documents was lost at the Air-Port by the applicant.

2. I am satisfied that the original copy of Customs and Exchange Control purposes of the licence No. P/U/2663813 of Rs. 6640/- have been lost and direct that the duplicate copy of the licence be issued to the applicant.

3. The original of Customs and Exchange control copy of the licence is cancelled.

[F. No. 236/13033/OD. 71/L/EPSC. II. C.]

D. D'SOUZA, Dy. Chief Controller.
for Joint Chief Controller

केन्द्रीय लाइसेंस क्षेत्र

आदेश

नई दिल्ली, 4 दिसम्बर, 1973

कां० प्रा० 1618.—महेश्वरी प्रोडक्ट्स प्रा० इंडिया, अणोका होटल, नई दिल्ली को 1. अनिमित हाथी दाँत/नन्हा गजदन्त तथा पूरा गजदन्त 2. बक्सों के लिए पीतल के कच्चे पीतल के पेंच, कुडिया तथा स्टेपल, कर्ण टाप्स के लिए क्लिप, 305 रु० तक कर्णवलयों के लिए हुक तथा पेंचों के आयात के लिए 4880 रु० का एक आयात लाइसेंस सं० पी/एल 2686284/सी दिनांक 30-3-72 स्वीकृत किया गया था। उन्होंने आयात व्यापार नियंत्रण नियम तथा क्रियाविधि हैड बुक 1973-74 की कड़िका 320 के अंतर्गत अपेक्षित एक शपथ पत्र दाखिल किया है जिसमें उन्होंने यह बताया है कि लाइसेंस सं० पी/एल/2686284/सी दिनांक 30-3-72 मूल्य 4880 रु० की सीमाशुल्क कार्यसंबंधी प्रति विस्तृत उपयोग किए बिना ही खो गई/अस्थानस्थ हो गई है।

मैं संतुष्ट हूँ कि उक्त लाइसेंस की सीमाशुल्क कार्यसंबंधी प्रति खो गई/अस्थानस्थ हो गई है।

अद्यतन यथासंशोधित आयात व्यापार नियंत्रण आदेश, 1955 दिनांक 7-12-55 की धारा 9(सी) के अंतर्गत मेरे लिए प्रवक्त अधिकारों का प्रयोग कर लाइसेंस सं० पी०/एल/2686284 दिनांक 30-3-72 मूल्य 4880 रु० (सीमाशुल्क कार्यसंबंधी प्रति) को एतद्वारा रद्द किया जाता है।

अब आवेदक को आयात व्यापार नियंत्रण नियम तथा क्रियाविधि हैडबुक, 1973-74 की कड़िका 320 की व्यवस्थाओं के अनुसार उक्त लाइसेंस की अनुलिपि सीमाशुल्क कार्यसंबंधी प्रति जारी की जा रही है।

[मि० सं० हैडी/54/जे०पी० 71/एस सी 3/सी एल ए/3308]

ए०एल० भस्मा, उपमुख्य नियंत्रक, और
संयुक्त मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात

(Central Licensing Area)

ORDER

New Delhi, the 4th December, 1973

S.O. 1618.—M/s. Products of India, Ashoka Hotel, New Delhi were granted licence No. P/L/2686284/C dated 30-3-72 for Rs. 4880/- for the import of 1. Ivory un-manufactured/baby tusks & full tusks. 2. Brass Hinges, Brass

screws, hasps and staples for boxes, clips for ear tops, hooks and screws for ear-rings upto Rs. 305/-. They have filed an affidavit as required under para 320 of Import Trade Control Hand Book of Rules & Procedure, 1973-74 wherein they have stated that Custom purpose copy of licence No. P/L/2686284/ dated 30-3-72 for Rs. 4880/- has been lost/misplaced without having been utilised at all.

2. I am satisfied that the Customs Purposes copy of the said licence has been lost/misplaced.

3. In exercise the powers conferred on me under sub-section 9(c) in the Import Trade Control Order 1955 dated 7-12-55 as amended upto date, the said licence No. P/L/2686284 dated 30-3-72 for Rs. 4880/- (Custom Purpose copy) is hereby cancelled.

4. The applicant is now being issued duplicate Custom Purposes Copy of the said licence in accordance with the provisions of para. 320 of Import Trade Control Hand Book of Rules & Procedure, 1973-74.

[File No. Handi/54/JS-71/SC-III/CLA/3308]

A. L. BHALLA, Dy. Chief Controller &
Jt. Chief Controller.

आदेश

कलकत्ता, 20 अप्रैल, 1974

S.O. 1619

कांसा 1619—सर्वश्री पीटर्स एण्ड स्मिथ (इंडिया) प्रा० लि०, कलकत्ता को अप्रैल-मार्च 1974 की अवधि के लिए निम्नलिखित लाइसेंस जारी किए गए थे :-

लाइसेंस सं० तथा दिनांक	विवरण	मूल्य
1	2	3
1. लाइसेंस सं० 0241091/सी/एक्स एक्स/49/सी/37-38 दिनांक 30-11-73	क्रम सं० 82/4 के अंतर्गत स्वी- कृत माल	2007 रु० (दो हजार सात सौ मात्र)
2. लाइसेंस सं० 0241092/सी/एक्स एक्स/49/सी/37-38 दिनांक 30-11-73	क्रम सं० 83/4 के अंतर्गत शराब	1250 रु० (एक हजार दो सौ पचास रु० मात्र)
3. लाइसेंस सं० पी/ई/0241093/ सी/एक्स एक्स/49/सी/37-38 दिनांक 30-11-73	क्रम सं० 84/4 के अंतर्गत ब्राण्डी/शराब	1250 रु० (एक हजार दो सौ पचास रु० मात्र)

फर्म ने उपर्युक्त पूरे मूल्य के लिए उक्त लाइसेंसों की अनुलिपि मुद्रा विनिमय नियंत्रण प्रतियों के लिए यह पुष्टि करने के बाद आवेदन किया है कि जब उन्होंने माह्र पत्र खोलने के लिए उक्त लाइसेंसों की मुद्रा विनिमय नियंत्रण प्रतियां सेन्ट्रल बैंक को प्रस्तुत की थीं तो वे बिल्कुल उपयोग किए बिना ही आग में नष्ट हो गई थी। कुल मूल्य जिसके लिए मूल मुद्रा विनिमय नियंत्रण प्रतियां जारी की गई थी वह 2007 रु०, 1250 रु० एवं 1250 रु० था और कुल मूल्य जिसके

लिए मूल मुद्रा विनिमय नियंत्रण प्रतियों का उपयोग कर लिया गया था, वह शून्य था अब अनुलिपि मुद्रा विनिमय नियंत्रण प्रतियों की आवश्यकता उपर्युक्त उल्लिखित पूरे मूल्य के लिए है।

2. इस तर्क के समर्थन में आवेदक ने प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट द्वारा विधिवत साक्षात्कृत स्टाम्प कागज पर लाइसेंसों की प्रत्येक मुद्रा विनिमय नियंत्रण प्रति के लिए एक शपथ पत्र दाखिल किये हैं।

3. मैं संतुष्ट हूँ कि आवेदक को आयात लाइसेंस सं० पी/ई/0241091/सी, पी/ई/0241092/सी/एक्स पी/ई/0241093/सी जिनका क्रमशः मूल्य 2007 रु० 1250 रु० एवं 1250 रु० है की अनुलिपि मुद्रा विनिमय नियंत्रण प्रतियां जारी की जानी चाहिए। उक्त लाइसेंस की मुद्रा विनिमय नियंत्रण प्रतियां उपर्युक्त उल्लिखित पूरे मूल्य के लिए रह की जाती हैं।

संख्या ईआर/37324/8/एएम74/बी

एस० के० मन्वल उप-मुख्य

नियंत्रक,

कूतें मुख्य नियंत्रक

ORDER

Calcutta, dated 20 April, 1974

S.O. 1619—M/s. Peters & Smith (India) Pvt. Ltd., Calcutta were issued Import Licences for the period April-March 1974 as under :-

Licence No. & Date	Description	Value
1. L. No. 0241091/C/XX/49/C/37-38 dt. 30-11-73.	Goods permissible under S. No. 82/IV.	Rs. 2007/- (Rupees two thousand & seven only)
2. L. No. 0241092/C/XX/49/C/37-38 dt. 30-11-73.	Wines under S. No. 83/IV.	Rs. 1250/- (Rupees one thousand two hundred & fifty only).
3. L. No. P/E/0241093/C/XX/49/C/37-38 dt. 30-11-73.	Brandy/Whisky under S.No. 84/IV.	Rs. 1250/- (Rupees one thousand two hundred & fifty only)

The firm have applied for duplicate Exchange Control copies of the above licences for the full values mentioned above, since they have confirmed that the Exchange Control copies of the said licences, while submitted for opening letters of credit to the Central Bank, were destroyed by fire without having been fully utilised. The total amount for which the original Exchange copies were issued were for Rs. 2007/-, Rs. 1250/- and Rs. 1250/- and the total amount for which the original Exchange Control copies were utilised were nil. The duplicate Exchange Control copies now required are to cover the entire amount mentioned above.

2. In support of this contention the applicant has filed an affidavit on a stamped paper duly attested by the first Class Magistrate against each of the above Exchange Control copies of the licences.

3. I am satisfied that the Exchange Control copies of Import Licence Nos. P/E/0241091/C, P/E/0241092/C and P/E/0241093/C for the full value of Rs. 2007/-, Rs. 1250/- and Rs. 1250/- respectively should be issued to the applicant. The Exchange Control copies of the above import licences are cancelled for the entire amount mentioned above.

[No.FI/37324/8/AM74/B]

S. K. MANDAL,

Dy. Chief Controller

For Jt. Chief Controller

आवेश

नई दिल्ली, 23 अप्रैल, 1974

का. आ. 1620.—सर्वश्री इन्टरनेशनल आटो सप्लाइज 903, क्वीन्स रोड, दिल्ली को मिटटी हटाने वाली मशीन में उपयोग के लिए हेड लैम्प के फालतू पुर्जों के रूप में 72 नंग सील्ड बीम लैम्प के आयात के लिए 4484 रु. का एक बदलाई लाइसेंस सं. पी/आई/3031965 दिनांक 21-7-1972 स्वीकृत किया गया था। उन्होंने उक्त लाइसेंस की अनुलिपि सीमा-शुल्क कार्यसंबंधी प्रति के लिए इस आधार पर आवेदन किया है कि मूल प्रति खो गई/अस्थानस्थ हो गई है। फर्म द्वारा आगे यह बताया गया है कि लाइसेंस की मूल सीमा-शुल्क कार्यसंबंधी सीमा-शुल्क कार्यालय में पंजीकृत नहीं कराई गई थी और इस लिए उसका उपयोग नहीं किया गया है।

उक्त घोषणा के समर्थन में आवेदक ने यह बताते हुए विधिवत साक्ष्यीकृत एक शपथ पत्र दाखिल किया है कि लाइसेंस की मूल सीमा-शुल्क कार्यसंबंधी प्रति खो गई है या अस्थानस्थ हो गई है।

मैं संतुष्ट हूँ कि उपर्युक्त लाइसेंस की मूल सीमा-शुल्क कार्यसंबंधी प्रति खो गई है और निवेश देता हूँ कि आवेदक को अनुलिपि सीमा-शुल्क कार्यसंबंधी प्रति जारी की जानी चाहिए। लाइसेंस की मूल सीमा-शुल्क कार्यसंबंधी प्रति रद्द की जाती है।

[सं. आइ ई पी टी./28/ए एम 71/क्यू एल/सी एल ए]

ओ. एन. आनन्द, उप-मुख्य नियंत्रक,

ORDER

New Delhi, the 23rd April, 1974

S.O. 1620.—M/s. International Auto Supplies, 903 Queens Road, Delhi were granted a replacement licence No. P/I/3031965 dated 21-7-72 for Rs. 4484/- for import of 72 pieces Sealed Beam Lamps as parts of Head Lamps for use on Earthmoving Machinery. They have applied for the duplicate Customs purpose copy of the said licence on the ground that the original has been lost or misplaced. It is, further stated by the firm that the original Custom Purpose Copy of the licence was not registered with Customs House and hence has not been utilised.

In support of this declaration, the applicant has filed an affidavit duly attested stating that the original Customs Purpose Copy of the licence has been lost or misplaced.

I am satisfied that the original Customs Purpose copy of the said licence has been lost and direct that duplicate Custom Purpose copy should be issued to the applicant. The original Customs Purpose copy of the licence is cancelled.

[F. No. Rept./28/AM-71/QL/CLA]

O. N. ANAND, Dy. Chief Controller.

आदेश

हैदराबाद, 11 अप्रैल, 1974

का० आ० 1621.—सर्वश्री जूवेल जेम्स सं० 5-4-14/2, निजामशाही रोड, हैदराबाद को सामान्य मुद्रा क्षेत्र में (1) टम्बलिंग मशीन, (2) पॉलिशिंग

एवं लेम्पिंग मशीन (3) कटिंग स्लेबिंग एवं स्लाइसिंग मशीन के आयात के लिए 12,000 रु० का एक आयात लाइसेंस सं० पी/एस/1736671/सी/एसएस एक्स/44/इक्यू/33-34 दिनांक 31-8-1972 स्वीकृत किया गया था।

उन्होंने लाइसेंस की अनुलिपि मुद्रा विनिमय नियंत्रण प्रति के लिए इस आधार पर आवेदन किया है कि मूल लाइसेंस बिल्कुल उपयोग किए बिना ही खो गया है।

अपने तर्कों के समर्थन में उन्होंने एक शपथ पत्र दाखिल किया है। मैं संतुष्ट हूँ कि लाइसेंस की मूल मुद्रा विनिमय नियंत्रण प्रति खो गई है और निवेश देता हूँ कि आवेदक को लाइसेंस की अनुलिपि मुद्रा विनिमय नियंत्रण प्रति जारी की जानी चाहिए। लाइसेंस की मूल मुद्रा विनिमय नियंत्रण प्रति एतद् द्वारा रद्द की जाती है।

[संख्या : जे० 15/एस एस आई/सी जी/ए एम 72/हेव०]

पी० गोविन्द राजू, उप मुख्य नियंत्रक

ORDER

Hyderabad, the 11th April, 1974

S.O. 1621.—M/s. Jewel Gems, No. 5-4-14/2, Nizamshahi Road, Hyderabad were granted an import licence No. P/S/1736671/C/XX/44/W/33-34 dated 31-8-1972 for Rs. 12,000/- for the items (1) Tumbling Machines, (2) Polishing and Lapping Machines, (3) Cutting Slabbing and Slicing Machines for import from General Currency Area.

They have applied for a duplicate copy of the Exchange Control Purposes Copy of the Licence on the ground that the Original Licence has been lost without having been utilised at all.

In support of their contention they have filed an affidavit. I am satisfied that the original Exchange Control Copy of the Licence is lost and direct, that a duplicate Exchange Control Copy of licence should be issued to the applicant. The original Exchange Control Copy of the licence is hereby cancelled.

[File No. J. 15/SSI/C.G./A.M.-72/Hyd.]

P. GOVINDA RAJU, Dy. Chief Controller.

मुख्य नियंत्रक आयात निर्यात का कार्यालय नई दिल्ली

आवेश

नई दिल्ली, 15 जून 1974

का० आ० 1622.—सर्वश्री मोहम्मती उद्योग, नारायणा, राजस्थान को एक आयात लाइसेंस सं० पी/सी जी/2066478 दिनांक 17-12-73 प्रदान किया गया था। उन्होंने उक्त लाइसेंस की मुद्रा विनिमय नियंत्रण प्रति की अनुलिपि जारी करने के लिए इस आधार पर आवेदन किया है कि मूल मुद्रा विनिमय नियंत्रण प्रति खो गई है। यह भी उल्लेख किया गया है कि मूल मुद्रा विनिमय नियंत्रण प्रति किसी भी सीमा शुल्क प्राधिकरण में पंजीकृत कराए बिना और बिल्कुल भी उपयोग किये बिना खो गई है।

इस तर्कों के समर्थन में आवेदक ने नोटरी पब्लिक, राजस्थान के सामने विधिवत शपथ लेकर एक शपथ पत्र दाखिल किया है। तब-नगर मैं संतुष्ट हूँ कि उक्त लाइसेंस की मूल मुद्रा विनिमय नियंत्रण

प्रति खो गई है। इसलिए यथासंशोधित आयात (नियंत्रण) आदेश, 1955 दिनांक 7-12-1955 के उपखंड 9 (सी सी) द्वारा प्रवर्तन अधिकारों का प्रयोग करते हुए सर्वश्री मोडानी उद्योग नारायणा राजस्थान को जारी किए गए लाइसेंस सं० पी/सीजी/2066478 दिनांक 7-12-73 की मूल मुद्रा विनियम नियंत्रण प्रति एतद् द्वारा रद्द की जाती है।

उक्त लाइसेंस की मुद्रा विनियम नियंत्रण प्रति की अनुलिपि प्रति अलग से जारी की जा रही है।

[संख्या : 29(3)/73-74/सी जी-4]

जे० शंकर, उप-मुख्य नियंत्रक

OFFICE OF THE CHIEF CONTROLLER OF
IMPORTS & EXPORTS
ORDER

New Delhi, the 15th June, 1974

S.O. 1622.—M/s. Modani Udyog, Naraina, Rajasthan were granted an Import licence No. P/CG/2066478 dated 17-12-73. They have applied for the issue of a duplicate Exchange Control Purposes copy of the said licence on the grounds that the original Exchange Control Purposes copy has been lost. It is further stated that the original Exchange Purposes copy has been lost without having been registered with any Customs authority and has not been utilised at all.

2. In support of this contention, the applicant has filled an affidavit duly sworn in before Notary Public Rajasthan. I am accordingly satisfied that the original Exchange Control Purposes copy of the said licence has been lost. Therefore, in exercise of the powers conferred under sub-clause 9(cc) of the Import (Control) Order, 1955 dated 7-12-1955 as amended, the said original Exchange Control Purposes copy of licence No. P/CG/2066478 dated 17-12-73 issued to M/s. Modani Udyog, Naraina is hereby cancelled.

3. A duplicate Exchange Control Purposes copy of the said licence is being issued separately.

[No. 29(3)/73-74/CG. IV]

J. SHANKAR, Dy. Chief Controller.

आवेश

नई दिल्ली, 17 जून, 1974

का० आ० 1623.—सर्वश्री इंग्लिश इलेक्ट्रिक आफ इंडिया लि० बल्कन इन्शुरेंस बिल्डिंग 202-बी वीर नारिमन रोड, बम्बई को 67,716 रु० का एक आयात लाइसेंस सं० जी०/आर/2087589/एस/आई ए विनांक 22-4-70 स्वीकृत किया गया था। उन्होंने उक्त लाइसेंस की अनुलिपि सीमाशुल्क कार्य के संबंधी प्रति के लिए इस आधार पर आवेदन किया है कि लाइसेंस की मूल सीमाशुल्क कार्यसंबंधी प्रति फर्म के निकासी अधिकरण कार्यालय, बम्बई में भ्राम में जलकर नष्ट हो गई है और उसका बिल्कुल उपयोग नहीं किया गया था। इस तर्क के समर्थन में आवेदक ने एक शपथ पत्र दायित्व किया है। मैं संतुष्ट हूँ कि लाइसेंस सं० जी/आर/2087589/एस/आई ए/ दिनांक 22-4-70 की मूल सीमाशुल्क कार्य संबंधी प्रति फर्म के निकासी अधिकरण कार्यालय बम्बई में भ्राम में जल कर नष्ट हो गई है और आवेदक को उसी की अनुलिपि सीमाशुल्क कार्यसंबंधी प्रति जारी की जानी चाहिए।

अद्यतन यथासंशोधित आयात (नियंत्रण) आदेश सं० 17/55 दिनांक 7-12-1955 की धारा 9 (सी सी) के अंतर्गत प्रवर्तन अधिकारों का प्रयोग कर अधोहस्ताक्षरी सर्वश्री इंग्लिश इलेक्ट्रिक ऑफ इंडिया लि०,

बम्बई के नाम जारी किए गए आयात लाइसेंस सं० जी/आर/2087589 दिनांक 22-4-70 की सीमाशुल्क कार्य संबंधी प्रति को रद्द करता है।

[संख्या : 17-ई/रेलवे/69-70/जी एल एस]

चन्द्र गुप्त, उप-मुख्य नियंत्रक

ORDER

New Delhi, the 17th June, 1974

S.O. 1623.—M/s. English Electric Co. of India Ltd. Vulcan Insurance Building, 202-B, Veer Nariman Road, Bombay were granted an Import Licence No. G/R/2087589/S/IA dated 22-4-70 for Rs. 67,716/-. They have applied for issue of Duplicate Customs Copy of the same on the ground that the original customs copy of import licence has been destroyed in the fire at the firms clearing Agents office at Bombay and the same was not registered at any Customs House and was not utilised at all. In support of their contention the applicant has filed an affidavit. I am satisfied that the original customs copy of import licence No. G/R/2087589/S/IA dated 22-4-70 has been destroyed in the fire at the firm's clearing agents office at Bombay and duplicate customs copy of the same should be issued to the applicant.

In exercise of the powers conferred on me by clause 9(cc) of the Import (Control) order No. 17/55 dated 7-12-1955 as amended from time to time the undersigned cancels the customs copy of import licence No. G/R/2087589 dated 22-4-74 issued in favour of M/s. English Electric Co. of India Ltd., Bombay.

[No. 17-E/Rly/69-70/GLS/27]

CHANDRA GUPTA, Dy. Chief Controller

औद्योगिक विकास मंत्रालय

आवेश

नई दिल्ली, 15 जून, 1974

का. आ. आई. डी. आर. ए/6/2/74, केंद्रीय सरकार, विकास परिषद् (प्रक्रियात्मक) नियम, 1952 के नियम 3 और 8 के साथ पीठत, उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 6 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, श्री के. एल. गम्भीर के स्थान पर श्री बी. के. राय और श्री एस एन जुन्नारकर को 28 नवम्बर, 1974 तक की, जिसमें यह दिन भी सम्मिलित है, अवधि के लिए अकादमिक रसायन उद्योग विकास परिषद् के सदस्य के रूप में नियुक्त करती हैं और भारत सरकार के औद्योगिक विकास मंत्रालय के आदेश सं. का. आ. 4062/आई. डी. आर. ए/6/7/72, तारीख 29 नवम्बर, 1972 में निम्नीलिखित संशोधन करती हैं, अर्थात् :—

उक्त आदेश के पैरा 1 में,—

(1) क्रम सं. 6 के स्थान पर, निम्नीलिखित क्रम सं. रखी जाएगी, अर्थात् :—

“6. श्री बी. के. राय, नमक आयुक्त,

हाफधर बाक्स सं. 139, जयपुर।”

(2) क्रम सं. 29 के पश्चात्, निम्नीलिखित क्रम सं. अंतः स्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

“30. श्री एस. एन. जुन्नारकर,

49, देसाई काटेज, डा. एम. बी. रावस रोड, शिवाजी पार्क
मुम्बई-400028।”

[सं. 8(5)/74-सी. डी. एन.]

प्रेम नारायण, अवर सींचक

MINISTRY OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT

ORDER

New Delhi, the 15th June, 1974

S.O. 1624.—1 DRA/6/2/74.—In exercise of the powers conferred by Section 6 of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), read with rules 3 and 8 of the Development Councils (Procedural) Rules, 1952, the Central Government hereby appoints Shri B. K. Roy, Vice Shri K. L. Gambhir and Shri S. N. Junnarkar, as members of the Development Council for Inorganic Chemical Industries, for a period upto and inclusive of the 28th November, 1974, and makes the following amendments in the Order of the Government of India in the Ministry of Industrial Development No. S.O. 4062/IDRA/6/7/72 dated the 29th November, 1972, namely:—

In paragraph 1 of the said Order:—

(i) for serial No. 6, the following serial No. shall be substituted, namely:—

"6. Shri B. K. Roy, Salt Commissioner, P. O. B. No. 139, Jaipur".

(ii) after serial No. 29, the following serial No. shall be inserted, namely:—

"30. Shri S. N. Junnarkar, 49, Desai Cottage, Dr. M.B. Raut Road, Shivaji Park, Bombay-400028.

[No. 8(5)/74-CDN]

PREM NARAIN, Under Secy.

औद्योगिक विकास, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय

भारतीय मानक संस्था)

नई दिल्ली, 15 मई, 1974

क्रा० प्रा० 1625—समय समय पर संशोधित भारतीय मानक संस्था (प्रमाणन चिह्न) विनियम 1955 के विनियम 14 के उपविनियम (4) के अनुसार भारतीय मानक संस्था द्वारा अधिसूचित किया जाता है कि लाइसेंस संख्या सी एम एल-3401 जिसके ध्योरे नीचे अनुसूची में दिये गए हैं, फैक्टरी के स्थान बदल देने के कारण 1 अप्रैल 1974 से रद्द कर दिया गया है:

अनुसूची

क्रम संख्या	लाइसेंस संख्या तथा तिथि	लाइसेंसधारी का नाम और पता	रद्द किए गए लाइसेंस के अधीन वस्तु/प्रक्रिया	भारतीय मानक की संख्या तथा पदनाम
1	2	3		
1.	सीएम/एल-3401 30-4-1973	मैक्स चंद्राज केमिकल इन्टरप्राइजेज प्रा० लि०, 13-साउथ टांगरा रोड, कलकत्ता-46 इनका रजि० कार्यालय पी-24 सी० आई० टी० रोड, स्कीम 52, कलकत्ता-14 में है।	जूता उद्योग के लिए रबड़ के बने पक्के चैप पदार्थ; ब्रांड : (1) "डेंड्राइट" (2) "पी सी-65" (3) "पी सी-67"	IS : 4663-1968 जूता उद्योग के लिए रबड़ के बने पक्के चैप पदार्थ की विशिष्टि

[सी एम जी/55:3401 (सीडी)]

ए० पी० बनर्जी उप महानिदेशक

MINISTRY OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT, SCIENCE & TECHNOLOGY

(Indian Standards Institution)

New Delhi, the 15th May, 1974

S. O. 1625—In pursuance of Sub-regulation (4) of regulation 14 of the Indian Standards Institution (Certification Marks Regulations) 1955, as amended from time to time, the Indian Standards Institution hereby notifies that licence No. CM/L-3401, particulars of which are given below has been cancelled with effect from 1 April 1974, due to shifting of the factory.

Sl. No.	Licence No. and date	Name and address of the licensee	Articles/Process covered by the licence cancelled	
1	2	3	4	5
	CM/L-3401 30-4-1973	M/s. Chandras' Chemical Enterprises (Pvt.) Ltd. 13 South Tangra Road, Calcutta-46 having their Regd. office at P-24, C.I.T. Road, Scheme 52, Calcutta-14.	Permanent Rubber based adhesive for footwear Industry. Brand: (i) "DENDRITE" (ii) "PC-65" (iii) "PC-67"	IS: 4663-1968 Specification for Rubber-based Adhesive for footwear Industry.

[No. CMD/55 : 3401 (CD)]

A.P. BANERJI, Deputy Director General.

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय
(पेट्रोलियम विभाग)

नई दिल्ली, 12 जून, 1974

का० प्रा० 1626—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि गुजरात राज्य में एन-के-75 से जी जी एस और सी टी एफ काडी तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिए पाइपलाइन तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा बिछाई जानी चाहिए।

और यतः यह प्रतीत होता है कि ऐसी साधनों को बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्वाक्य अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जित करना आवश्यक है।

अतः, अब, पेट्रोलियम पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना आणव्य एतद्वारा घोषित किया है।

बशर्ते कि उक्त भूमि में हितवन्त कोई व्यक्ति, उस भूमि के नीचे पाइप लाइन बिछाने के लिए आक्षेप समक्ष प्राधिकारी, तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग, निर्माण और देखभाल प्रभाग, मकरपुरा रोड बरोदा-9 को इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा।

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्ट यह भी कथन करेगा कि क्या वह चाहता है कि उसकी मुनवाई व्यक्तिगत हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत।

अनुसूची

डी०एस०एन०के०-75 से जी जी एस और सी टी एफ काडी तक पाइपलाइन बिछाने के लिए

राज्य	गुजरात	जिला :	महसाना	तालुका :	महसाना
ग्राम	सर्वेक्षण संख्या	हेक्टर	ए	आर	ई
			ए <td>आर</td> <td>ई</td>	आर	ई
महमूदपुरा	315	0	11	52	
	कार्ट ट्रैक	0	00	72	
	383	0	31	20	
	406	0	10	62	

[सं० 12016/7/74 एन एण्ड एन III]

MINISTRY OF PETROLEUM AND CHEMICALS

(Department of Petroleum)

New Delhi, the 12th June, 1974

S.O. 1626.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of petroleum from NK-75 to GGS-Cum-CTF Kadi in Gujarat State Pipelines should be laid by the Oil & Natural Gas Commission,

And whereas it appears that for the purpose of laying such Pipelines, it is necessary to acquire the Right of User in the land described in the schedule annexed hereto;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the section 3 of the Petroleum Pipelines (Acquisition of Right of User in land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein

Provided that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification, object to the laying of the pipelines under the land to the Competent Authority, Oil & Natural Gas Commission, Construction & Maintenance Division, Kakarpura Road, Baroda-9.

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by a legal practitioner.

SCHEDULE

For Pipeline from D.S. NK—75 to GGS-cum-CTF Kadi

State : Gujarat Dist : Mehsana Taluka : Mehsana

Village	Survey No.	Hec- tare	Are	P. Arc
Memadpu-RA	315	0	11	52
	Cart track	0	00	72
	383	0	31	20
	406	0	10	62

[No. 12016/7/74-L&L/III]

का० प्रा० 1627—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि गुजरात राज्य में मन्थाल-6 से मन्थाल-4 तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिए पाइपलाइन तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा बिछाई जानी चाहिए।

और यतः यह प्रतीत होता है कि ऐसी साधनों को बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्वाक्य अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जित करना आवश्यक है।

अतः, अब, पेट्रोलियम पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना आणव्य एतद्वारा घोषित किया है।

बशर्ते कि उक्त भूमि में हितवन्त कोई व्यक्ति, उस भूमि के नीचे पाइपलाइन बिछाने के लिए आक्षेप समक्ष प्राधिकारी, तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग, निर्माण और देखभाल प्रभाग, मकरपुरा रोड बरोदा-9 की इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा।

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्ट यह भी कथन करेगा कि क्या वह चाहता है कि उसकी मुनवाई व्यक्तिगत हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत।

अनुसूची

मन्थाल-6 से मन्थाल-4 तक पाइप लाइन बिछाने के लिए

राज्य : गुजरात जिला एवं तालुका : महसाना

ग्राम	सर्वेक्षण सं०	हेक्टर	ए	आर	ई	पी ए आर ई
1	2	3	4	5		
कमालपुर	525	0	06		36	
	518/2	0	03		48	
	518/1	0	03		60	

1	2	3	4	5
	519	0	07	20
	520	0	06	36
	517/1	0	05	04
	516	0	12	00
	515	0	08	28
	514	0	10	80
	फाटें ट्रैक	0	02	04
	544	0	13	44
	547/1	0	04	90
	546	0	09	24
सन्थाल	626	0	13	08
	625	0	11	28
	624	0	03	60
	635	0	06	36

[12018/7/74-एन एण्ड एल]

S.O. 1627.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of petroleum from Santhal-6 to Santhal-4, in Gujarat Pipelines should be laid by the Oil & Natural Gas Commission;

And whereas it appears that for the purpose of laying such Pipelines, it is necessary to acquire the Right of User in the land described in the schedule annexed hereto;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the section 3 of the Petroleum Pipelines (Acquisition of Right of User in land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein :

Provided that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification, object to the laying of the pipelines under the land to the Competent Authority, Oil & Natural Gas Commission, Construction & Maintenance Division, Makarpura Road, Baroda-9.

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by a legal practitioner.

SCHEDULE

For Pipeline from Santhal-6 to Santhal-4.

State : Gujarat Dist & Taluka : Mehsana

Village	Survey No.	Hec- tare	Are	P. Are
1	2	3	4	5
Kasarpura	525	0	06	36
	518/2	0	03	48
	518/1	0	03	60
	519	0	07	20
	520	0	06	36
	517/1	0	05	04
	516	0	12	00
	515	0	08	28
	514	0	10	08
	Cart track	0	02	04
	544			

1	2	3	4	5
	547/1	0	04	80
	546	0	09	24
Santhal	626	0	13	08
	625	0	11	28
	624	0	03	60
	635	0	06	36

[No. 12016/7/74-L&L/II]

का० आ० 1628.—यत. केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि गुजरात राज्य में डी एस डी के धोलका-1 तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिए पाइप लाइन तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा बिछाई जानी चाहिए।

और यतः यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद् पावद्ध अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जित करना आवश्यक है।

अतः, अतः, पेट्रोलियम पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने हुए, केन्द्रीय सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना आशय एतद्वारा घोषित किया है।

बशर्ते कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति, उस भूमि के नीचे पाइप लाइन बिछाने के लिए, आक्षेप समक्ष प्राधिकारी, तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग, निर्माण और देखभाल प्रभाग, मकरपुरा रोड बरोडा-9 को इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा।

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्ट यह भी कथन करेगा कि क्या वह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत।

अनुसूची

डी एस डी के से धोलका-1 तक पाइप लाइन बिछाने के लिए

राज्य : गुजरात	जिला : कैरा	तालुका : मंतर		
ग्राम	सर्वेक्षण संख्या	हेक्टर	ए. आर. ई.	पी. ए. आर. ई.
1	2	3	4	5
राधू	996	0	03	60
	999	0	07	80
	1000	0	08	40
	998	0	11	76
	986 पैकी	0	10	44
	986 पैकी	0	06	60
	985/1 + 2 + 3	0	05	64
	955/2	0	07	64
	955/4	0	07	00
	949	0	11	40
	988/1	0	03	36
	840/1	0	10	08
	885	0	10	80

1	2	3	4	5
	884/2	0	10	80
	883/5	0	26	60
	883/6	0	01	00
	856/5	0	07	92
	856/6	0	02	04
	855/1	0	06	48
	851/1	0	05	16
	851/1	0	03	00

[12016/7/74-एल एण्ड एलI]

S.O. 1628.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of petroleum from DS--DK to Dholka-I in Gujarat State Pipelines should be laid by the Oil & Natural Gas Commission

And whereas it appears that for the purpose of laying such Pipelines, it is necessary to acquire the Right of User in the land described in the schedule annexed hereto;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the section 3 of the Petroleum Pipelines (Acquisition of Right of User in land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein:

Provided that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification, object to the laying of the pipelines under the land to the Competent Authority, Oil & Natural Gas Commission, Construction & Maintenance Division, Makarpura Road, Baroda-9.

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by a legal practitioner.

SCHEDULE				
To Laying pipeline from DS-DK to Dholka-1.				
State : Gujarat District : Kaira Taluka : Matar				
Village	Survey No.	Hec-tare	Are.	P. Are.
1	2	3	4	5
Radhu	996	0	03	60
	999	0	07	80
	1000	0	08	40
	998	0	11	76
	986 Paiki	0	10	44
	986 Paiki	0	06	60
	985/1+2+3	0	05	64
	985/1/2/3			
	955/2	0	07	64
	955/4	0	07	00
	949	0	11	40
	888/1	0	03	36
	840/1	0	10	08
	885	0	10	80
	884/2	0	10	80
	883/5	0	26	60
	883/6	0	01	00
	856/5	0	07	92
	856/6	0	02	04
	855/1	0	06	48
	851/1	0	05	16
	851/4	0	03	00

[No. 12016/7/74-L & L/I]

मुख्यपत्र

क्रा० आ० 1629.—भारत सरकार के राजपत्र, भाग II खण्ड 3, उपखण्ड (II) दिनांक 14 अक्टूबर, 1972 पृष्ठ सं० 4180 से 4192 तक प्रकाशित भारत सरकार के राजपत्र में का०आ०सं० 2804 के अधीन पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय (पेट्रोलियम विभाग) भारत सरकार की अधिसूचना सं० 11(2)/72-लेबर और वेजिस में :

ग्राम : सेज

तालुका : कलोल

जिला : महसाना

यह पड़े				के स्थान पर			
सर्वेक्षण सं०	हैक्टर	ए आर ई	पी ए आर ई	सर्वेक्षण सं०	हैक्टर	ए आर ई	पी ए आर ई
1083/3	0	08	30	1083/3	0	08	80
998/2/ए	0	04	00	998/2/ए	0	02	20
998/2/बी	0	02	48	998/2/बी	0	02	00
998/2/सी	0	06	15	998/2/सी	0	11	40
1083/1/ए	0	03	15	1083/1/ए	0	02	80
1083/1/बी	0	03	00	1083/2/बी	0	02	60
1081/2	0	04	95	1081/2	0	05	80
1085/1/ए	0	01	00	1085/1/ए	0	05	70
कार्टे ट्रैक	0	01	68	कार्टे ट्रैक	0	04	30
1084/1/सी	0	03	42	1084/1/पी	0	00	80
1084/1/बी	0	08	60	1084/1/पी	0	08	60
998/1/बी/पी	0	00	50	998/1/बी/पी	0	00	50

ग्राम : मरीसा				तालुका : कालोल				जिला : महुसाना			
पट्टे				के स्थान पर							
सर्वेक्षण सं०	हेक्टर	ए. आर. ई.	पी. ए. आर. ई.	सर्वेक्षण सं०	हेक्टर	ए. आर. ई.	पी. ए. आर. ई.				
89	0	04	60	89	0	94	60				

ग्राम : धोएन मोती				तालुका : कालोल				जिला : महुसाना			
पट्टे				के स्थान पर							
सर्वेक्षण सं०	हेक्टर	ए. आर. ई.	पी. ए. आर. ई.	सर्वेक्षण सं०	हेक्टर	ए. आर. ई.	पी. ए. आर. ई.				
741/2/बी	0	00	25	741/2/ई	0	00	25				
कार्ट ट्रैक	0	01	20	कार्ट ट्रैक	0	01	00				

ग्राम : करेली				तालुका : कालोल				जिला : महुसाना			
पट्टे				के स्थान पर							
सर्वेक्षण सं०	हेक्टर	ए. आर. ई.	पी. ए. आर. ई.	सर्वेक्षण सं०	हेक्टर	ए. आर. ई.	पी. ए. आर. ई.				
कार्ट ट्रैक	0	01	60	कार्ट ट्रैक	0	01	00				

[सं० 11(2)/72-एन एण्ड एन भाग-1]

बी० आर० बल्ला, अवर सचिव

ERRATUM

S.O. 1629.—In the notification of Government of India in the Ministry of Petroleum & Chemicals (Department of Petroleum) No. 11(2)/72-Lab & Legis, dated 23rd September, 1972, under S. O. No. 2894 in the Gazette of Government of India, Part II Section 3, Sub-section (ii) dated 14th October, 1972, page Nos. 4180 to 4192 :

Village : Saij

Taluka : Kalol

Dist : Mehsana

READ

FOR

Survey No.	Hectare	Arc	P. Arc	Survey No.	Hectare	Arc	P. Arc
1083/3	0	08	30	1083/3	0	06	80
998/2/A	0	04	00	998/2/A	0	02	20
998/2/B	0	02	48	998/2/B	0	02	00
998/2/C	0	06	15	998/2/C	0	11	40
1083/1/A	0	03	15	1083/1/A	0	02	80
1083/1/B	0	03	00	1083/1/B	0	02	60
1081/2	0	04	95	1081/2	0	05	60
1085/1/A	0	01	00	1085/1/A	0	05	70
Cart track	0	01	68	Cart track	0	04	30
1084/1/C	0	03	42	1084/1/P	0	00	60
1084/1/B	0	08	60	1084/1/P	0	08	60
998/1/B/P	0	00	50	998/1/D/P	0	00	50

Village : Serisa				Taluka : Kalol				Dist : Mehsana			
READ				FOR							
Survey No.	Hectare	Are	P. Are	Survey No.	Hectare	Are	P. Are				
89	0	04	60	89	0	94	60				
Village : Bhoyan Moti				Taluka : Kolol				Dist : Mehsana			
READ				FOR							
Survey No.	Hectare	Are	P. Are	Survey No.	Hectare	Are	P. Are				
741/2/B	0	00	25	741/2/E	0	00	25				
Cart track	0	01	20	Cart track	0	01	00				
Village : Karol				Taluka : Kalol				Dist : Mehsana			
READ				FOR							
Survey No.	Hectare	Are	P. Are	Survey No.	Hectare	Are	P. Are				
Cart track	0	01	60	Cart track	0	01	00				

[No. 11(2)/72-L & L. Vol. I]

B.R. BHALLA, Under Secy.

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मंत्रालय

(स्वास्थ्य विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 5 जून, 1974

क्रा० डा० 1630.—यतः भारत सरकार के भूतपूर्व स्वास्थ्य मंत्रालय की 23 जुलाई, 1962 की अधिसूचना सं० 16-44/61-वि० 1 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने निदेश दिया है कि भारतीय चिकित्सा परिषद अधिनियम, 1956 (1956 का 102) के प्रयोजनों के लिए एम्सटरडम विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त चिकित्सा ग्रहता "आर्ट्स एक्जामिन" अर्थात् डिप्लोमा मेडिकल फैकल्टी माय चिकित्सा ग्रहता होगी, और यतः डा० (कुमारी) एच श्रेङ्गेर को जिसके पास उक्त ग्रहता है; शिक्षण तथा धर्मार्थ कार्य के प्रयोजन के लिए फिलहाल जलना मिशन अस्पताल, पूना क्रिश्चियन मेडिकल एसोसिएशन जलना, जिला औरंगाबाद (महाराष्ट्र) के साथ सम्बद्ध है।

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 14 की उपधारा (1) के परन्तुक के भाग (ग) का पालन करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद् द्वारा—

- (1) इस आदेश के सरकारी राजपत्र में प्रकाशित होने की तिथि से दो वर्ष की अवधि के लिए;

अथवा

- (2) उस अवधि को जब तक डा० (कुमारी) एच० श्रेङ्गेर जलना मिशन अस्पताल, पूना क्रिश्चियन मेडिकल एसोसिएशन, जलना, औरंगाबाद (महाराष्ट्र) के साथ सम्बद्ध रहते हैं, जो भी कम हो वह अवधि विनिश्चित करती है, जिसमें पूर्वोक्त डा० मेडिकल प्रैक्टिस कर सकेंगे।

[ए० सं० बी० 11016/3/74-एम पी टी]

कुमारी सती बालकृष्णा, अवसर सचिव

MINISTRY OF HEALTH & FAMILY PLANNING

(Department of Health)

ORDER

New Delhi, the 5th June, 1974

S.O. 1630.—Whereas by the notification of the Government of India in the late Ministry of Health No. 16-44/61-MI, dated the 23rd July, 1962, the Central Government has directed that the Medical qualification "ARTSEXAMEN" (i.e. Diploma Medical Faculty) granted by the University of Amsterdam shall be recognised medical qualification for the purposes of the Indian Medical Council Act, 1956 (102 of 1956);

And whereas Dr. (Miss) H. Kreuger who possesses the said qualification is for the time-being attached to the Jalna Mission Hospital of the Poona Christian Medical Association, Jalna Distt. Aurangabad (Maharashtra State) for the purposes of teaching and charitable work;

Now, therefore, in pursuance of clause (c) of the provision to sub-section (1) of section 14 of the said Act, the Central Government hereby specifies—

- (i) a period of two years with effect from the date of publication of this order in the Official Gazette, or
- (ii) the period during which Dr. (Miss) H. Kreuger is attached to the said Jalna Mission Hospital of the Poona Christian Medical Association, Jalna—Distt. Aurangabad (Maharashtra State) whichever is shorter, as the period to which the medical practice by the aforesaid doctor shall be limited.

[No. V. 11016/3/74-MPT]

MISS SATHI BALAKRISHNA, Under Secy.

रेल मंत्रालय

(रेलवे बोर्ड)

नई दिल्ली, 27 जून, 1974

क्रा० प्रा० 1631.--रेल यात्रियों पर सीमाकर अधिनियम, 1956 (1956 का 69) की धारा 4 द्वारा प्रवृत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एकात्मक निवेश देती है कि इसके साथ संलग्न अनुसूची में उल्लिखित अधिसूचित स्थान से/तक रेलवे द्वारा यात्रा करने वाले किसी यात्री पर ऐसे अधिसूचित स्थान से उनतीस किलोमीटर की परिधि के भीतर स्थित किसी रेलवे स्टेशन तक/से, सीमाकर नहीं लगाया जायेगा।

2. यह अधिसूचना 1 जुलाई, 1974 से प्रवृत्त होगी।

अनुसूची

करबी

[सं० एफ(एक्स) 1-69/टी एक्स-19/2-I]

Ministry of Railways

(Railway Board)

New Delhi, the 27th June, 1974

S.O.1631 In exercise of the powers conferred by Section 4 of the Terminal Tax on Railway Passengers Act, 1956 (69 of 1956), the Central Government hereby directs that no terminal tax shall be levied on any passenger travelling by railway from or to the notified place mentioned in the Schedule annexed hereto, to or from any railway station situated within a radius of twenty-nine kilometres from such notified place.

2. This notification shall have effect on and from the 1st July, 1974.

SCHEDULE

Karwi

[No. F (X)I-69/TX-19/2-II]

क्रा० प्रा० 1632:--रेल यात्रियों पर सीमाकर अधिनियम, 1956 (1956 का 69) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रवृत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड) की 17 जून, 1974 की अधिसूचना संख्या एफ(एक्स) 1-71/टी एक्स-19/I-IV का अधिग्रहण करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा--

- (क) इस अधिसूचना के साथ संलग्न अनुसूची के कालम (2) में उल्लिखित दरें निर्धारित करनी हैं। इन्हीं दरों के अनुसार उक्त अनुसूची के कालम (1) में विनिर्दिष्ट अधिसूचित स्थान तक रेलवे द्वारा ले जाये जाने वाले सभी यात्रियों के प्रत्येक रेलवे टिकट पर सीमाकर लगाया जायेगा; और
- (ख) यह निवेश देती है कि उपर्युक्त सीमाकर 1 जुलाई, 1974 से उद्घाट्य होंगी।
2. यह अधिसूचना 1 जुलाई, 1974 से प्रवृत्त होगी।

अनुसूची

(1)	(2)				
अधिसूचित स्थान का नाम	प्रति एकहूरे टिकट पर सीमाकर की दरें				
	वर्जा	वयस्क		3 से 12 वर्ष तक के बच्चे	
		थोड़ी दूरी के यात्रियों के लिए (30 कि० मी० से 242 कि०मी० तक	लंबी दूरी के यात्रियों के लिए (242 कि० मी० से आगे)	थोड़ी दूरी के यात्रियों के लिए (30 कि० मी० से 242 कि०मी० तक	लंबी दूरी के यात्रियों के लिए (242 कि० मी० से आगे)
		रु० पै०	रु० पै०	रु० पै०	रु० पै०
करबी	वातानुकूल दर्जा	0.50	0.75	0.25	0.40
	पहला वर्जा	0.30	0.45	0.15	0.25
	वातानुकूल कुर्सीयान दर्जा	0.30	0.45	0.15	0.25
	दूसरा दर्जा	0.15	0.20	0.05	0.10

व्याख्या :--बापसी टिकट पर सीमाकर अनुसूची में निर्धारित दर से दुगुना होगा।

[सं० एफ(एक्स) I-69/टी एक्स-19/2-II]

अमृत लाल गुप्ता, सचिव

S.O. 1632.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 3 of the Terminal Tax on Railway Passengers Act, 1956 (69 of 1956) and in supersession of the notification of the Government of India in the Ministry of Railways (Railway Board No. F (X)I-71/19-1-IV, dated the 17th June, 1971, the Central Government hereby—

(a) fixes the rates mentioned in column (2) of the Schedule annexed hereto as the rates at which terminal tax shall be levied in respect of every railway ticket on all passengers carried by railway from or to the notified place specified in column (1) of the said Schedule; and

(b) directs that the aforesaid terminal tax shall be leviable with effect from the 1st July, 1974.

2. This notification shall come into force on the 1st July, 1974.

SCHEDULE

Name of notified place	Rates of terminal tax persingle ticket				
	Class of accommodation	Adults		Children between 3 & 12 years of age	
		For short distance passengers (30 kms to 242 kms)	For long distance passengers (beyond 242 kms.)	For short distance passengers (30 kms—242 kms.	For long distance passengers (beyond 242 kms.)
		Rs. P.	Rs. P.	Rs. P.	Rs. P.
Karwi	Air-conditioned class	0.50	0.75	0.25	0.40
	I Class	0.30	0.45	0.15	0.25
	Air-conditioned Chair Car Class	0.30	0.45	0.15	0.25
	II Class	0.15	0.20	0.05	0.10

Explanation : The terminal tax on a return ticket shall be double the rates fixed herein.

[No. F.(X) I -69/TX-19/2-II]

A.L. GUPTA, Secy.

श्रम मंत्रालय श्रम और रोजगार विभाग आदेश

नई दिल्ली, 8 मई, 1973

क्रा० आ० 1633.—यतः उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट औद्योगिक विवाद केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण, दिल्ली के समक्ष लम्बित है;

और यतः विवाद से संबंधित कर्मकारों ने केन्द्रीय सरकार से निवेदन किया है कि मामला दिल्ली से चण्डीगढ़ को अन्तरित कर दिया जाए;

और यतः केन्द्रीय सरकार इस मांग को युक्तियुक्त समझती है;

अतः, अब औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 7क तथा धारा 33अ की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, एक औद्योगिक अधिकरण गठित करती है जिसके पीठासीन अधिकारी श्री एच० आर० सोधी होंगे, जिनका मुख्यालय चण्डीगढ़ होगा, और केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण, दिल्ली के समक्ष लम्बित उक्त वाद से संबंधित कार्यवाही को प्रतिसंहृत करती है तथा उसे श्री एच० आर० सोधी, पीठासीन अधिकारी के अधीन गठित औद्योगिक अधिकरण को अन्तरित करती है एवं निदेश देती है कि उक्त अधिकरण उक्त कार्यवाहियों से उसी प्रक्रम में कार्यवाही करेगा जिस पर वे उसे अन्तरित की गई है और विधि के अनुसार उसका निपटारा करेगा।

अनुसूची

क्रम संख्या	आदेश संख्या और तारीख	विवाद के पक्षकार
1.	एल० 12012/173/72/आई० आर० iii तारीख 27 अप्रैल, 1973।	सेंट्रल बैंक आफ इण्डिया तथा उसके कर्मकार।

[संख्या एल० 12012/173/72/आई० आर० 3]

करनेम सिंह, अधिवक्ता

MINISTRY OF LABOUR

Department of Labour and Employment

(New Delhi, the 8th May, 1973)

S. O. 1633.—Whereas the industrial dispute specified in the Schedule hereto annexed is pending before the Central Government Industrial Tribunal, Delhi;

And whereas the workmen concerned in the dispute have requested the Central Government for the transfer of the case from Delhi to Chandigarh;

And whereas the Central Government considers the request as reasonable;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 7A and sub-section (1) of section 33 B of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby constitutes an Industrial Tribunal with Shri H.R. Sodhi as the Presiding Officer, with headquarters at Chandigarh, withdraws the proceedings in relation to the said dispute pending before the Central Government Industrial Tribunal Delhi and transfers the same to the Industrial Tribunal constituted with Shri H.R. Sodhi as Presiding Officer thereof and directs that the said Tribunal shall proceed with the said proceedings from the stage at which they are transferred to it dispose of the same according to law.

SCHEDULE

Sl. Order No. and date	Parties to the dispute
1. L. 12012/173/72/IRIII dated the 27th April, 1973.	Central Bank of India and their workmen.

[No. L-12012/173/72/LRIII]

KARNAIL SINGH, Under Secy.

नई दिल्ली, 15 जून, 1974

प्रावेश

नई दिल्ली, 18 जून, 1974

का० प्रा० 1634 पी० डब्ल्यू० ए० खान/नियम/ए० एस०—मजदूरी संधाय (खान) नियम, 1956 में और संशोधन करने के लिए कतिपय नियमों का निम्नलिखित प्रारूप, जो संशोधन केन्द्रीय सरकार मजदूरी संधाय अधिनियम, 1936 (1936 का 4) की धारा 21 के साथ पठित धारा 26 की उपधारा (2) और (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए करना चाहती है, उक्त अधिनियम की धारा 26 की उपधारा (5) की अपेक्षानुसार, ऐसे सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिए एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है, जिसका उनसे प्रभावी होना सम्भावित है, तथा एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि उक्त प्रारूप पर, राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से तीन मास की अवधि के पश्चात्, विचार किया जाएगा।

इस प्रकार विनिर्दिष्ट अवधि के पूर्व जो भी आक्षेप या सुझाव किसी व्यक्ति से उक्त प्रारूप की बाबत प्राप्त होंगे, उन पर केन्द्रीय सरकार विचार करेंगी। ऐसे आक्षेप और सुझाव भारत सरकार के सचिव, श्रम मंत्रालय, श्रम शक्ति भवन, रफी मार्ग, नई दिल्ली-1 को सौंपा जा सकता है।

नियमों का प्रारूप

1. इन नियमों का नाम मजदूरी संधाय (खान) संशोधन नियम, 1974 है।

2. मजदूरी संधाय (खान) नियम, 1956 के नियम 1 के उपनियम (3) में "जम्मू और काश्मीर राज्य के सिन्धाय" शब्दों का नाम किया जाएगा।

[संख्या एस 65012/2/71/प्रग्राई०प्रा०111]

जे० आर० बागची, प्रवर सचिव

New Delhi, the 15th June, 1974

S.O. 1634.—PWA/Mines/Rules/Am.—The following draft of certain rules further to amend the Payment of Wages (Mines) Rules, 1956 which the Central Government proposes to make in exercise of the powers conferred by sub-sections (2) and (3) of section 26, read with section 24, of the Payment of Wages Act, 1936 (4 of 1936), is hereby published, as required by sub-section (5) of section 26 of the said Act for information of all persons likely to be affected thereby, and notice is hereby given that the said draft will be taken into consideration after a period of three months from the date of publication of this notification in the Official Gazette;

Any objections or suggestions which may be received from any persons with respect to the said draft before the period so specified, will be considered by the Central Government. Such objections or suggestions may be addressed to the secretary to the Government of India, Ministry of Labour, Shram Shakti Bhawan, Rafi Marg, New Delhi-1.

DRAFT RULES

1. These rules may be called the Payment of Wages (Mines) Amendment Rules, 1974.
2. In the Payment of Wages (Mines) Rules, 1956, in rule 1, in sub-rule (3) the words "except the State of Jammu and Kashmir" shall be omitted.

[No. S. 65012/2/71/IRIII]

J. R. BAGCHI, Under Secy.

का०प्रा०1635—यतः केन्द्रीय सरकार की राय है कि इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट विषयों के बारे में मैसर्स इब्राहिम मूसा सर्विसेज कम्पनी, मुम्बई के प्रबंधन में सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मचारों के बीच एक औद्योगिक विवाद विद्यमान है।

और यतः केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को न्यायनिर्णयन के लिए निर्दिष्ट करना वाछनीय समझती है;

अतः अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को उक्त अधिनियम की धारा 7क के अधीन गठित केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण संघ 2, मुम्बई को न्यायनिर्णयन के लिए निर्दिष्ट करती है।

अनुसूची

"क्या निम्नलिखित डाक एण्ड जनरल वर्क्स यूनियन, 35, सागर बिहार, 89, पी० डीमेलो रोड, मुम्बई-9 द्वारा मैसर्स इब्राहिम मूसा सर्विसेज कम्पनी के विरुद्ध निम्नलिखित मांग न्यायोचित हैं और यदि हाँ, तो कर्मकार किस अनुतोष के हकदार है:—

पहरेदारों (वाचमैन) को 1969-70 और 1970-71 के लेखे वर्षों में से प्रत्येक के लिए कुल मजदूरी का 20-प्रतिशत बोनस दिया जाना चाहिए?"

[संख्या एस 31011/4/72-पी०एण्ड डी]

वी० संकरालिंगम, अवर सचिव

ORDER

New Delhi, the 18th June, 1974

S.O. 1635.—Whereas the Central Government is of opinion that an industrial dispute exists between the employers in relation to the management of Messrs Ebrahim Moosa Services, Company, Bombay and their workmen in respect of the matters specified in the Scheduled hereto annexed;

And, whereas, the Central Government considers it desirable to refer the said dispute for adjudication;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (d) of sub-section (1) of section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby refers the said dispute for adjudication to the Central Government Industrial Tribunal No. 2, Bombay, constituted under section 7A of the said Act.

SCHEDULE

"Whether the following demand made by the National Dock and General Workers' Union, 35, Sagar Vihar, 89, P. D'Mello Road, Bombay-9, against Messrs Ebrahim Moosa Services Company, 65, P. D'Mello Road, Bombay-9, is justified and if so, to what relief are the workmen entitled:—

The watchmen should be paid bonus at 20 per cent of the total wages for each of the accounting years 1969-70, and 1970-71?"

[No. L-31011/4/72-P&D]

V. SANKARALINGAM, Under Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 18 मई, 1974

का०प्रा० 1636.—यतः केन्द्रीय सरकार की राय है कि इस में उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट विषयों के बारे में मैसर्स जी० सामोन्ता, अबरक खान मालिक, डाकघर कोडरमा, जिला हजारीबाग के प्रबन्ध से सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच एक औद्योगिक विवाद विद्यमान है;

और यतः केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करना वांछनीय समझती है;

अतः, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, उक्त विवाद को उक्त अधिनियम की धारा 7-क के अधीन गठित केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण (सं० 2) धनबाद का न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करती है।

अनुसूची

क्या मैसर्स जी० सामोन्ता, अबरक खान मालिक, डाकघर कोडरमा, जिला हजारीबाग द्वारा नियोजित श्रमिकों की, वर्ष 1971 में आरम्भ होने वाले लेखा वर्ष के लिए उनके द्वारा अर्जित मजदूरियों के 20 प्रतिशत की दर से बोनस के भुगतान की मांग न्यायोचित है? यदि नहीं, तो कर्मकार-उस वर्ष के लिए बोनस की किस राशि के हकदार हैं?

[सं० एल०-28011/6/73-एल० प्रार०-4]

ORDER

New Delhi, the 18th May, 1974

S.O. 1636.—Whereas the Central Government is of opinion that an industrial dispute exists between the employers in relation to the management of Messrs G. Samonta, Mica Mine Owners, Post Office Koderma, District Hazaribagh, and their workmen in respect of the matters specified in the Schedule hereto annexed;

And where the Central Government considers it desirable to refer the said dispute for adjudication;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (d) of sub-section (1) of section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby refers the said dispute for adjudication to the Central Government Industrial Tribunal (No. 2), Dhanbad constituted under section 7A of the said Act.

SCHEDULE

Whether the demand of the workmen employed by Messrs G. Samonta, Mica Mine Owners, Post Office Koderma, District Hazaribagh for payment of bonus at the rate of 20 per cent of the wages earned by them for the accounting year commencing in the year 1971 is justified. If not, to what quantum of bonus are the workmen entitled for that year?

[No. L-28011/6/73-LRIV]

आदेश

27 मई, 1974

का०प्रा० 1637.—यतः केन्द्रीय सरकार की राय है कि इसमें उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट विषयों के बारे में पातपाड़ा मैड स्टोन माइन, डाकघर दाबी, जिला बुन्दी के प्रबन्ध से सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच एक औद्योगिक विवाद विद्यमान है;

और यतः केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करना वांछनीय है;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त विवाद को उक्त अधिनियम की धारा 7-क के अधीन गठित केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण, जबलपुर को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करती है।

अनुसूची

क्या श्री कमल हसन, मुरज पोल, कोटा (राजस्थान) की पातपाड़ा मैड स्टोन माइन, डाकघर दाबी (जिला बुन्दी) में नियोजित कर्मकार किन्हीं राष्ट्रीय और उत्सव-प्रवकाश-दिनों की मंजूरी के संबंध में हकदार हैं?

[सं० एल०-29011(21)/74-एल० प्रार०-4]

ORDFR

New Delhi, the 27th May, 1974

S.O. 1637.—Whereas the Central Government is of opinion that an industrial dispute exists between the employers in relation to the management of Patpada Sand Stone Mine, Post Dabi, District Bundi and their workmen in respect of the matters specified in the Schedule hereto annexed;

And where the Central Government considers it desirable to refer the said dispute for adjudication;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (d) of sub-section (1) of section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby refers the said dispute for adjudication to the Industrial Tribunal, Jabalpur constituted under section 7A of the said Act.

SCHEDULE

Whether the workmen employed in the Patpada Sand Stone Mine Post Dabi (District Bundi) of Shri Kamrul Hassan, Surajpole, Kota (Rajasthan) are entitled for grant of any paid national and festival holidays?

[No. L-29011(21)/74-LR. IV]

आदेश

का०प्रा० 1638.—यतः केन्द्रीय सरकार की राय है कि इसमें उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट विषयों के बारे में बुधपुरा मैड स्टोन माइन डाकघर बुधपुरा, जिला बुन्दी (राजस्थान) के प्रबन्ध से सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच एक औद्योगिक विवाद विद्यमान है;

और यतः केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करना वांछनीय समझती है;

अतः, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को उक्त अधिनियम की धारा 7-क के अधीन गठित केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण, जबलपुर को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करती है।

अनुसूची

क्या श्री बाबुलाल जी यादव की बुधपुरा मैड स्टोन माइन, डाकघर बुधपुरा, जिला बुन्दी (राजस्थान) में नियोजित कर्मकार की 1965-66, 1966-67, 1967-68, 1968-69, 1969-70, 1970-71 लेखा वर्षों की मजदूरियों की 20% की दर से बोनस मंदाय की मांग न्यायोचित है? यदि नहीं, तो कर्मकार इन वर्षों में से प्रत्येक वर्ष के लिए बोनस की किस राशि के हकदार हैं?

[संख्या एल०-29011(10)/74-एल० प्रार०-4]

पी० पी० कानून, अबर सचिव

ORDER

S.O. 1638.—Whereas the Central Government is of opinion that an industrial dispute exists between the employers in relation to the management of Budhpura Sand Stone Mine, Post Office Budhpura, District Bundi (Rajasthan) and their workmen in respect of the matters specified in the Schedule here annexed;

And where the Central Government considers it desirable to refer the said dispute for adjudication;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (d) of sub-section (1) of section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby refers the said dispute for adjudication to the Central Govt. Industrial Tribunal, Jabalpur constituted under section 7A of the said Act.

SCHEDULE

Whether the demand of the workmen employed in Budhpura Sand Stone Mine of Shri Babulaji Yadav, Post Office Budhpura, District Bundi (Rajasthan) for payment of bonus @ 20 per cent of wages for the Accounting years 1965-66, 1966-67, 1967-68, 1968-69, 1969-70, 1970-71 is justified? If not to what quantum of Bonus are the workmen entitled for each of these years?

[No. L-29011(10)/74-LR. IV]

P. P. KANTHAN, Under Secy.

New Delhi, the 15th June, 1974

S.O. 1639.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the following award of the Central Government Industrial Tribunal, Delhi in the industrial dispute between the employers in relation to the Bank of Baroda and their workmen, which was received by the Central Government on the 11th June, 1974.

BEFORE THE CENTRAL GOVT. INDUSTRIAL TRIBUNAL : DELHI

REFERENCE I.D. Nos. 5 & 6 of 1973

BETWEEN

The employers in relation to the Bank of Baroda, Parliament Street, New Delhi,

AND

Their workmen.

Dr. Anand Parkash with Sh. Madho Kapur—for the management.

Shri M. K. Ramamurthi with Shri Romesh Pathak—for the workmen.

AWARD

As common questions of facts and law arise in both these references and both the workmen were employees of a single employer, they are being disposed of by a single award.

2. By Order No. L. 12012/170/72/LR/III dated 6th March 1973 the Central Government referred the following industrial dispute existing between the aforesaid parties for adjudication to the Tribunal presided over by my learned predecessor Shri R. K. Baweja :—

“Whether the action of the management of Bank of Baroda in terminating service of Shri Dharmanand watchman-cum-peon was justified? If not, to what relief is the workman entitled?”

2. The same Government by another Order No. L. 12012/169/72/LR/III dated 13th March, 1973 referred another industrial dispute existing between the said employer and Shri Kedar Lal, workman for adjudication to the Tribunal presided over by my learned predecessor Shri R. K. Baweja with the following term of reference :—

“Whether the action of the management of Bank of Baroda in terminating the services of Shri Kedar Lal, watchman-cum-peon was justified? If not, to what relief is he entitled?”

4. The former reference pertains to the justification or otherwise of the order of termination of services of Shri Dharmanand, watchman-cum-peon. In I.D. No. 6 of 1973, the matter which was referred for adjudication is if the management was justified in terminating the services of another watchman-cum-peon Shri Kedar Lal. In the written statement filed by the management, the preliminary objections raised were that as no demand was made on the management, there was no industrial dispute which could be validly referred for adjudication and that there was no proper espousal of the dispute. On these pleadings of the parties, the following three preliminary issues were framed in both these references :—

- (1) Whether a demand was made on the management in respect of the subject-matter of the dispute? If not, its effect?
- (2) Whether the dispute is not an industrial dispute?
- (3) Whether there was espousal of the dispute? If not, its effect?

All these issues were decided by my learned predecessor Shri R. K. Baweja vide his order dated the 7th of September 1973 and the cases were fixed for evidence on merits. Both these references proceeded before me as successor to Shri R. K. Baweja.

5. The allegations of the workmen as contained in the statement of claims filed by the Secretary of the Bank of Baroda Employees Union on their behalf are that Sarvashri Dharmanand and Kedar Lal were employed against permanent vacancies in the Bank in July and June 1970 respectively as watchmen-cum-peons-cum-liftmen but were not paid their salaries at the rates prescribed in the Bipartite settlement and awards which governed the service conditions of the employees working in the banking industry. According to the union, the management had been adopting unfair labour practice in the matter of employment. They approached the management to confirm them in service and also to pay them their dues as per the Bipartite settlement and the service conditions applicable to all other workmen working in the Bank but instead of accepting their justified and reasonable demand, they were told by the Security-cum-Administrative Officer of the Bank that the management had decided to terminate their services with effect from the 31st of July, 1972 and that they should sign a receipt in token of their having received money in full and final settlement of their dues. When they wanted to know the reasons, they were told that their services were no longer required by the management as they had allegedly put in their claim for being treated as permanent employees of the Bank. It was, therefore, prayed that as the action of the management in discharging them from service was in utter violation of the directions contained in the Bipartite settlement and awards in force at the relevant time, besides being illegal and unjustified, the management be directed to reinstate them in service with full back wages and continuity of service.

6. In the written statements filed by the management the pleas of the workmen as contained in the statement of claims were controverted and it was stated that as they were engaged on purely casual and temporary basis in connection with the construction of Parliament Street Building of the Bank their services came to an end automatically on the completion of the said construction work. According to the management, they were not entitled to salaries and other benefits admissible to the permanent employees of the Bank who were issued regular appointment letters. It is further stated that when the workmen came to know that their services were going to be terminated as temporary employees, they as an after-thought, started putting in claims for being treated as regular employees of the Bank. After

the completion of the main construction work, the concerned workmen and others were given certain casual jobs. It is also averred that, though under the law no retrenchment compensation was required to be paid to them, the management tendered one month's salary and compensation by way of precautionary measure but they refused to accept the same. It was, therefore, prayed that their claim be rejected as no case had been made out for any relief far less the relief of reinstatement or full back wages or continuity of service.

7. The first point that falls for determination is whether the two concerned workmen were employed on construction work or whether they were part of the regular staff of the Bank and were working against permanent vacancies. Now I shall proceed to consider on the basis of the oral and documentary evidence placed on record as to which version is correct.

8. In support of its case, the management produced two witnesses and relied on certain documents which are on the files. Shri Ishwar Dass Dogra MW1 is the Security-cum-Administrative Officer of the Bank at Karol Bagh, New Delhi. He deposed that the construction work of the Bank Building in Parliament Street started in 1965. One Kothari was the Architect who engaged 28 persons including the two concerned workmen. The wages to those workmen were paid on the basis of the certificate given by the Architect and they were engaged on different jobs from time to time as per the need. To workers like masons, carpenters, electricians, chowkidars and peons etc., no appointment letters were issued as they were not regular employees. According to Shri Dogra even for a temporary bank employee, the management issued a letter of appointment. The construction workers were not given any leave excepting the weekly paid holidays. The bank employees were governed by different awards and the Bipartite settlement while the casual workers were not governed by those settlements and awards. He further stated that when the main construction work of the building had been completed in June/July, 1972 their services were dispensed with alongwith twelve other construction workers. Before the start of the construction work, no casual or temporary employee was ever employed. Shri Dogra produced the attendance registers of temporary and regular employees who were recruited during the relevant time. In these registers names of the concerned workmen do not find a place. Shri Dogra, then, called the two concerned workmen alongwith others on the 31st of July, 1972 and offered them one month's salary, one month's notice pay and other compensation. Excepting the two concerned workmen, all others received their dues and went away. Thereupon, Shri Dogra gave a note on the chits Exts. W/10 and W/11 to the effect that the two workmen had not accepted their dues. The dues were later sent by money orders. Copies of the receipts which Shri Dogra obtained from the other employees were Exts. M/12 to M/21. Exts. M/22 to M/43 are copies of the appointment letters issued to the temporary employees of the bank who were appointed during the relevant period. He went on to say that the salaries of casual employees were debited to C.D.Misc. Property Revenue Account and they were paid at the rate of Rs. 200/- per month whether the month was of 28 days, 30 days or 31 days. On the 31st of July, 1972 this witness told them that their services were no longer required as the main construction work of the building had been completed. Shri Dogra denied that their services were terminated as they had made representations regarding terms and conditions of their service. The staff of the Bank shifted to the new building in April, 1971 as the major portion of the work had been completed. From the cross-examination of this witness it was not shown that what he had stated in his examination-in-chief was wrong.

9. The next witness produced by the Bank in support of its case is Shri R. Raghuraman MW2. In 1970-71, he was in the Regional Office of the Bank at New Delhi, and was looking-after the work connected with the construction of the building in Parliament Street. He said prior to the construction of the building, no casual employees were employed. The two concerned workmen were working on the construction site and were given different jobs like watch and ward of the building material and sometimes they also did the lift-operating work but it was not their regular duty. Certain casual staff was retained after 1971 when the main construction work had been completed. In cross-examination he stated that their service record was maintained by the

construction site office. The casual workers were employed by the site engineer on the recommendations of the Architect and were paid by the Bank. The statement of this witness remained unshaken in cross-examination.

10. The evidence on the side of the workmen consists of three witnesses. The first of them Shri Kedar Lal WW1 deposed that he worked as lift-operator-cum-peon for about eleven months. There was a permanent lift operator during that period with him, twelve other workers were there at the Bank site. He looked after the building material and furniture. The office of the Architect and the bank engineer was there and when he joined, the first floor had been constructed. The site engineer used to certify the number of days for which he worked in a month. The second witness is Shri Dharma Nand WW2. His statement is similar to that of Shri Kedar Lal. In cross-examination, he explained that before joining the management, he worked in the postal department on daily wages as porter. He was assigned the work of chowkidar-cum-peon when he started working at the building site. He was a watchman for the office and building manager and worked by rotation during day and night. On Sundays and holidays he worked on lift and on other days he worked as peon. The others are permanent as they are getting their full wages and uniforms. He denied that any retrenchment compensation was paid to him. The third witness Shri R. L. Virmani WW3 is the secretary of the union. He deposed that the construction of the building started in 1965 and he used to go there in 1971-72. He saw the two concerned workmen working there. For different work different chowkidars were there.

11. From the above evidence it is quite obvious that the management treated the concerned workmen as Casual employees. The fact that the workmen were employed on construction work and were doing work in its connection is more or less admitted by the workmen themselves. Shri Kedar Lal contacted the Bank Engineer for appointment and with him twelve other workers were at the site of the bank building, who looked after the building material. This shows that they were employed in connection with the construction work. Shri Dharmanand has also admitted that he was assigned the work of looking-after the building material. Even the secretary of the union has stated that he saw the two workmen working on the site of construction of the building. It is also clear from the evidence of the management's witnesses that their names were not mentioned in the attendance registers or regular employees and they were not given other facilities admissible to regular employees of the Bank. This shows that they were not being treated as bank employees. The fact that the concerned workmen were not paid wages under the Bipartite settlement, is not disputed even by the union. It also goes to show that these workmen were not treated as regular employees of the bank. Then there were no letters of appointment in respect of them, though, it is the case of the bank that it issued such letters in respect of even temporary employees. Shri Dharma Nand stated that he was a chowkidar-cum-peon when he started working at the site. On Sundays and holidays, he worked on the lift. Exts. M/46 to M/50 are the statements of salary paid to such workers. All these documents show that they were paid at the site by the site engineer on the recommendations of the Architect. Exts. M/1 to M/9 are the attendance registers of permanent employees and they were produced at the instance of the Union. In these registers the names of the construction workers do not find a place. There is no evidence that the workmen were employed on permanent basis or against permanent vacancies. On the contrary the workmen made representations that they should be made permanent. But they never stated that they were employed on permanent basis against permanent vacancy. Dr. Anand Parkash took me through the entire evidence of the workmen and pointed out that in their evidence there was no assertion that they were employed against jobs of permanent nature. Thus, the workers have failed to establish that they were employed against permanent vacancies or on permanent basis. Shri Kedar Nath was operating the lift on Sundays and holidays. Now if a construction worker is asked to operate lift on Sundays and holidays, it cannot be said that he was working against a permanent post, or in connection with the affairs of the bank. It is in evidence of the management that posts of liftmen were in existence and had not been abolished. It is also in the evidence of the workmen that on Sunday and holidays they were asked to work on lift though on other days they were looking-after the construction work. This

merely would, however, not mean nor make them permanent workmen in view of the dictum of the Hon'ble Supreme Court of India in *Rohtas Industries Vs. its workmen* (1956 II. LLJ. 444) cited by Dr. Anand Prakash appearing for the management. It was held, therein, that even if after the completion of the temporary work, the temporary worker worked for sometime in production department then it did not make him permanent. In the present case also, both the workers were employed on construction work which work was of a temporary character. It would be wholly inequitable, too, in the very nature of their employment to force the employer to continue to employ them beyond the completion of the work for which they were engaged (1970, Lab. I. C. 907). The allegation of the management that they were paid on daily basis does not, however, carry any conviction with me. MW1 Shri Ishwar Dass Dogra admitted in cross-examination that they were paid at the rate of Rs. 200/- per month irrespective of the fact whether a month was of 28 days, 30 days or 31 days.

12. Hence, I reach a conclusion that the concerned workmen were employed at the site of the construction work of the building of the bank and when that work came to an end, their services could be retrenched as they were no longer required in connection with the construction of the said building.

13. In view of my finding above that the concerned workmen were employed in connection with the construction work of the building of the bank, it remains no more of any consequence whether they were temporary workmen or casual workmen. As held in 1971. I. LLJ. 241 even a casual worker is a worker within the meaning of the word, 'workman' as defined in Section 2(s) of the Industrial Disputes Act. It was further held that although casual workmen are expressly excluded from the benefits of lay-off compensation yet they are not excluded from the benefit of retrenchment compensation if they fulfil certain conditions prescribed in Section 25F of the Act. The same view was taken by the Madras High Court in 1970 II. LLJ. 454 (*Elomalai v. Management of Simplex Concrete Piles (India) Ltd. Madras* and another) whether it was held that the definition of worker in Section 2(s) is in the widest possible terms and includes a casual worker. In view of this I hold that even if these workers are taken to be casual workers it does not make any difference.

14. It is, also, of no importance whether the case falls under Section 25F or 25FFF(2) of the Industrial Disputes Act, as in either case compensation payable to the workmen is the same, except that in case of 25F, the payment of compensation is a condition precedent to retrenchment which it is not under section 25FFF(2). Sub-section (2) of Section 25-FFF of the Act reads as follows:—

"Where any undertaking set-up for the construction of building, bridges, roads, canals, dams or other construction work is closed down on account of the completion of the work within two years from the date on which the undertaking had been set-up, no workman employed therein shall be entitled to any compensation under clause (b) of Section 25-F, but if the construction work is not so completed within two years, he shall be entitled to notice and compensation under that section for every completed year of continuous service or any part thereof in excess of six months."

In the present case, the construction work was not completed within two years. It is, therefore, clear from a perusal of the above sub-para that in case of an undertaking set-up for construction of building a workman will be entitled to compensation if the work does not complete within two years from the date on which the undertaking had been set-up. As already stated above, in this case the construction work was started in 1965 and it continued till 1973; therefore, the workman was entitled to compensation under Section 25-F. The difference, however, between Section 25-F and Section 25-FFF is that the conditions specified in Section 25F are conditions precedent to retrenchment so that if retrenchment is effected without complying with the said conditions the retrenchment is void whereas Section 25FFF does not provide for any condition precedent. An employer can close down his business without prior payment of compensation as held

36 G. of I. /74—6.

by the Supreme Court in the case of *Hathising Manufacturing Co. Ltd. v. Union of India* (1960. II. LLJ. 1). Applying Section 25F with its condition precedent, I find that Shri Dharmanand workman was offered Rs. 200/- as wages for July 1972 and a further sum of Rs. 400/- as compensation. He refused to accept the said sums on the 31st of July 1972. These amounts were then sent by pay-order and he accepted the same under protest. Similarly, in the case of Shri Kedarlal Rs. 200/- and Rs. 400/- were offered on the 31st of July 1972 but he too refused to accept the same. Thus, there was no violation of the condition laid down in Section 25F. Moreover, it was not the case of the workmen that their termination of service was in violation of the provisions of Section 25F of the Act. In this connection my attention was drawn to the case of *Gyanchand Vs. Rawal Pindi Victory Transport Co. Ltd.* (1970. 37. FJR. 451). It is a case in which the facts are on all fours the same as in this case. It has been held therein that, "a tribunal would be acting beyond its jurisdiction in giving a decision on a matter which has not been raised in the pleadings." In their demand notices Exts. W/1 and W/2, too, the workmen did not take the stand that the termination of their services was in violation of the provisions of Section 25F of the Act. The result is that so far as Section 25F is concerned, the workmen are not entitled to any relief under it.

15. Similarly, under Section 25FFF, too, they are not entitled to any relief as ultimately under it, section 25F was to be pressed into service and it has been already held that there was no violation of it.

16. Shri Ramamurthi submitted that the services of the workmen were terminated on malafide intentions and untenable grounds. Dr. Anand Parkash on the other hand urged that in that sense the malafide intentions and untenable grounds meant that if the workmen were able to prove that the construction work had not been over or that there had been victimisation it would be untenable grounds and malafide intention. I have already held above that the concerned workmen were employed against a specific work and the same had been completed. So, there is no question of malafides on the part of the management inasmuch as when the main construction work against which they were engaged came to an end, their services could be retrenched.

17. The last question is whether the action of the bank in terminating the services of Sarvashri Dharmanand and Kedarlal was justified.

18. On consideration, I am of the opinion that the management was quite justified in their action of retrenching the concerned workmen. They were employed in connection with the construction work of the Parliament Street building of the bank and it having been completed, it was well within the management discretion of the bank to organise and arrange its work and to retrench the dead weight of uneconomic surplus.

19. There was no violation of any law, either, in this retrenchment. Due compensation was offered and even paid which the workmen accepted. Hence, in view of this, the workmen are not entitled to any relief in these proceedings; and the award is made accordingly.

D. D. GUPTA, Presiding Officer

4th June, 1974.

[No. L. 12012/170/72/IRIII]

New Delhi, the 17th June, 1974

S.O. 1640.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the following award of the Central Government Industrial Tribunal, Jabalpur in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Messrs. Jaipur Udyog Limited, Sawaimadhopur and their workmen, which was received by the Central Government on the 10th June, 1974.

CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL-
CUM-LABOUR COURT, JABALPUR (CAMP AT
ALLAHABAD)

Case No. CGIT/LC (R) (24)/73

(Notification No. L-29011(55)/72-LR. IV) dated 24th November, 1973.

PARTIES :

Employers in relation to the management of Messrs. Jaipur Udyog Limited, Sawaimadhopur P.O. Phalodi Quarry, district Sawaimadhopur and their workmen.

APPEARANCES :

For the workmen—1. Sri P. K. Sharma, 2. Sri B. L. Gautam.

For the management—Sri C. N. Sharma, Advocate.

Industry : Lime Stone Quarries District : Sawaimadhopur
(Rajasthan).

AWARD

This is a reference under section 10(1)(d) of the Industrial Disputes Act, 1947, hereinafter called 'the Act'. The question referred for the adjudication of this Tribunal is:—

"Whether the management of Messrs. Jaipur Udyog Limited Sawaimadhopur have implemented the recommendations of the Central Wage Board for Cement Industry in regard to piece-rated stone cutters employed in their Phalodhi Bharonpura Bajarakho and Laxmipura Lime Stone Quarries? If not, to what relief are these workmen entitled?"

In short, the contention of the workmen of Messrs Jaipur Udyog Limited Sawaimadhopur hereinafter called the management, is that the management did not give the piece-rated stone cutters employed by it any annual increments which were due to them in the year 1961 and onwards.

Preliminary objections have been raised on behalf of the management. Firstly, that the dispute, by a mutual agreement dated 22-12-1971, was referred to the arbitration of Sri Mohan Lal Ji Sukhadia, presently the Governor of Karnatka, and the reference before this Tribunal is illegal. The representative of the management could not give any information to the Tribunal as to the progress made in the aforesaid arbitration proceeding before Sri Mohanlal Ji Sukhadia. Merely because the dispute was referred to the said Arbitrator as far back as 22-12-1971 and in absence of anything on the record to indicate as to the stage of the proceedings before the Arbitrator, I am not prepared to hold that the reference before this Tribunal suffers from any legal infirmity. Evidently, there was a dispute between the parties and it came before the Assistant Labour Commissioner (Central), Kota for conciliation. Eventually, the conciliation proceedings ended in failure, and the dispute has been referred to this Tribunal. I hold that the reference before me is in accordance with the law.

Secondly, it was contended on behalf of the management that the workmen have claimed increments from 1961 onwards and on the face of its their claim is very belated. There appears to be substance in this contention. If the workmen were entitled to increments from 1961 onwards they should have put forward their claim within a reasonable time soon after when the management denied them the increments for the first time. Evidently, the workmen did not pursue their claim for a long time and on the fact of it their claim now made before this Tribunal is stale and belated. The management relied on the decision of the Supreme Court in *Inder Singh & Sons. Ltd., and their workmen (1961)(II)LLJ-P.89*. The Supreme Court observed:—

"It is true that laws of limitation which might be any Civil Court from giving remedy in respect of law-

ful rights are not and should not be applied by the Industrial Tribunals. On the other hand it is well-accepted principle of Industrial adjudication that over state claims should not generally be encouraged or allowed, unless there is a satisfactory explanation for the delay."

In the circumstances of the present case I would have been reluctant to grant to workmen any relief as claimed by them in view of the very belated nature of their claim.

On the merits it appears that there is not much substance in the claim for annual increments as put forward by the workmen. Reliance was placed on their behalf on the recommendations of the 1st Central Wage Board for Cement Industry which came into effect on 1st January, 1960. The Wage Board classified the piece-rated workmen as unskilled workmen. On page 74 para 13.11.1. the Board said:—

"In the case of piece-rated operatives, the basic wages mentioned above should be the basic wage payable on the Standard Minimum workload."

It was contended on behalf of the workmen that in accordance with the aforesaid recommendations, the management fixed the piece-rated stone cutters in "E" grade of operatives and fixed the minimum workload on existing rates i.e. @ 50 paise per tonne on monthly basis at 104 tonnes. While implementing the recommendations the management deliberately ignored the recommendations regarding the annual increments to such piece rated workers and related the output with annual increments against the recommendations. In other words, the management did not treat the annual increments given to such piece-rated stone-cutters an additional basic wage and increased the workload every year with the annual increment. It was submitted on behalf of the workmen that by the abovementioned practice the management fixed the minimum workload on existing rates i.e. @50 paise per tonne on monthly basis at 104 tonnes to such piece-rated stone cutters.

The recommendations of the Second Central Wage Board came into operation with effect from 13-2-1968. The only modification in the recommendations of the 1st Central Wage Board that the Second Central Wage Board made was that it provided for Rs. 61.60 p.m. or Rs. 2.35 per day as the basic wage for an unskilled workman. It said:—

"We, therefore, stipulate that the new piece rate should be arrived at by dividing this basic wage by the existing workload. Except for this, the other recommendations of the First Cement Wage Board in respect to piece-rate shall remain unaffected. The new fall back wage, as per our recommendations, shall be Rs. 61.60 p.m. if the workload is fixed on monthly basis and Rs. 2.35 per day if workload is on a daily basis. The other conditions mentioned in para 13.13.4 of the First Wage Board in regard to fall back wage shall continue to hold good."

On the basis of the aforesaid modification in the First Wage Board recommendations, it was contended on behalf of the workmen that due to the increase in fall back wage from Rs. 52 p.m. to Rs. 61.60 p.m. on existing minimum workload the new rate comes to Rs. 59.23 paise per tonne instead of 50 paise per tonne and all the payments had to be made accordingly after 13-2-1968, but the management did not implement these recommendations and calculated and paid wages @ 50 paise per tonne. It was thus contended that:—

"In substance, the company did not give any annual grade increment to piece-rated stone-cutters which fell due to them in the year 1961 and onwards. The payment is also being made @ 50 paise per tonne instead of 59.23 p. per tonne w.e.f. 13-2-1968."

Admittedly, the workmen who are claiming the annual increments, are about 325 in number. They are only a section of unskilled piece-rated stone cutters. It was contended on behalf of the management and not denied by the representative of the workmen that stone is drilled and blasted by other workmen and the duty of the workmen in question before me is only to load the pieces of stone. It was con-

tended on behalf of the management that it has to incur separate expenses for drilling and blasting the stone rocks and the workmen in question have only to collect them. It was strenuously argued on behalf of the management that the fixation of the wage at Rs. 52 by the First Wage Board had no relevance to the workload and it was wholly wrong on the part of the workmen to say that an average of Rs. 104 per tonne should be made the basis of calculation. Reference was made to the report of the National Productivity Council with regard to excavation in which it was said that the average excavation should be 13 tonnes per day (vide page 129 para 19.2.8.). The management referred to the settlement between it and the workmen dated 15-4-1955 which, according to it, was a comprehensive settlement in respect of the various demands pertaining to the workmen of Phalodi Quarry. The question of wages of stone cutters was mutually settled. The relevant terms of the aforesaid settlement are :—

"(1) For white hard stone (high) at the rate of annas eight per tonne plus two annas and six pies for compressor charges. Company would recover from the workers for the drilling charges at the rate of five annas and six pies per running foot for 1-1/4" to 2" size holes. After working for the period of a month if it would be found that 1 ft. hole yields less than 2-1/4" tonnes of stone the recoverable rate for drilling charges would be reduced to five annas per running foot. In case we go in for the bigger size boring experiment would be made and rates for charging the recoverable amount would be adjusted proportionately. Quantity of explosives considered reasonable by the Company would be supplied free of cost.

"(ii) For red stone workers would be paid at the rates of annas ten per tonne. No boring is to be done by the Company. Quantity of explosives considered reasonable by the Company would be supplied free of cost."

The management contended that from the aforesaid terms it would appear that the rate of 8 annas per tonne was inclusive of all allowances and payments were actually made for a long time on that basis and according to it out of payment of 8 annas per tonne, the company could recover from the workmen drilling charges at the rate of five annas and six pies per running foot for 1-1/4" to 2" size holes. This amount was to be adjusted from the rate of 8 annas per tonne of excavated limestone. According to the management the workload immediately preceding the operation of the First Wage Board for the Cement Industry was 6.02 tonnes per man per day calculated on the basis of the average for the year 1959. According to it, the payment at the rate of Rs. 2 per day had to be made to the workmen on the basis of 6.02 tonnes production which would work out to 33 paise per tonne out of which drilling charges had further to be recovered in terms of the settlement dated 15-4-1955. It was emphatically denied that the management had fixed the minimum workload on existing rates i.e. at the rate of 50 paise per tonne on a monthly basis at 104 tonnes. It was emphasized that the existing workload was 6.02 tonnes per man per day and as such the minimum monthly workload worked out to 156.52 tonnes and not 104 tonnes as alleged on behalf of the workmen. The management has stated that it has not given less to the workmen concerned than what was recommended by Wage Board irrespective of their production and that additional payments at the rate of 8 annas per tonne were to be given to the workmen who produced more than 6.02 tonnes per day which was the existing workload on 1-1-1960. It was further emphasised that the management had refrained from recovering the drilling charges which had been incurred by it from the workmen and had acted with a view to give overall benefits to workmen to which they were entitled under the settlement of 1955 or under the Wage Board recommendations. According to the management, at no time its piece-rated operatives were paid less than what the unskilled operatives were paid. It was emphasised that the settled rate was 50 paise per tonne under the said settlement and it was not or could not be 59.23 paise as was claimed on behalf of the workmen. An affidavit was produced on behalf of the management along with certain enclosures. Annexure '2' of the affidavit shows the average per man per day production of limestone in 1959 in Phalodi Quarry of the

management. From the aforesaid statement, the average production per tonne per man comes to Rs. 156.52. It would thus appear that the entire controversy between the parties is with regard to the quantum of the workload and whether it would be Rs. 104 tonnes as claimed by the workmen or the minimum monthly workload would work out to Rs. 156.52 as alleged by the management. The Recommendations of the First Wage Board only said :—

"The proper method to do this will be to divide the new basic wage of Rs. 52 per month if the workload is fixed on monthly basic or Rs. 2 per day on daily basis by the existing workload in order to arrive at the new piece-rate, dearness allowance and house rent allowance to be paid as recommended for unskilled operatives in para 13.7.1."

It did not mention the quantum of the workload. There is no evidence in support of the contention on behalf of the workmen that the management "had fixed the minimum workload on existing rates i.e. @ 50 paise per tonne on monthly basis at 104 tonnes". On the other hand, the management had produced sufficient evidence to show that the quantum of the workload per day was 6.02 tonnes. There is no force in the contention of the workmen that the management had wrongfully increased the workload every year and had thus neutralised the annual increments. The workmen have been getting their due annual increments, and it could not be said that such annual increments had been neutralised by the output of the workmen.

My answer to the question referred to this Tribunal is in the affirmative. I hold that the management has implemented the recommendations of the Central Wage Board for Cement Industry in regard to piece-rated stone cutters employed in their Phalodi, Bharonpura Bajakho and Laxmipura Lime Stone Quarries and as such the workmen are not entitled to any relief as claimed by them. I make my award accordingly. Parties will bear their own costs.

S. N. KATJU, Presiding Officer.

Dated 24-4-1974.

[No. L-29011/55/72-LR. IV]

S.O. 1641.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the following award of the Central Government Industrial Tribunal-Cum-Labour-Court, Jabalpur in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Shri Chand Khan, Mine Owner, Budhpura Sand Stone Mine, Post Office, Budhpura District Bundi and their workmen, which was received by the Central Government on the 7th June, 1974.

CAMP AT PACHMARHI

CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL- CUM-LABOUR COURT JABALPUR (M.P.)

PRESENT :

Mr. Justice S. N. Katju, Presiding Officer.

Case No. CGIT/LC(R)(6) of 1974

(Notification No. L-29011/5/74-LRIV Dated 25-2-1974)

PARTIES :

Employers in relation to the management of Shri Chand Khan, Mine Owner Budhpura Sand Stone Mine, P.O. Budhpura, Distt. Bundi and their workmen represented through the Pathar Khan Mazdoor Sangh (Independent), Kota (Rajasthan).

APPEARANCES :

For employer—None.

For workmen—Shri Mahabir Prasad Sharma.

Industry : Sand Stone Mine District : Bundi (Rajasthan)

AWARD

This is a reference under Section 10(1)(d) of the Industrial Disputes Act, 1947.

The question referred to this Tribunal for its adjudication is :—

“Whether the workmen employed in the Budhpura Sand Stone Mine of Shri Chand Khan, Post Office Budhpura, Distt. Bundi (Rajasthan) are entitled for grant of any paid national and festival holidays ? If so, for how many days ?”

The workmen of the Budhpura Sand Stone Mine of Shri Chand Khan, Post Office Budhpura, district Bundi have claimed that they are entitled to the grant of the following Festival and National holidays as paid holidays :—

1. 26th January (Republic Day)	... 1 day.
2. Holi (Dhulendi)	... 1 day.
3. 1st May (Labour Day)	... 1 day.
4. Raksha Bandhan	... 1 day.
5. Krishna Janmastmi	... 1 day.
6. 15th August (Independence Day)	... 1 day.
7. Dipawali	... 1 day.
8. 2nd October (Gandhi Jayanti)	... 1 day.
9. Dushabha	... 1 day.
10. Id or Local Festival	... 1 day.

The dispute with regard to the said claim of the workmen was sponsored on behalf of the workmen by the Pathar Khan Mazdoor Sangh (Independent) Kota. The President of Pathar Khan Mazdoor Sangh, Shri Mahabir Prasad Sharma, at first sent a letter to the management with regard to the claim on 2-11-1973 (Ex. W/1) the acknowledgment receipt of which is Ex. W/2. But the management did not send any reply to the said letter. Thereafter the Mazdoor Sangh raised the present dispute before the Assistant Labour Commissioner (Central) Kota by its letter dated 24-11-1973 (Ex. W/3). The management's representative did not appear before the Assistant Labour Commissioner (Central) Kota and the conciliation proceedings before him ended in failure.

No one appeared on behalf of the management on the various dates fixed for the hearing of the reference. The acknowledgement receipts of the notices to the management were not received back by this Tribunal. The hearing of the case had to be adjourned on 10-4-1974, 26-4-1974, 8-5-1974 and 9-5-1974 because on the aforesaid dates neither any representative of the management appeared before me nor the acknowledgement of the service of notices issued were received back.

On 9-5-1974 I passed the following order :—

“Acknowledgement of the service on the management has not been received so far.

Put up for filing of written statement-cum-rejoinders of the parties, and for final hearing on 22-5-1974 at Pachmarhi (New Rest House).”

It is difficult to understand as to why repeated notices sent to the management have not been served on it. I am not prepared to postpone the hearing of this reference any further. The management had been duly informed of this reference by the Central Government and it should by itself have filed its written statement within 10 days of the receipt of the order of reference by the Central Government.

Shri Mahabir Prasad Sharma, the President of the Pathar Khan Mazdoor Sangh (Independent) Kota, gave evidence on behalf of the workmen. He has stated that the workmen

in the neighbouring mines are given the aforesaid Festival and National holidays as paid holidays. In a number of references, which have come to me from districts Bundi and Sawaimadhopur, the same question as is involved in the present reference came for consideration before me. I expressed the view that the workmen are entitled to the aforesaid holidays as paid holidays. These holidays are national holidays and are observed as such throughout the country. There is no reason why these holidays should be denied to the workmen employed in the Budhpura Sand Stone of Shri Chand Khan, Post Office Budhpura, District Bundi. The mere fact that the workmen are given one day's off in a week under the Mines Act is no ground for withholding the aforesaid National and Festival holidays from them. I am clearly of the view that the workmen of the Budhpura Sand Stone Mine of Shri Chand Khan are entitled to the grant of the aforesaid National and Festival holidays as paid holidays from 2-11-1973 and I make my award accordingly. The workmen will have Rs. 100/- as costs.

Dated 22-5-1974.

S. N. KATJU, Presiding Officer.

[No. L-29011(5)/74-I.R. IV]

S.O. 1642.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the following award of the Central Government Industrial Tribunal, Jabalpur in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Messrs Tiwari Jhumarlal Swarooplal, Mine Owner, Karauli and their workmen, which was received by the Central Government on the 11th June, 1974.

**CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL—
CUM-LABOUR COURT AT JABALPUR (CAMP AT
ALLAHABAD)**

Present :

Mr. Justice S. N. Katju, Presiding Officer.

Case No. CGIT/LC(R)(23)/1973.

(Notification No. L-29012/29/73-LR-IV dated September 24, 1973).

Parties :

Employers in relation to the management of Messrs Tiwari Jhumarlal Swarooplal, Mine Owners, Post Office-Karauli District Sawaimadhopur and their workman.

APPEARANCES :

For the workman—Shri M. P. Sharma.

For the management—Sri B. L. Sharma.

Industry: Lime Stone District : Sawaimadhopur (Raj.)

AWARD

This is a reference under section 10(1)(d) of the Industrial Disputes Act, hereinafter called 'the Act'. The dispute before me refers to the termination of service of Shiv Shanker Sharma. He was employed as a Munshi in the Mining Office, Karauli, of M/s. Tiwari Jhumarlal Swarooplal, Mine Owners, Post Office Karauli, district Sawaimadhopur, hereinafter called 'the management'.

The dispute of the workman was sponsored by the Pathar Khan Mazdoor Sangh, hereinafter called the Mazdoor Sangh,

which is a registered Trade Union, of which the workman, Shiv Shanker Sharma, is a member. It was contended on behalf of the workman that he was employed as a Munshi by the management since the last 30 years, and was getting Rs. 275/- at the time of the termination of his service on 31-10-1972. It was further contended that no notice with regard to termination of service of the workman was given to him and his services were abruptly terminated by a registered letter sent by the management to him dated 30-10-1972 which said that his services were terminated with effect from 31-10-1972. The Mazdoor Sangh first wrote directly to the management on behalf of the workman by its letter dated 14-5-1973 to which the management did not give any reply. Then the dispute was raised before the Assistant Labour Commissioner (Central) Ajmer. It appears that on the dates fixed for discussions before the Regional Labour Commissioner (Central) Ajmer, the management did not send any representative and only sought adjournments. Eventually, the proceedings before the Regional Labour Commissioner ended in failure. Thereafter, the dispute was referred to this Tribunal.

Before this Tribunal also, the management did not put in appearance on a number of dates fixed in the case and did not file its written statement. The representative of the management appeared before me on 4-4-1974 at Jaipur. With considerable reluctance I gave him another opportunity to file the management's written statement on 5-4-1974.

An application was made on behalf of the management for being permitted to be represented by an Advocate. This was opposed by the workman and the application was rejected. Another application was made on the same date viz. 5-4-1974 on behalf of the management for adjournment of the hearing which was rejected by me.

The workman Shiv Shanker Sharma was examined and cross-examined before me. He stated that he was working in the mines of the management since the last 30 years as a Munshi and his services had been terminated by the management by a letter (Ex.W/1), which was received by him on 30-10-1972 and which said that his services were terminated from 31-10-1972. He admitted that he had received his salary for the period upto 31-10-1972. He further stated that he did not receive any notice nor any chargesheet was given to him by the management. He stated that he had sent a notice to the management through his Advocate dated 4-11-1972 (Ex.W/6), which was not accepted by the management. He further stated that he did not know reasons for the termination of his service and has prayed that he should be reinstated on his post and get his back wages from the management.

In his cross-examination, Shiv Shanker Sharma said that he was employed in the mines of the management in 1944 or 1945 on a salary of Rs. 15/- per month. Thereafter, the salary was increased periodically and he was getting Rs. 275/- per month since about two years before the termination of his service. He denied that he had a personal business or owned a Truck. He further stated:—

"I have no mining business of my own. My sons do mining business. This mining business is of my two sons, who are grown up and have their own children. My two sons are separate with me. There is no truck even in the name of my sons. It is wrong to say that my services were terminated because I had started my separate business. In my reply given through an Advocate dated 3-11-1972 I had not asked for reinstatement of my service."

In the course of arguments on behalf of the management, it was contended that Shiv Shanker Sharma had started a rival business in the name of his sons, and he was negligent in the performance of his duties and had lost the confidence of the management. As mentioned above, Shiv Shanker Sharma denied that he had a separate business of his own. He, however, admitted that his two sons, who according to him are separate from him, are engaged in mining business.

The management also carries on mining business and admittedly the two sons of the workman are engaged in a business similar to that of the management. In these circumstances, it would not be surprising that the management would lose confidence in Shiv Shanker Sharma.

In *Binny Limited v. Their Workmen and another* (A.I.R. 1972 S.C. 1975), the Supreme Court observed:—

"It has become almost a settled principle that reinstatement should not be awarded where the management justifiably alleges that they have ceased to have confidence in the dismissed employee. In other cases, the Tribunal must consider carefully the circumstances of the case to come to a finding that justice and fair play require that reinstatement should be awarded."

In *M/s Francis Klein & Co. Private Ltd. v. The Workmen and another* (A.I.R. 1971 S.C. 2414), it was observed that:—

".....if once the Company has lost confidence in its employee it is idle to ask them to employ such a person in another job."

In *Binny Ltd. v. Their Workmen* (A.I.R. 1973 S.C. 1403), the Supreme Court observed:—

"It was quite clear that on his own admission he had acted in a manner by which the Management could possibly have no confidence in him for the future. His reinstatement as well as the payment of Rs. 5,000/- as back wages therefore, could not have been ordered according to the well settled law and principles on the point."

While it was denied by the workman that he was carrying on a mining business of his own, he has admitted that his sons are carrying on such business. Even though the workman has said that his sons have their separate business and it was argued on his behalf that he had no concern with the business of his sons, I am not prepared to go to the extent of believing that the workman himself was entirely disinterested in the business of his sons. Where a person is employed in a business concern and his sons start separate business of their own on similar lines, there will, particularly in the circumstances of the case before me, be a valid reason for the management for losing confidence in the employee concerned. I am, therefore, not prepared to direct the reinstatement of the workman in the service of the management.

The management, however, has acted in an arbitrary manner in dispensing with the services of Shiv Shanker Sharma without giving him any notice or asking for any explanation from him. As mentioned above, it also avoided appearing before the Regional Labour Commissioner as also before me prior to 4-4-1974 when I took up the case at Jaipur. Evidently, the management has scant respect for legal formalities. Even if it had a valid ground for dispensing with the services of Shiv Shanker Sharma, it should have not done so in an arbitrary manner without giving him any notice or an opportunity to explain his position. Shiv Shanker Sharma did not ask for his reinstatement when he sent his letter to the management dated 3-11-1972 through his Advocate. As mentioned above, I am not prepared to direct the reinstatement of Shiv Shanker Sharma in the service of the management. He is, however, entitled to compensation from the management, particularly in view of the rash and arbitrary manner in which his services were terminated by the management. He is entitled to get Rs. 1,000/- as compensation from the management together with Rs. 200/- as costs, in all Rs. 1200/-.

I hold that the action of the management in terminating the services of Shiv Shanker Sharma, Munshi, Mining Office, Karauli with effect from 31st October, 1972 was arbitrary and not in accordance with the law and he is entitled to get Rs. 1,000/- as compensation and in addition Rs. 200/- as costs from the management.

I make my award accordingly.

Dated 23-4-1974

S. N. KATJU, Presiding Officer.

[No. L-29012/29/73-I.R. IV].

S.O. 1643.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the following award of the Central Government Industrial Tribunal, Jabalpur, in the industrial dispute, between the employer in relation to Shri Kanhaji Dhakad, Mine Owner, Budhpura Sand Stone Mine, Post Office Budhpura, District Bundi and his workmen, which was received by the Central Government on the 7th June, 1974.

**CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL—
CUM-LABOUR COURT, JABALPUR (M.P.)
CAMP AT PACHMARHI**

Case No. CGIT/LC(R) (7) of 1974.

(Notification No. L-29011(4)/74-LRIV Dated 2-3-1974).

Parties :

Employers in relation to Shri Kanhaji Dhakad, Mine Owner, Budhpura Sand Stone Mine, Post Office Budhpura, District Bundi (Rajasthan) and their workmen represented through the Pathar Khan Mazdoor Sangh, Kota (Rajasthan).

Appearances :

For employer	None
For workmen	Shri Mahabir Prasad Sharma.

District : Bundi (Rajasthan) **Industry :** Stone Mine.

AWARD

This is a reference under section 10(1)(d) of the Industrial Disputes Act, 1947.

The question raised in the reference is whether the workmen employed in the Budhpura Sand Stone Mine of Shri Kanhaji Dhakad, Post Office, Budhpura, District Bundi (Rajasthan) are entitled to the grant of the following National and Festival holidays as paid holidays as claimed by them.

1. 26th January (Republic Day)	... 1 day.
2. Holi (Dhulendi)	... 1 day.
3. 1st May (Labour Day)	... 1 day.
4. Ruksha Bandhan	... 1 day.
5. Krishna Janmastmi	... 1 day.
6. 15th August (Independence Day)	... 1 day.
7. Dipawali	... 1 day.
8. 2nd October (Gandhi Jayanti)	... 1 day.
9. Dushehra	... 1 day.
10. Id or Local Festival	... 1 day.

The dispute as regards the said claim of the workmen was sponsored on behalf of the workmen by the Pathar Khan Mazdoor Sangh (Independent) Kota.

The President of the Pathar Khan Mazdoor Sangh, Shri Mahabir Prasad Sharma, at first sent a letter to the management with regard to the workmen's claim on 31-10-1973 (Ex. W/1) but the management did not send any reply to the said letter. Thereafter the Mazdoor Sangh raised the present dispute before the Assistant Labour Commissioner (Central) Kota by its letter dated 21-11-1973 (Ex. W/2). The management's representative did not appear before the Assistant Labour Commissioner (Central) Kota and the conciliation proceedings before him ended in failure.

No one appeared on behalf of the management on the various dates fixed for the hearing of the reference. The service of the notices sent to the management were not received back by this Tribunal. On 18-3-1974 I fixed 10-4-74

for filing of written statements by the parties. On 10-4-1974 Shri Mahabir Prasad Sharma appeared on behalf of the workmen, but no one appeared on behalf of the management. Since the notice had not been served on the management I fixed 26-4-1974 for filing of written statement by the management and for written statement-cum-rejoinders by the parties. No one appeared on behalf of the parties on 26-4-1974 and acknowledgment of service of the notice on the management was also not received by that date. Again on 7-5-1974 the acknowledgment of service on the management had not been received. I directed the reference to be put up for filing of "written statement by the management, rejoinders of the parties and final hearing on 21-5-1974 at Pachmarhi". Again no one appeared on behalf of the management, nor the acknowledgment of service of notice on the management has been received by the Tribunal. It is difficult to understand as to why repeated notices sent to the management have not been served on it. I am not prepared to adjourn the hearing of the case any further. The management had been duly informed of this reference by the Central Government and it should by itself have filed its written statement within 10 days of the receipt of the order of reference by the Central Government.

Shri Mahabir Prasad Sharma, the President of the Pathar Khan Mazdoor Sangh (Independent) Kota, gave evidence on behalf of the workmen. He has stated that the workmen in the neighbouring mines are given the aforesaid Festival and National holidays as paid holidays. In a number of references, which have come to me from districts Bundi & Sawaimadhopur, the same question as is involved in the present reference came for consideration before me. I expressed the view that the workmen are entitled to the aforesaid holidays as paid holidays. These holidays are national holidays and are observed as such throughout the country. There is no reason why these holidays should be denied to the workmen of the Budhpura Sand Stone Mine. The mere fact that the workmen are given one day's off in a week under the Mines Act is no ground for withholding the aforesaid National & Festival holidays from them. I am clearly of the view that the workmen of Budhpura Sand Stone Mine of Shri Kanhaji Dhakad, Mine Owner, Post Office Budhpura, District Bundi, are entitled for the grant of the aforesaid National & Festival holidays as paid holidays from 31-10-1973 and I make my award accordingly. The workmen will have Rs. 100/- as costs.

S. N. KATJU, Presiding Officer

Dated 21-5-1974

[No. L-29011/4/74-LR. IV]

P. P. KANTHAN, Under Secy.

नई दिल्ली 22 जून, 1974.

का. आ. 1644.—खान अधिनियम, 1952, (1952 का 35) की धारा 5 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा श्री ए. बी. सिंह को मुख्य खान निरीक्षक के अधीन खान निरीक्षक के रूप में नियुक्त करती है।

[सं. ए-35017/7/71-एम-1]

टी. एस. कृष्णामूर्ति, अवर सचिव

New Delhi, the 22nd June, 1974

S.O. 1944.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 5 of the Mines Act, 1952 (35 of 1952), the Central Government hereby appoints Shri A.B. Singh as Inspector of Mines subordinate to the Chief Inspector of Mines.

[No. A. 35017/7/71-MI]

T. S. KRISHNAMURTHI, Under Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 18 मई, 1974

का० प्रा० 1645—यतः केन्द्रीय सरकार की राय है कि इससे उपावद्ध, अनुसूची में विनिर्दिष्ट विषयों के बारे में बुरहार और अम्लाई कोलियरीज, डाकघर धानपुरी, जिला शहडोल (मध्य प्रदेश) के प्रबन्ध से सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मचारियों के बीच एक औद्योगिक विवाद विद्यमान है;

और यतः केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करना वांछनीय समझती है;

अतः, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को उक्त अधिनियम की धारा 7-क के अधीन गठित औद्योगिक अधिकरण, जबलपुर को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करती है।

अनुसूची

क्या बुरहार सं० 1 और 2 अम्लाई कोलियरीज, धानपुरी, शहडोल (मध्य प्रदेश) के पहिले मालिक—मैसर्स रेवा कोलफील्ड्स लिमिटेड, कलकत्ता का, लेखा वर्ष 1972 के कुल लाभों से दी जाने योग्य उपदान की स्वीकृत राशि को घटा देना न्यायोचित है और यदि नहीं, तो कर्मकार किस अनुतोष के हकदार हैं?

क्या बुरहार सं० 1 और 2 और अम्लाई कोलियरीज, धानपुरी, शहडोल (मध्य प्रदेश) के पहिले और इस समय के मासिक मैसर्स रेवा कोलफील्ड्स लिमिटेड, और मैसर्स कोल माइन्स प्रायिवेट लिमिटेड का बोनस संदाय अधिनियम, 1965 के उपबन्धों का उल्लंघन करते हुए, लेखा वर्ष 1972 के लिए अपने कर्मचारियों को बोनस का भुगतान न करना न्यायोचित है। यदि नहीं, तो वे किस लाभ के हकदार हैं?

[सं० एल०-22011/12/73-एल०प्रा०-2]

पी० भार० नैयर, उप-सचिव

ORDER

New Delhi, the 18th May, 1974

S.O. 1645.—Whereas the Central Government is of opinion that an industrial dispute exists between the employers in relation to the management of Burhar and Amlai Collieries, Post Office Dhanpuri District Shahdol Madhya Pradesh and their workmen in respect of the matters specified in the Schedule hereto annexed

And whereas the Central Government considers it desirable to refer the said dispute for adjudication;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (d) of sub-section (1) of section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby refers the said dispute for adjudication to the Industrial Tribunal, Jabalpur, constituted under section 7A of the said Act.

SCHEDULE

Whether Messrs Rewa Coalfields Limited, Calcutta, erstwhile owners of Burhar No. 1 and 2 and Amlai Collieries, Dhanpuri, Shahdol (Madhya Pradesh) are justified in deducting inflated amount of gratuity payable from the gross profits of the accounting year 1972 and if not, to what relief are the workmen entitled?

Whether Messrs Rewa Coalfields Limited and Messrs Coal Mines Authority Limited, the erstwhile and present owners of Burhar No. 1 and 2 and Amlai Collieries Dhanpuri, Shahdol (Madhya Pradesh) are justified in not making payment of bonus to their workmen for the accounting year 1972 in contravention of the provisions of payment of Bonus Act, 1965. If not, to what benefit are they entitled?

[No. L-22011/12/73-I.RIL.]

New Delhi, the 22nd June, 1974

S.O. 1646.—In pursuance of the section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the following award of the Arbitrator in the industrial dispute between employers in relation to the management of Honnahalli Iron Ore Mines of Shri Inniah Reddy and their workman Shri R. Lakshmi Reddy which was received by the Central Government on the 12th June, 1974.

BEFORE SHRI M. R. RAJU, REGIONAL LABOUR COMMISSIONER (CENTRAL) HYDRABAD—ARBITRATOR

In the matter of on an industrial dispute under section 10A of the Industrial Disputes Act, 1947.

No. B1/105 (6)/74

BETWEEN

Shri A. Laxmi Reddy, Workman.....Claimant

AND

Shri A. R. Murthy Power of Attorney to Shri S. Inniah Reddy, Mine Owner.....Respondent

PRESENT

Shri M. R. Raju, Regional Labour Commissioner (Central), Hyderabad.—ARBITRATOR.

APPEARANCES :

For workman — 1. Shri A. C. J. Dasen Solomonn
Authorised representative.

2. Shri R. Laxmi Reddy—Workman.

For Employer — 1. Shri A. R. Murthy, Power of Attorney to Shri S. Inniah Reddy, Mine Owner.

AWARD

The present reference arises out of order No. L-260-13/1/74-LR-IV dated 10th April, 1974 passed by the Central Government in respect of an industrial dispute between the parties mentioned above. Subject matter of the dispute has been specified in the schedule to the said order, and the said schedule runs as follows :—

"Whether the management of Honnahalli Iron Ore Mines is justified in terminating the services of Shri R. Lakshmi Reddy, Maistry? If not, to what relief Shri R. Lakshmi Reddy is entitled to?"

2. This order was received by me on 18-4-74 and notices were sent to the parties for submission of their written statements. In his written statement it is contended by the workman that he was employed as a Maistry in the above Iron Ore Mine from 18-11-72 and his services were terminated on 25-11-73. He also contended that the services of a temporary workman cannot be terminated as punishment for misconduct without establishing it at a proper domestic enquiry held for the purpose and he further demanded that he should be reinstated with all back wages and continuity of service. In reply to the statement of the workman, the respondent stated that Shri Laxmi Reddy had been

working as casual maistry and his services were dispensed with after 10 months of service. He was again reappointed as a fresh employee on 6-9-69 as a casual worker and he was put on probation and his services were terminated with effect from 24-11-73. As he has hardly put in 2 months service he is not entitled to invoke the provisions of the Industrial Disputes Act.

3. The matter was posted for hearing on 5-6-74 in the office of the Asstt. Labour Commissioner (Central) Bellary. During the course of discussions the parties requested time to have mutual discussions. The request was acceded to. After completion of their discussions, the parties filed a memo of compromise according to which the workman will be paid Rs. 400/- in full and final settlement of his claims against the management and he will have no claim against the management for employment. I have gone through the terms of settlement contained in the said petition. They are fair and reasonable and, therefore, I make an award on the basis of the terms of settlement. The joint petition of compromise shall part of the award.

4. Let a copy of this award be forwarded to the Central Government under Section 15 of the Industrial Disputes Act, 1947.

M. R. RAJU, Regional Labour Commissioner.

BEFORE THE ARBITRATOR REGIONAL LABOUR
COMMISSIONER (CENTRAL), HYDERABAD CAMP
AT BELLARY ON 5-6-1974

BETWEEN

Shri A. R. Murthy.....Claimant

AND

Shri R. Lakshmi Reddy.....Respondent

JOINT MEMO FILED ON BEHALF OF PARTIES

The parties have compromised the matter and the claimant has agreed to receive Rs. 400/- (Rupees Four Hundred only) in full and final settlement of all claims against

the respondent. The claimant has no claims on employment. The amount will be paid in the presence of the Assistant Labour Commissioner (Central) Bellary with in 15 days from the date of this memo on a date fixed by the Assistant Labour Commissioner (Central) Bellary.

It is prayed that award may be passed in terms of this Joint Memo.

Signature of the parties.

Representing the Management

A. R. MURTHY, Power of Attorney to Shri S. Inniah
Reddy Mine Owner.
Camp : Bellary
Dated : 5-6-74

Representing the Employee.

A. C. J. DASEN SOLOMON, Authorised Representative.
R. LAKSHMI REDDY, Workman Claimant.

[No. L-26013(1)/74-LR.IV]

P. R. NAYAR, Under Secy.

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue and Insurance)

CORRIGENDUM

New Delhi, the 29th June, 1974

CUSTOMS

S.O. 1647.—In the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue and Insurance) No. S.O. 1391 (77-Customs) dated 19th May, 1973, published at page 1818 of the Gazette of India, Part II Section 3 Sub-section (ii), dated 19th May, 1973 for "7th May, 1969" read "7th May, 1960".

[No. 55-Customs/F. No. 14/8/70-LCII]

D. SARUP, Under Secy.

